सत्यमेव जयते

असंशोधित

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

03 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 03 मार्च, 2021 ई0

द्वितीय सत्र — 12 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नकाल होगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मामला है । अभी कोरोना-काल है, 4 मार्च से मेडिकल इंट्रेंस की परीक्षा हो रही है ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : आप अपने स्तर से, आसन से सरकार को निर्देश दिया जाय कि इस कोरोना-काल में हर जिले में परीक्षा हो, इसको सरकार सुनिश्चित करे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूँ । महोदय, सत्र चल रहा है और सभी विभागों को यह निर्देश है कि चलते सदन में जिसमें माननीय विधायक अपेक्षित हों, कार्यक्रम नहीं करना है । मुझे कल संध्या 6 बजे दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त का वाट्सऐप द्वारा सूचना दिया गया कि आज 12 बजे कचरा प्रस्संकरण केन्द्र का उद्घाटन होगा । मैं वाट्सऐप पर उनको बोला भी कि सत्र चल रहा है ।

यह तो सरासर विधायी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो विधायी कार्य में बाधा होगा और यह सरासर विशेषाधिकार का मामला है, अध्यक्ष महोदय । विशेषाधिकार हनन का नोटिस उनपर दिया जाय....

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष : बैठ जायं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सबलोग खड़े हैं, विशेषाधिकार के लिए जो नियम हैं कि माननीय सदस्य को खड़ा होना है, वे खड़े हैं । क्योंकि यह विधायी कार्य में सरासर....

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, चलते सत्र में कोई भी विभाग का बैठक जहाँ विधायक मेम्बर हैं, वहाँ नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये सब लोग । बैठ जाइये सुदामा जी । यह सभी माननीय विधायक से जुड़ा हुआ मामला है । (व्यवधान) सुन लीजिए पहले । सभी विधायक का मामला है । महबूब जी, बैठ जाइये ।

संजय सरावगी जी, आपकी सूचना को सरकार ने ग्रहण किया है और इस तरह के मामले में, सभी माननीय सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है, कोई पदाधिकारी अनदेखी करेंगे तो वे विशेषाधिकार के क्षेत्र में आयेंगे और उनपर कार्रवाई होगी ।

सरकार संज्ञान लेकर एक पत्र भी इस तरह का जारी करे कि कोई भी पदाधिकारी माननीय सदस्य के साथ चलते सत्र में इस तरह के कार्य नहीं करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आसन के निर्देश का पालन सरकार करे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, आसन का निर्देश हुआ तो इसपर टिप्पणी क्या करना चाहते हैं ललित बाबू ? पुराने सदस्य हैं । आसन का निर्देश सर्वोपरि है ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न । माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र । माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग।

(व्यवधान)

अब इनका क्वेश्चन शुरू है । सही समय पर उठाइयेगा, अभी बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर भाकपा(माले) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

सही समय पर उठाइयेगा । अभी बैठ जाइये । पोस्टर को हटा दीजिए । मार्शल पोस्टर को हटायें ।

(व्यवधान)

अब स्थान ग्रहण कर लीजिए । आ गया ध्यान में, अब बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर वेल से माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गए)

## प्रश्नोत्तर काल

### अल्पसूचित प्रश्न सं0 23 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187 मनेर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत 11 आई0टी0आई0 भवनों के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है :-

1. दानापुर, पटना जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-2235 दिनांक-18.09.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में फरवरी, 2021 में श्रम संसाधन विभाग द्वारा नौबतपुर में स्थल उपलब्ध करायी गई है, जिसमें मिट्टी जॉच की प्रक्रिया की जा रही है ।

2. सुपौल जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निर्मली के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-2448 दिनांक-29.11.2019 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में दिनांक-14.06.2020 को स्थल प्राप्त होने के पश्चात् विषयांकित निर्माण कार्य प्रथम बार निविदा रद्द होने के कारण पुनर्निविदा की गई है ।

3. बेगुसराय जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मझौल के निर्माण हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-3282 दिनांक-26.11.2019 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में दिनांक-14.06.2020 को स्थल प्राप्त होने के पश्चात् उक्त निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है ।

4. बेतिया जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बगहा के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-4174 दिनांक-04.11.2016 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में दूसरी जगह स्थल उपलब्ध होने के कारण निविदा प्रक्रियाधीन है ।

5. वैशाली जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-857 दिनांक-30.03.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में स्थल विवादित रहने के कारण अबतक सीमांकन नहीं हुआ, जिसके कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

6. गोपालगंज जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-2383 दिनांक-26.11.2019 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में प्रथम बार निविदा रद्द होने के कारण पुनर्निविदा की गई है ।

7. बेगुसराय जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माण, तेघरा के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-1702 दिनांक-23.07.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में दिनांक-03.03.2020 को स्थल प्राप्त होने के पश्चात् उक्त निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति में है ।

8. औरंगाबाद जिलान्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-856 दिनांक-30.03.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में निविदा निष्पादित है, परन्तु स्थल विवादित रहने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है, औपबंधिक कार्यादेश निर्गत है परन्तु स्थल पर ग्रामीणों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है । (स्थल विवादित है)

9. औरंगाबाद जिलान्तर्गत पुरूष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-1048 दिनांक-08.05.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में निविदा निष्पादित है । स्थल विवादित रहने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, औपबंधिक कार्यादेश निर्गत है परन्तु स्थल पर ग्रामीणों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है । (स्थल विवादित है)

10. नवादा जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौआकोल का निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग द्वारा दिनांक-26.12.2018 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में दिनांक-18.07.2019 को भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात् उक्त निर्माण कार्य निविदा की प्रक्रियाधीन है ।

11. लखीसराय जिलान्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग के पत्रांक-1704 दिनांक-23.07.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु स्थल अप्राप्त है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दो साल पहले घोषणा की थी कि 11 आई0टी0आई0 के भवन का निर्माण किया जायेगा । सरकार की तरफ से माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि कहीं स्थल निरीक्षण किया गया, इसका प्राक्कलन बनाया जा रहा है, कहीं विवादित है तो कहीं कुछ है ।

महोदय, दो साल पहले घोषणा सरकार की हुई, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि इसके लिए दोषी जो लोग हैं, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता, क्या सरकार जॉच करके उनपर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रशासी विभाग हमें प्रशासनिक स्वीकृति देता है और स्थल का चयन करता है । कहीं-कहीं स्थल विवादित है और सिर्फ जगह, हम माननीय सदस्य को जो जवाब दिए हैं, उसमें नवादा जिलान्तर्गत जो कौआकोल प्रशिक्षण संस्थान है, वहॉ पर इशू है, वहॉ पर जमीन भी उपलब्ध है लेकिन 2018 में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति आई है । इसकी हम जॉच करवायेंगे । बाकी सब जगह ट्रैक पर है । कहीं न कहीं इशूज हैं, कहीं-कहीं री-टेन्डर में है, चूंकि सिंगल टेन्डर पड़ा था ।

लेकिन हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि तीन महीना के अंदर इस इशू को हम रिजॉल्व कर देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी....

श्री भाई वीरेन्द्र : वही समय-सीमा चाहते थे, अभी तीन महीना का उन्होंने कहा है । धन्यवाद देते हैं।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने लम्बे-चौड़े जवाब में बताया लेकिन इनको राशि कब उपलब्ध हुई, यह नहीं बताये और इतने लम्बे समय तक राशि रह जाने के कारण जो प्राक्कलन का दर बढ़ेगा, क्या सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा ? इसके लिए कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हैं ? उनको कोई चिन्हित किया गया है ? यदि कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हैं तो उनपर कौन-सी कार्रवाई सरकार करना चाहती है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासी विभाग हमें जमीन और पैसा उपलब्ध कराता है । जब जमीन पूरी तरह से दुरूस्त रहेगा तभी उसपर कार्य शुरू हो सकता है । इन 11 आई0टी0आई0 में कुछ जगह काम प्रक्रियाधीन है, कुछ जगह काम, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था, उसके चलते भी बहुत से काम लम्बित हो गए थे और जहॉ पर जमीन में कहीं इशू नहीं है, वहॉ पर निविदा की प्रक्रिया में है ।

एक जगह सिर्फ नवादा का जो इशू है, वहाँ जमीन भी ठीक है, वहाँ पर टेन्डर भी टाईम पर हुआ था लेकिन वहाँ डिले हुआ है, वहाँ जो पदाधिकारी दोषी होंगे, हम तीन महीना का समय माँगे हैं, जो पदाधिकारी दोषी होंगे उसपर कार्रवाई करेंगे और जो 11 आई0टी0आई0 हैं, तीन महीना के अंदर शुरू कराने के लिए प्रक्रिया की शुरूआत करेंगे ।

टर्न-2/आजाद/03.03.2021

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर इतना विस्तृत है, बहुत पहले ही विभाग को गया और ऑनलाइन करने में क्या प्रोब्लम हुआ, यह जानकारी प्राप्त करके आगे से सुधार करवा लें।

श्री ललित कुमार यादव : ऑनलाइन जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष : ऑनलाइन जवाब मिलना चाहिए । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : अब कौन सी व्यवस्था आपकी है ?

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, ऑनलाइन जब आपने जवाब देने की व्यवस्था की है और आपने उत्तर को मुद्रित भी करवा दिया है । सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नं0 ......

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री विश्वनाथ राम ।

( व्यवधान )

यह उचित नहीं है, आप बैठिए । आपका समय आयेगा, उस समय बताइयेगा । पहले दूसरे सदस्य का समय है ।

(व्यवधान)

आप आसन के आदेश के बिना नहीं पूछ सकते हैं और न आपकी बात प्रोसीडिंग्स में जायेगी । आप लिखकर दे देंगे । माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ राम ।

माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज,मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-762 (श्री विश्व नाथ राम(क्षेत्र सं0-202 : राजपुर(अ0जा0)</u>

अध्यक्ष : आपको समय मिलेगा, आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ ग्राम सिकटौना है, जिसे पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्मित्त सरंजा नारायणपुर अतरौना से जहानपुर तक पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । पुल स्थल के दूसरी तरफ बसावटों को राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित इटाढ़ी अतरौना पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । प्रश्नाधीन पुल के स्थल ग्रामीण कार्य विभाग

के आरेखण में नहीं है । इसके अपस्ट्रीम में दो कि0मी0 और डाऊनस्ट्रीम में 1.5 कि0मी0 में पुल निर्मित है ।

अतएव इस निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री विश्व नाथ राम : महोदय, यह पहले से ही प्रस्तावित है । हमने जो सवाल किया है वह पहले से ही बिहार सरकार द्वारा उसी जगह जहां मैं मांग कर रहा हूँ, उसी जगह प्रस्तावित था । लेकिन अब किन परिस्थितियों के कारण पुल को अन्य जगह किया गया, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ ?

अध्यक्ष : जवाब दे दिये हैं, यह स्थानांतरित हुआ है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-763(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह)</u>

क्षेत्र सं0-221 नवीनगर

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता(असै0) के कुल 355 स्वीकृत पद के विरूद्ध 260 पदों पर पदाधिकारी कार्यरत है । इस प्रकार वर्तमान में कार्यपालक अभियंता(असै0) के कुल 95 पद रिक्त है ।

विषयांकित प्रमंडल उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन है, जिसके अधीन स्वीकृत 05 कार्य प्रमंडलों में से 04 कार्य प्रमंडलों के पदों पर वर्तमान में कार्यपालक अभियंता(असै0) कार्यरत है ।

विषयांकित पद का अतिरिक्त प्रभार निकटवर्ती कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा को प्रदान कर कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

अभियंताओं की उपलब्धता होने पर विषयांकित प्रमंडल में पूर्णकालिक कार्यपालक अभियंता का पदस्थापन किया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए । बैठ जाइए माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है कि 355 कार्यपालक अभियंता का पद है, जिसमें 260 ही कार्यरत हैं और 95 अभी रिक्त है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि यह जो 95 रिक्त है, वह कब तक भरेगा ?

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो इनका प्रश्न था तो उसके संबंध में हमने यह कहा कि औरंगाबाद में 5 एजक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है, जिसमें 4 में एजक्यूटिव इंजीनियर कार्यरत हैं और एक के पास एडिशनल चार्ज है । असिसटेंट इंजीनियर का इन्टरव्यू चल रहा है बी0पी0एस0सी0 में, 13 अप्रील तक वह खतम हो जायेगा और बहाली हो जायेगी

। हमलोगों को लगता है कि जून तक स्ट्रैन्थ बढ़ जायेगा और उसके बाद पोस्टिंग हो जायेगी ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ....

अध्यक्ष : अब तो समय भी बता दिये ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : 5 में 4 कार्यरत है । 5 एजक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है, जिसमें 4 कार्यरत है, सिर्फ एक के पास एडिशनल चार्ज है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी जब खड़े होते हैं तो बैठ जाइए न ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : सिर्फ एक के पास एडिशनल चार्ज है । अभी इन्टरव्यू चल रहा है असिसटेंट इंजीनियर का, 13 अप्रील तक बी0पी0एस0सी0 का इन्टरव्यू पूरा हो जायेगा, उसके बाद जो असिसटेंट इंजीनियर ऑलरेडी कार्यरत हैं उनका प्रमोशन होगा और जून तक हमारा स्ट्रैन्थ पूरा हो जायेगा तो जो पांचवां है, वह भी चला जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-764 (डॉ0 संजीव कुमार,क्षेत्र सं0-151 परबत्ता)

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए, ऑनलाइन उत्तर मिला है ।

डॉ0 संजीव कुमार : महोदय, नहीं मिला है, नहीं आया है । जवाब दे दें तो अच्छा रहेगा माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : ठीक है, जवाब दे दीजिए लेकिन जब ऑनलाइन डालते हैं तो लोग उसको देखें ।

डॉ0 संजीव कुमार : मैं देखा हूँ, नहीं मिल रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं दिखता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप तो ऑनलाइन डाले हैं, हमलोगों के पास तो आया है । एक चीज माननीय मंत्री जी, सरकार के सभी माननीय मंत्री सुन लें कि ऑनलाईन कम से कम 24 घंटा पहले डलवा दें और सभी लोग देख लें ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अगुवानी-सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है जिसे दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

गोगरी प्रखंड के रामपुर पंचायत से कटघरा आश्रम से भूड़िया दियारा तक जाने वाली सड़क पथ प्रमंडल, खगड़िया के क्षेत्राधीन है ।

उक्त पथ के चैनेज 3300 एवं चैनेज 12200 में अवस्थित पुल क्षतिग्रस्त होने पर अस्थायी पुर्नस्थापन कार्य कराकर यातायात चालू किया है । उक्त पथ में क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर नये एच0एल0 ब्रीज के निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा समर्पित डी0पी0आर0 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है । मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि यह पुल अगुवानी-सुल्तानगंज पुल माननीय मुख्यमंत्री और मेरे आदरणीय पिता श्री

आर0एन0 सिंह पूर्व मंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और फरवरी, 2014 में और उस समय से 7 साल हो गया, उसका कमप्लीशन का समय 5 साल का था लेकिन अभी तक कमप्लीट नहीं हुआ । आपने समय दिया है दिसम्बर तक हो जायेगा । इतना वक्त क्यों लगा और संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? दूसरा प्रश्न जो हमारा है, इसी के साथ हमारा है कि रामपुर से लेकर के कटघरा आश्रम जाता है, वो पुल जब बना था, उसी साल बाढ़ आया और उसी साल बाढ़ में वह पुल बह गया । अब 5 साल में आपके विभाग का क्या अनुरक्षण हुआ है, कोई मेनटेनेन्स नहीं किया गया। नया पुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बना और संवेदक पर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई और अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई और कार्रवाई करेंगे तो कब तक करेंगे ?

अध्यक्ष : ठीक है, एक ही बार इतना पूरक पूछ लीजिए, बोलिए माननीय मंत्री जी ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अधीन काम करने का प्रयास किया गया। शुरू में भू-अर्जन की प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हुआ लेकिन उसमें अभी 11 कि0मी0 पहुॅंच पथ में ही भूमि का अधिग्रहण प्राप्त होना बचा हुआ है । बाकी सब काम हुआ है और भूमि अधिग्रहण का कागज आ चुका है । उन्होंने दो एच0एल0 ब्रीज की बात की है, उसका डी0पी0आर0 आ चुका है और बहुत जल्द उसको हमलोग निविदा की प्रक्रिया में भेजेंगे डी0पी0आर0 आने के बाद ।

डॉ0 संजीव कुमार : महोदय, मैं तो सुन लिया कि वे बनायेंगे पहले भी बोले हैं माननीय मंत्री जी, मैं कह रहा हूं कि 5 साल में कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, जो संवेदक हैं जो मेनटेनेन्स नहीं किये और पुल बनने के बाद ही बह गया । माननीय मंत्री जी कार्रवाई करने .....

अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि भू-अर्जन के कारण ।

डॉ0 संजीव कुमार : महोदय, वह दूसरी बात है । वे गंगा पुल के बारे में बताये हैं । मैं बात कर रहा हूॅं जो पुल बह गया है, मैं उसकी बात कह रहा हूॅं जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, 5 साल की उनकी जिम्मेवारी थी, इसके लिए न संवेदक पर कार्रवाई की गई और न अधिकारियों पर ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस चीज की सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं ...

अध्यक्ष : आप उसको जॉंच करवा दीजिए ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : जॉंच करवाकर और जो भी ऐसा कोई विषय आयेगा ....

अध्यक्ष : जॉंच करवाकर के माननीय सदस्य को अवगत कराइए और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसको संज्ञान में लीजिए ।

डॉ0 संजीव कुमार : महोदय, एक और भी माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जो पुल वहां पर बनेगा अगुवानी-सुल्तानगंज तो हमारे विधायक जी भी हैं, वे भी कह रहे थे कि सुल्तानगंज साइड में एक एप्रोच पथ उसमें दिया जाय छोटी-छोटी गाड़ियों के लिए ताकि आसान रहेगा जाने में ।

अध्यक्ष : आपका तीन पूरक हो चुका, अब आप बैठ जाइए ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, सुल्तानगंज में ही बहुत दूर में जाकर के जिसका जीरो प्वायंट बना है । सुल्तानगंज में ही छोटी गाड़ियों को उतरने के लिए उसमें एक एप्रोच पथ बने जिससे छोटी गाड़ियां, मोटरसाईकिल सब उतर जाय ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : इसपर हम पहले माननीय सदस्य से बातचीत करके देख लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-765(श्री संजय सरावगी,क्षेत्र सं0-83 दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार एवं रेलवे के बीच 50-50 प्रतिशत कौस्टशेयर के आधार पर आर0ओ0बी0 एवं पहुॅच पथ दोनों के निर्माण हेतु एम0ओ0यू0 1/4 मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरटेकिंग 1/2 पर हस्ताक्षर दिनांक 07.05.2019 को किया गया है।

1. एल0सी0नं0-25 पर आर0ओ0बी0 का निर्माण बी0एस0आर0डी0सी0 एल0 द्वारा कराया जाना है, जिसका डी0पी0आर0 का गठन कर लिया गया है ।

2. दरभंगा जिला मुख्यालय से म्यूजियम गुमटी नं0-26 का जेनरल एरैंजमेंट ड्रॉईंग रेलवे को समर्पित किया गया है । अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

पथ निर्माण विभाग/रेलवे द्वारा प्रशासनिक अनुमोदनोपरान्त आर0ओ0बी0 का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इसका ऑनलाइन जवाब आया हुआ है । मैं इसपर यह बोलना चाहता हूॅं कि पूरा दरभंगा शहर में आर0ओ0बी0 नहीं बनने के कारण पूरा जाम रहता है और 4 साल पहले ही दरभंगा शहर में 7 जिसमें बेला गुमटी, दिल्लीमोड़, दोनार गुमटी, म्यूजियम गुमटी, पंडासराय गुमटी, चट्टी चौक यहां के लिए आर0ओ0बी0 स्वीकृत हुआ था और माननीय मंत्री जी यह बता रहे थे कि अभी प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गयी है तो माननीय मंत्री जी बतावें कि इसके कारण पूरा दरभंगा शहर जाम रहता है । ये 7 आर0ओ0बी0 ब्रीज कब तक बनकर तैयार हो जायेगा, 4-5 साल हो गया रेलवे विभाग को स्वीकृति दिये हुए मैं यह पूछना चाहता हूॅं ?

टर्न-3/शंभु/03.03.21

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है इसमें आर0ओ0बी0 की पहले की जो प्रक्रिया थी और अब के प्रक्रिया में तीन साल पहले दोनों राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में सहमति बनी और अभी हमलोग 53 आर0ओ0बी0 पूरे राज्य में बना रहे हैं इस फार्मूले के तहत जिसमें दरभंगा जिले में 10 स्वीकृत है और इस वित्तीय वर्ष सभी में हमलोगों की काम लगाने की योजना है, जो पैसे का भी था, कुछ जो प्रक्रियाधीन है उसमें दरभंगा जिले के 3 आर0ओ0बी0 का अभी भी प्रक्रिया में हैं जिसमें आपका 2 है, बाकी 1 और रूका हुआ है । ये 53 पर इस वित्तीय में हमलोगों के यहां काम लग जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि तीन साल पहले रेल विभाग और पथ निर्माण विभाग के बीच एम0ओ0यू0 साइन हुआ तो ये तीन साल लग गया और अभी तक प्राक्कलन की स्वीकृति भी नहीं आयी है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि यह बहुत महत्वपूर्ण आर0ओ0बी0 है ।

अध्यक्ष : आपलोग शांति बनाये रखिये । यह प्रश्न पक्ष और विपक्ष का नहीं है यह प्रश्न सदन का है और सभी सदस्य को ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए ।

श्री संजय सरावगी : माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूरे बिहार में 54 बना रहे हैं उसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 54 में 7 केवल दरभंगा शहर के लिए आर0ओ0बी0 है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अभी तक प्राक्कलन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तो समयबद्ध करें कि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कब तक हो जायेगी। प्रशासनिक स्वीकृति कब तक हो जायेगी ताकि काम में हाथ लगेगा ।

श्री नितिन नवीन,मंत्री : यह पूरी आर0ओ0बी0 की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई तकनीकी पहलू है कि रेलवे को गैट के परमिशन के लिए भेजना पड़ता है बिहार सरकार को फिर वहां से परमिशन आता है फिर डी0पी0आर0 की प्रक्रिया होती है और डी0पी0आर0 के बाद फिर फायनल कन्फर्मेशन के लिए, फायनल डिसिजन के लिए फिर हमलोग केन्द्र भेजते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में समय जरूर लगा है, लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है हमलोग पूरा प्रयास करेंगे कि अगले तीन महीने में प्रक्रिया को स्पीड करके काम शुरू कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री नन्दकिशोर यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सदन को करेक्ट करना चाहता हूँ । मैंने जो प्रश्न देखा है और माननीय मंत्री का जो जवाब देखा है उसमें एक त्रुटि है, आर0ओ0बी0 का अर्थ अलग-अलग होता है, अगर कोई सड़क के उपर रेल लाइन का पुल बनता है उसको कहते हैं रेल ओवर ब्रिज, लेकिन अगर रेलवे लाइन के उपर कोई ब्रिज बनता है उसको रोड ओवर ब्रिज कहते हैं, लेकिन माननीय प्रश्नकर्त्ता ने भी उसको

रेल ओवर ब्रिज लिख दिया और माननीय मंत्री जी ने जवाब में भी उसको रेल ओवर ब्रिज लिख दिया । मेरा आग्रह केवल इतना ही है कि ये डोकुमेन्ट होता है सदन की कार्यवाही इसमें इसको करेक्ट कर लें कि वह रोड ओवर ब्रिज होगा न कि रेल ओवर ब्रिज होगा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि बिहार में 53 आर0ओ0बी0 ये बनवा रहे हैं। भागलपुर का 68 करोड़ में पांच साल पहले बना था उसके बाद फिर से डी0पी0आर0 बना, रेलवे तीन बार ऑब्जेक्शन किया फिर पास हुआ । यह जो कोस्टिंग बढ़ता है और काम नहीं होता है, इसका जवाबदेह कौन है ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न आपका इससे जुड़ा नहीं है आप इसपर अलग से प्रश्न लाइयेगा ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, एक ही प्रश्न पर सदन का पूरा समय नहीं जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-766(श्री रितलाल राय)क्षेत्र सं0-186 दानापुर

(उत्तर मुद्रित)

श्री जयंत राज,मंत्री : 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति है कि प्रश्नाधीन आनंद बाजार से चांदवारी होते हुए डी0पी0एस0 स्कूल तक पथ की मरम्मति कार्य बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत प्रारंभ है । तद्नुसार शीघ्र मरम्मति कार्य करा दिया जायेगा ।

2- खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर मुद्रित है पूरक पूछिए ।

श्री रितलाल राय : माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ ।

डा0 रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, यह पथ बहुत ही महत्वपूर्ण पथ है ।

अध्यक्ष : कौन सी रोड का ?

डा0 रामानन्द यादव : यह आनंद बाजार से चांदवारी रोड ।

अध्यक्ष : जो प्रश्न किये उन्होंने धन्यवाद दे दिया तो आप क्या कह रहे हैं ?

डा0 रामानन्द यादव : वे नहीं समझे ।

अध्यक्ष : वे कैसे नहीं समझे, वे सदस्य हैं ।

डा0 रामानन्द यादव : वे सदस्य हैं तो हम भी सदस्य हैं । मेरे समय में वह रोड बना था, लेकिन कन्टेनमेंट रोड से आवागमन चालू हो गया, वह रोड एकदम मृत हो गया और अभी गड्ढा में तब्दील है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी डी0एम0 गये थे बात करने के लिए ब्रिगेडियर से और ब्रिगेडियर ने कहा कि.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पूरक ।

डा0 रामानन्द यादव : पूरक मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जवाब दिया कि ग्रामीण कार्य के 2018 के अनुरक्षण नीति के तहत प्रारंभ है । कब तक यह रोड बनेगा ? चूंकि वहां के लोगों का आवागमन कन्टोनमेंट द्वारा बंद है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप जवाब दिये हैं कि शीघ्र मरम्मति कार्य कराया जायेगा । समय सीमा बता दीजिए ।

श्री जयंत राज,मंत्री : अगले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-767(श्री समीर कुमार महासेठ)क्षेत्र सं0-36 मधुबनी

(उत्तर मुद्रित)

श्री नितिन नवीन,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ कई भागों में है जिसकी स्थिति निम्नवत् है ।

1- मुधबनी नगर परिषद् क्षेत्र में पड़नेवाली कोतवाली चौक से सिंधिनिया चौक तक सड़क पथ निर्माण विभाग के रैयाम मधुबनी पथ के अधीन है, जिसे ओ0पी0आर0एम0सी0 फेज-2 के अन्तर्गत संधारित किया जा रहा है एवं पथ की स्थिति अच्छी है ।

2- स्टेडियम गांधी चौक होते हुए महाराजगंज गांधी चौक, सूड़ी हाइस्कूल चौक तक सड़क नगर परिषद् मधुबनी के अधीन है ।

3- सूड़ी हाईस्कूल से किशोरी लाल चौक तक पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत रहिका मधुबनी पथ का अंश है, जिसकी स्थिति अच्छी है ।

4- किशोरी लाल चौक से संतु नगर तक का सड़क नगर परिषद् मधुबनी के अधीन है।

5- सूड़ी हाईस्कूल से महंथीलाल चौक तक का सड़क पथ निर्माण के रहिका मधुबनी पथ का अंश है, जो अच्छी स्थिति में है ।

6- महंथी लाल चौक से सुमंता होटल तिलक चौक होते हुए गौशाला चौक तक का सड़क नगर परिषद् मधुबनी के अधीन है । इस प्रकार प्रश्नाधीन पथों में से कोतवाली चौक से सिंधिनिया चौक, सूड़ी हाईस्कूल से किशोरी लाल चौक एवं सूड़ी हाईस्कूल से महंथी लाल चौक तक का पथ, पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत है तथा पथों की स्थिति अच्छी है । शेष पथांश नगर परिषद् मधुबनी के अधीन है । नयी पथ अधिग्रहण नीति के अनुसार पथ अधिग्रहण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग से निकायवार समेकित प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए, आपलोग भी पूरक नहीं पूछियेगा तो कौन पूछेगा ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो जवाब दिया है, लेकिन आग्रह करेंगे कि जब डिपार्टमेंट को......

अध्यक्ष : अब धन्यवाद दे दिया तो बैठ जाइये । अब श्रीमती अरूणा देवी । धन्यवाद दिये तो संतुष्ट हैं, अब आप बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-768(श्रीमती अरूणा देवी)क्षेत्र सं0-239 वारिसलीगंज

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सकरी सिंचाई योजनान्तर्गत नवादा जिले के सकरी नदी पर पौरा बियर निर्मित है । इसके दायां मुख्य नहर के 0.24 कि0मी0 से बेलहा वितरणी मिश्रित है । जिसकी कुल लंबाई 7 कि0मी0 है । मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा बिहारशरीफ को विभागीय पत्रांक-256, दिनांक-25.02.2011 द्वारा खरीफ वर्ष 2021 के पूर्व वर्णित नहर का सम्पोषण एवं मरम्मति कराते हुए नहर के अंतिम छोड़ तक जलस्राव उपलब्ध कराने हेतु निदेशित कर दिया गया है ।

श्रीमती अरूणा देवी : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : वे संतुष्ट हैं अब आप पूछिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, जो पौरा छिलका है वह अस्थामा तक आता है उसका अंतिम छोड़ और वह अतिक्रमित है, वह अतिक्रमण का शिकार है तो कब तक उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार सरकार रखती है ?

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : महोदय, मैं इसको देखवा लेता हूँ ।

तारांकित प्रश्न सं0-769(श्री शकील अहमद खां)क्षेत्र सं0-64 कदवा

(श्री संदीप सौरव प्राधिकृत)

श्री जयंत राज,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों पथ के निर्माण हेतु शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-3 के अन्तर्गत सर्वे कार्य कराया जा रहा है । तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-770(श्रीमती वीणा सिंह)क्षेत्र सं0-129 महनार

श्री जयंत राज,मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । पथ की लंबाई 17.45 कि0मी0 है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न तीन पथों से संबंधित है । महनार अम्बेदकर चौक से अंधराबड पथ की लंबाई 11.50 कि0मी0 है । पथ की मरम्मति शीर्ष 3054 एम0आर0 योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराया गया है । पथ अनुरक्षण अवधि में है एवं अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है ।

क्रमशः

टर्न-4/ज्योति/03-03-2021

क्रमशः

श्री जयंत राज, मंत्री : पथ की चोड़ाई 3.75 कि0मी0 है, अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात् ट्रैफिक सर्वे कराने के बाद पथ के चौड़ीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव

हो सकेगा । दूसरा पथ है अंधराबड से धंदुआ तक पथ- इस पथ की लम्बाई 2.95 कि.मी. है । इस पथ के 2.05 कि.मी. पथांश की मरम्मती का कार्य 3054 एम.आर.ई. योजना के अंतर्गत कराया गया है । पथ अनुरक्षण अवधि में है और अनुरक्षण कराया जा रहा है । शेष पथांश 0.90 कि.मी. में मरम्मती कार्य नये अनुरक्षण नीति के अंतर्गत पूर्ण कराया गया है । पथ अनुरक्षण अवधि में है और अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। पथ क्रश की चौड़ाई 3.75 मीटर है अनपुरक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात् ट्रैफिक सर्वे कराने के बाद पथ का चौड़ीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा ।

तीसरा पथ है धंदुआ से बहसी तक पथ इस पथ की लंबाई 3 कि.मी. है जो पथ निर्माण विभाग के अधीन है ।

श्रीमती वीणा सिंह : अध्यक्ष महोदय, चौड़ीकरण बहुत जरुरी है चूँकि यह बहुत ही व्यस्त सड़क है और हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है एवं लोगों को बहुत परेशानी होती है इसलिए जल्द से जल्द इसका चौड़ीकरण कराया जाय और यह चौड़ीकरण कबतक होगा ?

श्री जयंत राय, मंत्री : अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद इसको करवायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 771 (श्री गुंजेश्वर साह,क्षेत्र सं0-77,महिषी)- अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या 772 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव,क्षेत्र सं0-17, पिपरा)

(लिखित उत्तर )

श्री जयंत राज, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.25 कि0मी0 है । प्रश्नाधीन पथ के एक छोर का बसावट मधुरापुर अनुसूचित जाति बस्ती मुख्य बसावट मधुरापुर के आंतरिक पथ पर अवस्थित है । मुख्य बसावट मधुरापुरा को चकिया मधुरापुर पी0डब्लू0डी0पथ0 एवं पिपरा कल्याणपुर आर0डब्लू0डी0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरे छोर का बसावट उचिडीह को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित महरानी से मुस्लिम टोला लोकाई बेलवा पथ में सम्पर्कता प्राप्त है । बीच में चौर होने एवं कोई योग्य बसावट नहीं होने के कारण किसी भी कोर नेट वर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब का निष्कर्ष है कि बीच में चौर होने एवं कोई योग्य बसावट नहीं होने के कारण किसी भी कोर नेट वर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है ।अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मंत्री जी से पूछना

चाहूंगा कि इसमें चौर नहीं है और बसावट भी योग्य है कोर नेट वर्क में नहीं होने के कारण विभाग द्वारा इसको दिग्भ्रमित किया गया है इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि कबतक कोर नेटवर्किंग में जोड़वाकर कबतक रोड निर्माण का काम करेंगे ?

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो जो ग्राम का जो जो बसावट का इन्होंने प्रश्न किया है मेरे पास सूचना है कि दोनों तरफ के बसावट में सम्पर्कित पथ है और अभी विभाग द्वारा अभी कोई ऐसा विचार नहीं है कि यहाँ पुल बनाया जाय ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि विचार क्यों नहीं है ? जब इनका विभाग कोर नेटवर्किंग में नहीं जोड़ा और सदन को दिग्भ्रमित कर दिया तो उसको कोर नेटवर्किंग में जाँच कराकर कोर नेटवर्किंग में जोड़ना चाहिए और इसका निर्माण कराना चाहिए ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विचार क्यों नहीं है ?

श्री जयंत राज, मंत्री : अच्छा, हम इसको पुनः जाँच करवा लेंगे और इनको बुला कर पूछ लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या -773 (श्री शाहनवाज, क्षेत्र सं0-50,जोकीहाट)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवन सह निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना के निर्माण हेतु 12.15 करोड़ रुपये की लागत व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त योजना के पुनरीक्षित तकनीकी प्राक्कलन ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त हुआ है । विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है । समीक्षोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री शाहनवाज : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या 774 (श्रीमती विभा देवी, क्षेत्र सं0-237, नवादा)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग । प्रश्न का उत्तर औन लाईन है, पढ़ दीजिये एक बार ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । यह पईन सकरी नदी से निकलती है जिसका सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है । सर्वेक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर विहित प्रक्रिया के तहत निधि उपलब्धता के आधार पर पईन का जीर्णोद्धार कार्य कराया जायेगा ।

श्रीमती विभा देवी : कबतक ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : यह जनपयोगी योजना है और हमलोग इसके प्रति पूरी तरह संकल्पित हैं, हम समझते हैं बहुत जल्द ही यह कार्य करा लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या -775 (श्री सिद्धार्थ सौरव, क्षेत्र सं0-191, विक्रम)

अध्यक्ष : उत्तर आपका संलग्न है ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : हम देखें हैं एरर आता है, साईट नहीं खुल रहा था ।

अध्यक्ष : पथ निर्माण विभाग देखें एरर क्यों आता है । औन लाईन क्वेश्चन, सुन लीजिये, औन लाईन जिस विभाग के जवाब नहीं आते हैं माननीय मंत्री पदाधिकारी से स्पष्टीकरण लें और विधान सभा को अवगत करायें कि क्यों ऐसा हो रहा है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : आपके साईट पर आ रहा होगा आपके औफिस को देखवाना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है ।

अध्यक्ष : हमारे पास जवाब आया हुआ है, माननीय मंत्री जवाब पढ़ दीजिये ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वर्तमान में पथ में इम्प्रूभमेंट औफ राईडिंग क्वालिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य प्रगति में है । पथ में अवस्थित पुल पुलिया पुराने हैं वर्णित स्थल पर सर्वेक्षण के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष में पुलिया निर्माण का लक्ष्य है ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने ऐसा एस्टीमेट पूरे बिहार में बना रखा है, न नाला का निर्माण देखते हैं और जहॉ आवश्यक पुल पुलिया है, उसको देखते हैं तो क्या किसानों की वेदना के लिए उनकी समस्या के लिए आज सरकार चिन्तित नहीं है, आज घड़ाघड़ रोड बनते जा रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये भूमिका नहीं बनाईये ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : कबतक बनवा देंगे ? अभी काम स्थगित करवा दें ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में पुलिया के निर्माण करने का लक्ष्य है ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : अभी कम से कम काम रुकवा दिया जाय नहीं तो सारे घर में पानी घुस जायेगा।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : हम दिखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 776 (सुश्री श्रेयसी सिंह, क्षेत्र सं0-241, जमुई)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय , 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल 3053 एम.आर.ई. योजनान्तर्गत निर्मित खैरा सोनो पथ से टिहिया भाया डिहरी डीह कोरवाडीह पथ के आरेखन में अवस्थित है । उक्त पुल के निर्माण हेतु टेक्नोफिजिब्लिटी रिपोर्ट की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गयी है तत्पश्चात् तकनीकी समीक्षोपरान्त आवश्यक कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से बस यही आग्रह है कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द कराया जाय क्योंकि वहाॅं के लोग बहुत आपसे आशा रखते हैं साथ ही माननीय मंत्री जी की सकारात्मक सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या 777 (श्री संदीप सौरभ, क्षेत्र सं0-190,पालीगंज)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के एक तरफ समदा गांव हैं जिसे पी0एम0जी0एस0वाय0 2 के अधीन निर्माणाधीन खिरी मोड़ से गौस गंज समदा पथ तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी । पुनपुन नदी के दूसरी तरफ बहादुरगंज बसावट एन.एच. 69 से बहादुरगंज पथ पर अवस्थित है। प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ बसावटों के एकल सम्पर्कता प्रदत है । यह ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर अवस्थित नहीं है । पुल के स्थल डाउनस्ट्रीम में 3.5 कि. मी. पर, अपस्ट्रीम में 9 कि.मी. पर पुल निर्मित है इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, समदा जो गांव है वहाॅं साल में एकबार बड़ा मेला लगता है और कई बार ऐसा हुआ है कि नदी को क्रौस करने के चलते लोग डूब गए हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री संदीप सौरभ : वहीं बोल रहा हूॅं । पचास हजार की आबादी उसके आस पास है और लंबे समय से वहाॅं लोगों की मांग है तो अलग अलग विभागों के चलते सिर्फ वहाॅं पुल नहीं बन पायेगा समदा बहादुर गंज के बीच में और वह क्यों नहीं बन पायेगा ? यह हम पूछना चाहते हैं ?

श्री जयंत राज, मंत्री : दोनों गांव के एक तरफ डाउन स्ट्रीम में 3.5 कि.मी. में पुल है और एक तरफ अपस्ट्रीम में 9 कि.मी. पर पुल है आसपास में काफी पुल अभी है । अभी कुछ विचाराधीन नहीं है । आगे देखा जायेगा ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, 9 कि0मी0 तो काफी दूर है । अगर किसी को जाना है तो 9 कि0मी0 चल कर जायेगा, वहां घनी आबादी दोनों साईड में है और 9 कि0मी0 जायेंगें पुल क्रौस करके तो यह तो ठीक बात नहीं है ।

अध्यक्ष : वह देखने की बात कहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 778 (श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्र सं0-16,कल्याणपुर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, संदीप सौरभ के प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया और उन्होंने खुद कहा कि 9 कि.मी. पर पुल ..

अध्यक्ष : अब तो आगे बढ़ गये उसी समय उठकर पूरक आप पूछ लेते । अब गाड़ी आगे बढ़ गयी। अब बैठ जाईये । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : यह तो जल संसाधन विभाग का प्रश्न है । स्थानांतरित हुआ है अभी जवाब आया नहीं है । अगली डेट में इसका जवाब आयेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्न स्थानांतरित हुआ है ।

टर्न-5/अभिनीत/पुलकित/03.03.2021

तारांकित प्रश्न संख्या- 779

(श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0- 82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है, प्रश्न दो पथों से संबंधित है ।

1- धोयी से मिश्रौलिया पथ- इस पथ की लम्बाई 1.2 कि0मी0 है । यह पथ धोयी से आमी (10.0 कि0मी0) का पथांश है, जिसमें 8.75 कि0मी0 पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित है । शेष 1.2 कि0मी0 ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । पथ की पूरी लम्बाई में पी0सी0सी0 का कार्य किया हुआ है, जो वर्तमान में अच्छी स्थिति में है । वर्ष 2020 में आयी बाढ़ के कारण पथ के लगभग 0.5 कि0मी0 की लम्बाई में नदी के तरफ स्लोप में सोल्डर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका पुनर्स्थापन कार्य करा लिया गया था । वर्तमान में पथ मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

2- सोनकी थाना चौक से लरवाना पथ - यह पथ एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्माणाधीन है । वर्ष 2020 में आयी बाढ़ के कारण लगभग 150 मीटर में तालाब के किनारे सोल्डर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका मरम्मती शीघ्र ही करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष: श्री ललित कुमार यादव, उत्तर मुद्रित है, स्थानांतरित हुआ है । पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, ये दो पथों से संबंधित है, धोयी से मिश्रौलिया और सोनकी थाना चौक से लरवाना पथ । दोनों पथों में मैंने स्पष्ट पूछा है कि पथ में कटाव हो रहा है इसमें प्रोटेक्शन वाल का निर्माण माननीय मंत्री कब तक करना चाहते हैं, फिर इनका वही जवाब कि अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । हम प्रोटेक्शन वाल, रोड अनुरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्शन वाल का निर्माण माननीय मंत्रीजी कब तक करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत इसका प्राक्कलन तैयार किया गया है । इसमें जब किसी का प्राक्कलन तैयार किया जाता है तो उसमें जरूरत के जो

सामाग्री होते हैं सबकुछ डाला जाता है । बोल्डर पिसिंग, बोल्डर कंक्रीट, एप्रोच सुरक्षा के जो भी प्रावधान हैं, इसमें लगभग 150 मीटर का किया गया है । एक जगह है, जो आपका है धोयी से मिश्रौलिया पथ और एक पथ है सोनकी थाना से लरवाना पथ, इसका एम0एम0जी0एस0वाई0 से यह रोड बन रहा है और एकरारनामा के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि है 07.08.2020 और एकरारनामा की समाप्ति तिथि है 06.08.2021, इसमें संवेदक राधे श्याम काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें बाढ़ में कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था तो उसके प्रोटेक्शन वाल के निर्माण का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि प्रोटेक्शन वाल का निर्माण करने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री जयंत राज, मंत्री: हाँ, प्रोटेक्शन वाल का उसमें जितना जरूरत होगा उसका विचार रखती है ।

श्री ललित कुमार यादव: माननीय मंत्रीजी, ठीक है । महोदय, ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन वाल का निर्माण करायेंगे, दोनों पथों में माननीय मंत्रीजी अगले वित्तीय वर्ष में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण करा देंगे ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप देख लीजिए । अगले वित्तीय वर्ष में, इनका पूरक है देख लीजिएगा ।

श्री जयंत राज, मंत्री: जल्द ही इसको दिखवा लेते हैं, चूंकि दोनों पथ में..

अध्यक्ष: श्री राम विशुन सिंह ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, माननीय मंत्रीजी अभी जवाब दे रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री जयंत राज, मंत्री: हम आपको बुलाकर बात भी कर लेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: हाँ, आपको बुलाकर कर बात कर लेंगे । आप बैठ जाइये मंत्री जी ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, हमने सदन में पूछा है, सदन में ही जवाब चाहते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में उक्त दोनों पथों में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण करा देंगे या नहीं ? महोदय, सदन में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: हो गया न, वो बोल दिए हैं न । राम विशुन सिंह । गाड़ी तेजी से बढ़ेगा ही क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 780

(श्री राम विशुन सिंह, क्षेत्र सं0- 197, जगदीशपुर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभी यह ट्रांसफर होकर पंचायती राज विभाग में नहीं आया है ।

अध्यक्ष: नहीं आया है, ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 781

(श्री विनय बिहारी, क्षेत्र सं0- 5, लौरिया)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण के योगापट्टी और लौरिया दोनों प्रखंड के बीच लखनी चौर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1454 हेक्टेयर है । इस चौर से पानी को निकालने के लिए पूर्व में नाला का निर्माण किया था । चौर का पानी पूर्व निर्मित नाला होते हुए हरहा नदी के माध्यम से गंडक में गिरता है । पूर्व में हरहा नदी की चौड़ाई 150 फीट थी, वर्तमान में अत्याधिक गाद भर जाने के कारण नदी की चौड़ाई मात्र 10 से 15 फीट शेष रह गयी है । समुचित रूप से जल निकासी हेतु नाला को पक्के किये जाने की नहीं बल्कि नाला के साथ-साथ हरहा नदी के तल सफाई की आवश्यकता है । उक्त क्रम में विभागीय पत्रांक 1304 के द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण मुजफ्फरपुर को प्रश्नगत नाला की सफाई हेतु विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत यथोचित प्रस्ताव विभाग को समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि, मैं लखनीचंबर के जल जमाव की बात कर रहा हूं, मैं सिकरहना नदी की सफाई की बात नहीं कर रहा हूं । सिकरहना नदी लखनीचंबर के उत्तर में है और सेमरीमन जो है वह लखनीचंबर के पश्चिम में है, जबतक पक्का नाला का निर्माण कराकर के इस जल जमाव को हटाया नहीं जायेगा, जैसा अभी मंत्रीजी ने बताया कि कितनी जमीन है, किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा है, ऐसे उत्तर से तो, यह सवाल तो 2 साल पहले भी सदन में आ चुका है ।

अध्यक्ष: आपका पूरक क्या है, सीधे पूरक पूछिये ।

श्री विनय बिहारी: महोदय, जल जमाव को दूर करवाने के लिए हमें समय चाहिए, हमें समय दिया जाय कि कब तक इस जल जमाव को सिकरहना ......

अध्यक्ष: आप जानकारी चाहते हैं कब तक ।

श्री विनय बिहारी: जी महोदय, माननीय मंत्री जी समय-सीमा बतायें ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि हम लोगों ने चीफ इंजीनियर मुजफ्फरपुर से डिटेल्स और इसका प्रपोजल मांगा है । 26 फरवरी को लेटर लिखा है वो डिटेल प्रपोजल लेकर आ रहे हैं इसके बाद हम लोग तुरंत कार्रवाई शुरू कर देंगे ।

अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-782

(श्री शमीम अहमद, क्षेत्र सं0-12, नरकटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री: महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.5 किलोमीटर है । इस पथ के एक छोर पर अवस्थित रेगनियां ग्राम को पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत निर्मित अगरबा से रेगनियां पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरे छोर पर अवस्थित ग्राम जितना को पी0एम0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित घोड़ासहन बनकटवा-जितना पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । इस पथ के आरेखन में अन्य कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण किसी कोर-नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

अत: पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष: उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिये ?

श्री शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने स्वीकार किया है कि 2.5 किलोमीटर कच्ची सड़क है और इसके बन जाने से ब्लॉक की दूरी मात्र 3 किलोमीटर हो जायेगी । अभी ब्लॉक आने में कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक-दो वाक्य में पूरक पूछ लीजिये । उत्तर मुद्रित है । आप सीधे पूरक पूछिये ताकि अगले सदस्यों का भी प्रश्न आ सके ।

श्री शमीम अहमद: महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस रोड को जनहित में बनवा दें, क्योंकि ब्लॉक और हॉस्पिटल जाने में 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ।

अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्रीजी आप इस प्रश्न को देख लीजिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-783

(श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जा चुका है ।

केसरिया प्रखंड चकिया अनुमंडल में तथा संग्रामपुर प्रखंड अरेराज अनुमंडल के अंतर्गत पड़ता है, जहां क्रमश: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरेराज संचालित है । इसके अतिरिक्त पूर्वी चंपारण जिला के 05 अनुमंडलों में भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है ।

पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत स्थापित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केसरिया विधान सभा क्षेत्र के केसरिया एवं संग्रामपुर प्रखंड सहित सभी प्रखंडों के इच्छुक युवक/युवती तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं ।

वर्तमान में राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में कोई अन्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष: उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, एक पूरक है । मैं माननीय मंत्रीजी से पूछती हूं कि सरकार महिलाओं और युवाओं के स्वरोजगार के लिए काफी जागरूक है और काम कर भी रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि जब जिला मुख्यालय या अनुमंडल में जाकर बच्चे पढ़ेंगे, दूरी होने की वजह से 25 से 50 किलोमीटर की दूरी होती है तो बच्चे जा नहीं पाते हैं, तो स्वरोजगार, आई0टी0आई0 नहीं होने से ब्लॉक में कैसे रोजगार उत्पन्न होगा, कैसे सीखेंगे ? माननीय मंत्रीजी कब तक विचार रखते हैं कि ब्लॉक लेवल पर आई0टी0आई0 का कॉलेज खुले ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक स्तर पर अभी आई0टी0आई0 खोलने का सरकार का इरादा नहीं है । हम लोगों ने सभी अनुमंडलों में आई0टी0आई0 को खोल रखा है और माननीय सदस्या ने जिस जगह की चर्चा की है, केवल वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक आई0टी0आई0 निर्माणाधीन है और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्लास कहीं ओर चल रही है तो हम समझते हैं कि 6 किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, यह हमारे क्षेत्र का मामला है.....

श्रीमती शालिनी मिश्रा: महोदय, अभी मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष: अभी माननीय सदस्या पूरक पूछ रही हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, निर्माणाधीन है आई0टी0आई0 लेकिन अभी उसकी पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है जांच करवा लें और पढ़ाई शुरू करवा दें तो कोई दिक्कत नहीं है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: देख लीजिये माननीय मंत्रीजी । आप दोनों में तय करिये कि कौन पहले बोलेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, यह पूर्वी चंपारण का मामला है । हमारे यहां 6 अनुमंडल हैं सिकरहना से लेकर, माननीय मंत्रीजी के जवाब में है कि वहां संचालन हो रहा है तो माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि सिकरहना अनुमंडल में बगही भेलुआ में निर्माण हो रहा है, इसका संचालन किस जगह पर हो रहा है और इसके संचालनकर्त्ता कौन हैं ?

श्री जिवेश कुमार मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सिकरहना की पढ़ाई वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोतिहारी में चालू है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: महोदय, जब सरकार का ये मापदंड है कि प्रत्येक अनुमंडल में खोला जाना है और संचालन होना है तो सिकरहना से 40 किलोमीटर की दूरी पर मोतिहारी है, तो सिकरहना के बच्चे क्या मोतिहारी पढ़ने जाते हैं ? और सिकरहना में कितने बच्चे हैं जो मोतिहारी में नामांकित हैं ?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप अलग से प्रश्न लाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का जवाब जो है उसके आलोक में ही हम बोले हैं । हम मंत्रीजी से चाहेंगे सिकरहना में पढ़ाई कब तक शुरू होगी ?

अध्यक्ष: ठीक है, बैठ जाइये आप । आपका पूरक क्या है ?

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहेंगे कि चकिया में बताया जा रहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है । महोदय, चकिया अनुमंडल है लेकिन चकिया अनुमंडल में अभी उसका कोई अता-पता नहीं है ।

टर्न-6/हेमन्त-धिरेन्द्र/03.03.2021

अध्यक्ष : आपने जवाब नहीं सुना, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि दूसरी जगह पढ़ाई चल रही है ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : सर, चकिया की कहां पढ़ाई चल रही है ? यह हम पूछना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : बता दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया की पढ़ाई वर्तमान में मोतिहारी प्रशिक्षण संस्थान में सुचारू रूप से चल रही है और सिकरहाना...

(व्यवधान)

अब जवाब ले लीजिए । सिकरहाना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भी पढ़ाई वर्तमान समय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी में चल रही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण जब माननीय मंत्री बोलें तो सभी बैठ जायं । पहले बैठ जाइये, मंत्री जी का जवाब सुनिये । माननीय मंत्री जी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया की पढ़ाई और औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकरहाना की पढ़ाई अभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी के परिसर में चल रही है ।

अध्यक्ष : चल रही है । अब बैठ जायं ।

(व्यवधान)

आपके तीन पूरक तो खत्म हो गये हैं ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, जवाब तो मिल नहीं रहा है । अध्यक्ष महोदय, जवाब मिलेगा तब न ।

अध्यक्ष : इतना साफ जवाब इन्होंने दिया ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : हम लोगों ने पूछा कि सिकरहाना में पढ़ाई कब तक शुरू होगी ।

अध्यक्ष : एक मिनट इनका भी सुन लें ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ जो है ओल्डेस्ट सब डिविजन है, अंग्रेज के जमाने का सब डिविजन है वहां अभी तक बाढ़ में आई.टी.आई. क्यों शुरू नहीं हुआ ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : जब माननीय सदस्य बाढ़ का प्रश्न लायेंगे, तो सरकार संतोषपूर्ण उत्तर देगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब ज्ञानू जी, एक मिनट, सभी सदस्य बैठ जाइये । बैठ जाइये ज्ञानू जी ।
जहां से संबंधित प्रश्न है, आप लायेंगे तभी माननीय मंत्री जी उसकी जानकारी प्राप्त करके बतायेंगे और जवाब इन्होंने बड़ा स्पष्ट दिया है । श्रीमती वीणा सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-784(श्रीमती वीणा सिंह, क्षेत्र सं0-129, महनार)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग । श्रीमती वीणा सिंह ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये ।

श्रीमती वीणा सिंह : मैं पूछती हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : और प्रश्न आने दीजिए न, बैठ जाइये । मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महनार बाजार से हसनपुर के बीच......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महनार सुरक्षा बांध और हट्टा बांध अवस्थित है । वस्तुत: यह लघु बांध है । बाढ़ अवधि में गंगा नदी का जल स्तर ऊंचा होने पर पानी का दबाव रहता है, जिसके कारण वेव वॉश से इन लघु बांधों की मिट्टी का क्षरण होता है । इस अवधि में आवश्यकतानुसार मरम्मती एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर इन लघु बांधों को सुरक्षित किया जाता है । साथ ही शहर में पानी फैलने से रोका जाता है । घनी बसावट एवं भूमि अनुपलब्धता के कारण प्रश्नगत सुरक्षा बांध रूपांकन एवं रेखांकन के अनुसार निर्मित नहीं है । साथ ही बांध लगातार नहीं होने के कारण यह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता है,

जिससे बोल्डर पिचिंग कराया जाना तकनीकी रूप से उचित नहीं है । आगामी बाढ़ अवधि के दौरान विशेष चौकसी एवं निगरानी बरतते हुए आवश्यकतानुसार न्यूनतम बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक-1292, दिनांक-25.02.2021 से निदेशित किया गया है ।

अध्यक्ष : श्री अली असरफ सिद्दिकी ।

श्रीमती वीणा सिंह : सर, यह तो वहां की बहुत इम्पोरटेंट समस्या है । पहले जान-माल की हानि होती थी और फसल को नुकसान होता था । अब वहां जान-माल की हानि होती है और लोग बेघर होते हैं । बहुत सारे पानी के कारण वहां परेशानी होती है, बहुत साल से यह समस्या चली आ रही है । मैं चाहती हूं कि वहां बोल्डर पीचिंग करवाने को लेकर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष : निर्देशित किया गया है, अब बैठ जाइये । श्री अली असरफ सिद्दिकी ।

तारांकित प्रश्न सं0-785(श्री अली अशरफ सिद्दिकी, क्षेत्र सं0-158, नाथनगर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-786(श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-20, चिरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्माणाधीन पथ आमागाछी से डीह महुआई पथ के लगभग चैनेज 1500 मीटर पर अवस्थित है, जिसके निर्माण हेतु Techno Feasibility Report समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ? वह पूछिये ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि नेटवर्क में जोड़ने की जो बात है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लिखकर दे दीजिये सब हो जायेगा तो यह नेटवर्क में कब जुड़ेगा, हमलोगों के ग्रामीणों का रोड कब बनेगा ?

अध्यक्ष : इनका पूरक है कि कब जुड़ेगा ? बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब भी स्पष्ट है ...

अध्यक्ष : लेकिन आपने तो प्रश्न किया है कि हहवा नाला पर कब तक पुलिया का निर्माण करने का विचार रखते हैं ? खंड-3 देखिये । एक मिनट, माननीय मंत्री जी आप प्रश्न पढ़िये तो खंड-3 । श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, आप खंड-3 पढ़िये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर....

अध्यक्ष : आप नहीं पढ़िये । बैठिये ।

आप पढ़िये, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी । आप प्रश्न देते हैं और आपको खुद पता नहीं चलता है । आगे से माननीय सदस्यगण अपने प्रश्न को पढ़ कर और उत्तर को देखकर आयें, जिससे कि कम समय में सदस्यों के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लिये जा सकें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें है क्षेत्र सं0-20, चिरैया ....

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, आप ।

तारांकित प्रश्न सं0-787 (श्री विजय कुमार मण्डल, क्षेत्र सं0-210, दिनारा)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय सदस्य, विजय कुमार मण्डल से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-त्र-105(989) खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित है ।

अत: निदेशानुसार प्रासंगिक पत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-105(989) मूल में खान एवं भूतत्व विभाग, पटना को स्थानांतरित किया जाता है ।

अध्यक्ष : स्थानांतरित है ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : इसकी भी एक जानकारी सभा सचिवालय को भेजवा दिया करें कि किस विभाग में स्थानांतरित हुआ ताकि बताया जा सके ।

श्री विजय कुमार मण्डल : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब....

अध्यक्ष : खान एवं भूतत्व विभाग को ट्रांसफर हुआ है । अगली डेट में होगा ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब है ।

अध्यक्ष : एक मिनट, खनन विभाग का जवाब आ गया है । श्री विजय कुमार मण्डल जी आप ले लेंगे ।

श्री विजय कुमार मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी आ गया है ।

अध्यक्ष : तो आपको पूरक पूछना है ?

श्री विजय कुमार मण्डल : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब पूर्णत: निराधार है....

अध्यक्ष : आधार के साथ बताइये, पूरक । पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार मण्डल : अध्यक्ष महोदय, हम चुनौती देते हैं कि क्या उन्होंने जांच करायी है ? सोन नदी को दस जगहों पर बांध कर, उसकी धार को विपरीत दिशा में बहाया जा रहा है और

ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है । हम कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाय ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । इसको ध्यान में ले लीजिये, उन्होंने जांच कराने के लिये सलाह दी है ।

(व्यवधान)

उन्होंने सलाह दी है, पूरक नहीं पूछा है । बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-788 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0-38, झंझारपुर)

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1.05 किमी है । पथ की मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तद्नुसार, इस पर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, अनुरक्षण मद की जो पॉलिसी है, यह सड़क पाँच...

अध्यक्ष : सुन लीजिये, इनका प्रश्न पहले ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, उनको पूरक प्रश्न पूछने दिया जाय । कितना महत्वपूर्ण सवाल है ।

अध्यक्ष : जब आगे बढ़ जाता है, उसके बाद हम पूरक पूछने का अधिकार नहीं दे सकते हैं । बोलिये, श्री नीतीश मिश्रा जी ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहूँगा कि अभी इन्होंने झंझारपुर का जो जिक्र किया कि मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत उसका फिजिबिलिटी और एस्टीमेट बनवा रहे हैं । 5-6 वर्षों से यह सड़क जर्जर स्थिति में है और झंझारपुर स्टेशन का यह पूरा एरिया कॉमर्शियल है । इनकी जो मरम्मत अनुरक्षण पॉलिसी है, तो रिपेयर अभी तक विभाग क्यों नहीं करवा पाया है और जब पॉलिसी वर्ष 2018 की है तो वर्ष 2021 में मुझे इस प्रश्न को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसको जल्द करवा देंगे ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मण्डल (201) एवं श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह वेल में आ गये।)

अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाइये । आप उस समय पूरक नहीं पूछे थे । बैठिये ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

टर्न-7/सुरज-संगीता/03.03.2021

(व्यवधान)

<u>शून्यकाल</u>

श्री महानंद सिंह : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । वेल में बार-बार आना यह उचित नहीं है । प्रश्न को वेल में लेकर आना उचित नहीं है । बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मण्डल(210) एवं श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह अपने-अपने स्थान पर चले गए)

श्री महानंद सिंह : महोदय, अरवल जिला के...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, अभी बहुत लंबा सत्र चलेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पुट कर दिया जाए ।

अध्यक्ष : चलिये । श्री अरूण सिंह ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, मैं पूछ रहा हूं अभी हुआ नहीं है ।

अध्यक्ष : आप नहीं पढ़े हैं तो सदन वेट नहीं करेगा आगे बढ़ता जायेगा । बैठ जाइये अरूण जी । बोलिये जल्दी से । आप वेट मत करिये ।

श्री महानंद सिंह : अरवल जिला के हैबतपुर में करोड़ों रुपये की लागत से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनकर तैयार हो गया है लेकिन अभी तक पठन-पाठन का काम शुरू नहीं हुआ है ।

मैं तत्काल पठन-पाठन का कार्य शुरू कराने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : काराकाट विधान सभान्तर्गत गोड़ारी सकला पथ के पूरब किरहीं गांव अवस्थित है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ा है । गांव के पूरब पुल है । प्रतिवर्ष मिट्टी कटाव होने से पुल ध्वस्त हो सकता है ।

मैं मांग करता हूं कि आवागमन बाधित न हो इसलिए रिटर्निंग वाल का निर्माण कराया जाए ।

श्री रामबली सिंह यादव : जहानाबाद जिलान्तर्गत घोशी, काको मोदनगंज और हुलासगंज प्रखण्ड के किसान-मजदूर लगातार अगलगी के शिकार होते रहे हैं । पानी की किल्लत और अग्निशामक दस्ता दूरी पर होने के कारण बचाव संभव नहीं हो पाता । सरकार से मांग है कि चारों प्रखण्ड में बड़ी गाड़ीयुक्त अग्निशामक केंद्र स्थापित किया जाए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : वैश्य समाज के कसेरा जाति घुमघुम कर मजदूरी करती है । अभी कसेरा जाति पिछड़ी जाति के अंतर्गत है । उसकी सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति लगभग शून्य है । कसेरा जाति अतिपिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने की सभी अर्हताएं पूरी करती है ।

अत: कसेरा को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाय ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक-28.02.2021 को सीतामढ़ी के पुपरी थाना के बगदे में पथिक लूट के शिकार हो गए, सीतामढ़ी में अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं । सीतामढ़ी जिले में हो रहे अपराध पर नियंत्रण हेतु ए.एस.पी (अभियान) की पूर्व की तरह नियुक्ति की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखण्ड में वर्ष 2017 से जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत 6 हजार लाभुकों को राशि नहीं दी गई । इसी तरह का मामला अन्य प्रखण्डों का भी है ।

अत: अविलंब पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत जननी बाल सुरक्षा मद की देय राशि का भुगतान किया जाय ।

श्री शाहनवाज : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखण्ड के ग्राम-बलवा के मो0 अशरफ अली, पिता-मो0 बसी अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से दिनांक-23.02.2021 शाम से लापता हैं ।

अत: मैं सदन से उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : महोदय, दिनांक-25.02.2021 को पटना जिला के बिक्रम थाना अंतर्गत ग्राम-खोरैठा की फूलवंती देवी, पति-श्री रघुवर वर्मा को बिना किसी वजह के पुलिस प्रशासन के अधिकारी द्वारा घर में घुसकर लाठी से बहुत ही बेरहमी से पीटा गया ।

अत: पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ दोषी पुलिस पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई करने का मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में बिना कोरोना जांच किए, वोटर लिस्ट एवं पुराने ओ0पी0डी0 रजिस्टर से वेबसाइट पर नाम अंकित किया गया है । उसमें 50 प्रतिशत नामों का मोबाईल नंबर पता गलत है जिसका आजतक सत्यापन नहीं किया गया । जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई की जाये।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मलाही एवं पहाड़पुर प्रखंड अन्तर्गत पकड़िया एवं पश्चिमी सरैया में डॉक्टर एवं नर्स की स्थायी प्रतिनियुक्ति करने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगॉव प्रखंड के अंतीचक पंचायत में प्रस्तावित बिक्रमशीला केन्द्रीय विश्वविद्यालय का जल्द भूमि अधिग्रहण कर निर्माण कार्य पूरा किया जाय ताकि देश विदेश में यह धरोहर शिक्षा के क्षेत्र में पुन: अपनी पहचान स्थापित कर सके ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर, मोरवा एवं पटोरी प्रखंड के किसानों को नीलगायों के द्वारा फसल की भारी बर्बादी एवं क्षति हो रही है । सरकार से मांग करता हूं कि इसका अविलंब रोकथाम एवं पीड़ित किसान भाइयों को उचित मुआवजा मिले ।

अध्यक्ष : श्रीमती भागीरथी देवी, श्रीमती भागीरथी देवी । नहीं हैं ।

(अनुपस्थित)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य में ग्राम रक्षा दल सभी जिला में रात्रि प्रहरी का काम कर रही है । युवा वर्ग स्वयंसेवक के रूप में इस कार्य में लगे हुए हैं । सुरक्षा को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी की दर से इन्हें मानदेय भुगतान करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जिला-पूर्वीचम्पारण के प्रखंड कल्याणपुर में चकिया-केसरिया पी०डब्लू०डी० पथ में पकड़ी दीक्षित पंचायत के चैनपुर अनुसूचित जाति

के भूमिहीन परिवार चालीस वर्षों से सड़क के किनारे अपने घर बनाकर जीवन बसर करते हैं, इधर इन परिवारों के सामने विस्थापन की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त परिवारों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराकर आवासित किया जाय ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के घूरणा बाजार से सटे सीमा सुरक्षा रोड से घूरना ओ०पी० के पास नेपाल सीमा तक का रोड 2008 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त होकर नाला के रूप में तब्दील हो गया है ।

उक्त रोड को बनवाने की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड में ग्राम सिरिस और फतेहपुर के बीच पुनपुन नदी पर पुल नहीं होने के कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है । मैं सरकार से इस पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में मुख्यमंत्री नल-जल योजना में वार्ड सचिव को अनुरक्षक रखने में प्राथमिकता देने के विभागीय निर्देश को दरकिनार कर सैकड़ों जगह अन्य लोगों को अनुरक्षक रखा गया है ।

मैं राज्य सरकार से वार्ड सचिव को अनुरक्षक के रूप में रखने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जल्दी-जल्दी अपनी सूचनाएं पढ़ें । आज 56 शून्यकाल की सूचनाएं हैं, इसीलिए छूटेगा तो आप ही लोगों का छूटेगा ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला में दिनांक 24.02.2021 को उचकागांव में गैस एजेंसी के 03 कर्मियों को लूटपाट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर लुटेरे भाग निकले ।

अतएव उक्त घटना से सबंधित अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करते हुए घायलों को 5-5 लाख रुपये सरकारी सहायता देने की मांग करता हूं ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के सदर प्रखंड (बक्सर नगर) में स्थित बिहार का सबसे पुराना लाईट एंड साउंड वर्षों से बंद पड़ा है । मैं सदन

के माध्यम से मांग करता हूं कि बंद पड़े लाईट एंड साउंड को अविलंब चालू कराया जाय ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2019 में लगभग 6,379 कनीय अभियंता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उपबोधन प्रक्रिया के बाद भी मेरिट लिस्ट नहीं आई है ।

अत: उक्त आयोजित परीक्षा के परीक्षाफल अतिशीघ्र प्रकाशित करने की मांग करता हूं ।

टर्न-8/ मुकुल-राहुल/03.03.2021

श्री कुमार शैलेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में बैकठपुर के दूधैला पंचायत के कसमाबाद गांव में कल दिनांक-02.03.2021 को दिन के 11.00 बजे अचानक भीषण आग लग गई । जिसकी वजह से लगभग चार सौ घर जल कर राख हो गया है ।

अत: सरकार से पीड़ित परिवार को अविलंब राहत दिलवाने की मांग करता हूं । महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले । अति पिछड़ा का गांव है, नारायणपुर प्रखंड से 70 किलोमीटर दूर है और नाथनगर 5 किलोमीटर दूर है । इसलिए सरकार संज्ञान ले ।

अध्यक्ष: आपदा अति पिछड़ा और पिछड़ा नहीं देखती है । आपदा, आपदा है सरकार इसको संज्ञान में लेगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, 2015 की रिक्ति के अनुसार 4257+2 अतिथिशिक्षकों को आरक्षण के नियमानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारियों के अनुमोदनोपरांत, शिक्षा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-51/25.01.2018 के विज्ञापन द्वारा जुलाई 2018 में नियुक्त किया गया है । मैं अपील करता हूं कि उक्त शिक्षकों की दक्षता परीक्षा लेकर 60 वर्षों तक के लिए नियमित किया जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के अधिकतम पंचायतों के हजारों महादलित परिवार सरकार द्वारा तीन डिसमील जमीन अबतक उपलब्ध नहीं कराये जाने से आवास एवं शौचालय योजना से वंचित हैं । उन सभी परिवारों को जमीन दिलाकर आवास एव शौचालय योजना दिलाने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव: महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में सितम्बर, 2020 में असामयिक वर्षा से खरीफ फसल क्षति हुई जिसका प्रतिवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रानीगंज द्वारा ससमय किया गया लेकिन फसल क्षति की राशि निर्गत नहीं की गई ।

अत: किसानों को फसल क्षति की राशि निर्गत करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सुधाकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत आदापुर थानाध्यक्ष द्वारा पुलिसिया जुल्म उजागर करने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा आंदोलन तथा प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि आंदोलन बंद करो अन्यथा प्राथमिकी दर्ज की जायेगी । घटना की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें ।

श्री आनन्द शंकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बेला ग्राम-पंचायत के जरमा खाप ग्राम में अदरी नहर पर वृहतपुलिया नहीं होने के कारण चार पहिया वाहनों का परिचालन नहीं हो पाता है । जिससे ग्रामीणों को विभिन्न कार्यक्रमों, आपातकालीन स्थितियों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: सरकार से निवेदन है कि उक्त पुलिया का निर्माण जल्द कराये ।

डॉ0 मुरारी मोहन झा: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के राजोड़ा पंचायत में सगुना नदी के दरोगा बांध पर यदि पुल बना दिया जाय तो यहां एवं बिस्फी प्रखंड से मधुबनी जिला मुख्यालय की दूरी बहुत कम हो जायेगी । इस जन उपयोगी योजना को धरातल पर अविलंब उतारकर सरकारी निर्णय को पूरा किया जाय ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला सहित राज्य में लगभग तीन लाख ग्रामरक्षादल के जवान पंचायती राज के अधीन सरकारी योजनाओं, सामाजिक, धार्मिक उत्सवों में सुरक्षा सेवा देते हैं । परंतु, इन्हें मानदेय या सहयोग राशि नहीं मिलती है ।

अत: मैं सरकार से ग्रामरक्षादल के सराहनीय कार्य हेतु इन्हें मानदेय तथा वर्दी भत्ता देने की मांग करता हूं । अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है सरकार इसे संज्ञान ले ।

श्री कृष्णनंदन पासवान: अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री कॉलेज नहीं है, यहां के लड़के और लड़कियां डिग्री हासिल करने 25-30 किलोमीटर की दूरी तय कर मोतिहारी, अरेराज जाने को मजबूर हैं जिससे आर्थिक, मानसिक ह्रास होता है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि हरसिद्धि में डिग्री कॉलेज स्थापित कराया जाय ।

श्री अजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली थाना के बहादुरपुर निवासी श्री राम कुमार अरुणाचल प्रदेश के जिला च्यांगलांग स्थित क्यूपीसी ऑयल एंड गैस कम्पनी में कार्यरत थे, जिन्हें 21 दिसम्बर, 2020 को अल्फा उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया, जिनका अभी तक पता नहीं है ।

मैं सरकार से श्री कुमार के सकुशल रिहाई कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार । आपकी सूचना सबसे संक्षिप्त है मात्र 21 शब्दों में है आपको धन्यवाद ।

श्री विजय कुमार: थैंक्यू सर, शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड के महुली बाजार में आवागमन को सुगम बनाने हेतु पथ के दोनों तरफ जनहित में नाला का अविलंब निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला नगर थाना वैशाली में दिनांक–20.12.2019 को राकेश कुमार यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है । पुलिस प्रशासन निष्क्रिय एवं मूकदर्शक बनी है ।

अतएव, नगर थाना कांड संख्या 1144/19 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने एवं पुलिस प्रशासन की भूमिका की जांच कराई जाय ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद: महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर में विगत वर्ष बाढ़ से 42 पंचायतों के लाखों जन–जीवन सहित फसलों की क्षति हुई परंतु आपदा राहत मात्र 88411 व्यक्ति को दिया गया । अभी छूटे हुए लाखों परिवारों को निर्धारित आपदा राहत की स्वीकृति आपेक्षित है ।

अध्यक्ष: श्री भूदेव चौधरी, आपका शून्यकाल 24 शब्दों का है, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री भूदेव चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखंड में चलना मोड़ से भेलाई पहाड़ी तक लगभग 09 कि0मी0 जर्जर सड़क को जनहित में पी0सी0सी0 का निर्माण अविलंब कराया जाय ।

श्री मिश्री लाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के तारड़ीह प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुर्सो मछैता का पंचायत सरकार भवन कई महीनों से बन कर तैयार है । पंचायत को सुपूर्द नहीं किया गया है ।

अत: पंचायत सरकार भवन पंचायत को सुपूर्द करने तथा नहीं करने के विरूद्ध कार्रवाई हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, 1948 में बने पी0पी0 एक्ट के बावजूद आज तक बिहार में 50 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को जिस जमीन पर वे बसे हैं, उसका मालिकाना हक नहीं मिला है उलटे बेदखली हो रही है । आज की स्थिति में शहर–देहात के लिए एक समेकित आवास कानून बनाने की मांग करता हूं ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी: अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत रहमतपाड़ा शांहनगरा वाली सड़क में कजलामोनी सराय के बीच मुर्गीगेदी जगह उच्चस्तरीय सी0सी0 पुल निर्माण कार्य को संवदेक ने बीच में ही बंद कर दिया है ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि विभागीय जांच कराकर लंबित कार्य को पुन: प्रारम्भ करवाया जाय ।

श्री विनय कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, श्रीमती कमल देवी W/o पूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्व0 शोभानन्द झा, ग्राम/पोस्ट– नारायणपट्टी, राजनगर, जिला–मधुबनी को राज्य सरकार द्वारा

स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली पेंशन मार्च 2017 से नहीं मिल रही है जिसका भुगतान किया जाय ।

श्री सुदामा प्रसादः अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के तरारी प्रखण्ड के सिकरहटा खुर्द में 02.11.2018 को अमन कुमार, पिता-राम कुमार पासवान की चाट में भैंस धोते समय ट्रक पलट जाने से मृत्यु हो गई व तीन अन्य घायल हो गए । मृतक के परिजन को 4 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य में विद्यालय प्रबंध समिति गठित किये सभी प्रधानाध्यापक रात्रि प्रहरी की बहाली बिना प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष (स्थानीय विधायक) की सहमति, से कर रहे हैं । जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय घूंसी (उर्दू) मनीगाछी दरभंगा में बहाली । अतः ऐसे दोषी प्रधानाध्यापक पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाने की मांग करता हूं । हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से शिक्षा मंत्री का भी कल बयान आया था और बार-बार बयान आ रहा है उसके बाद शिक्षा मंत्री का, सदन की अवमानना है, विभाग के मंत्री की अवमानना है । महोदय, सरकार इसको संज्ञान में ले ।

अध्यक्षः ठीक है, हम दिखवा लेंगे । माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले भी हैं कि हम पत्र भेजेंगे । माननीय सदस्य श्री संजय कुमार गुप्ता ।

(अनुपस्थित)

श्री शम्भु नाथ यादवः महोदय, बक्सर जिला के सेमरी प्रखण्ड के केशोपुर पंचायत के ग्राम-मानीकपुर में दिनांक-18.06.2020 को आकाशीय बिजली गिरने से रामजी यादव की मृत्यु हो गई थी, सरकार द्वारा मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया, पर आज तक नहीं मिला है । सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलावें ।

टर्न-9/यानपति-अंजली/03.03.2021

श्री युसुफ सलाहउद्दीनः अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कडड्डमर घाट एवं सलखुआ प्रखंड के डेंगराही घाट पर पुल का निर्माण नहीं होने से लाखों लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं ।

अतः सरकार से जनहित में उक्त घाटों पर पुल के निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत, प्रखण्ड रतनी, फरीदपुर पंचायत रतनी, ग्राम रकसिया निवासी अजीत कुमार पिता सुरेश सिंह एवं सुरेश सिंह पिता रंजीत सिंह का निधन 11 हजार विद्युत स्पर्शघात से दिनांक 17.10.2017

को हो गयी थी मृतक पिता-पुत्र एवं भूमिहीन हैं, परिवार का भरण पोषण इन्हीं के माध्यम से होता था । आश्रित को मुआवजे की मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, 'रोहतास जिला के करवंदिया में वर्ष 2010 से क्रशर मशीन को बंद करने से 50000 मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं, जबकि राज्य के अन्य जिलों में क्रशर मशीन एवं पत्थर उद्योग चालू है; सरकार क्रशर मशीन एवं पत्थर उद्योग चालू कर मजदूरों को रोजगार दिलावें ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, सारण जिलांतर्गत छपरा आरा पुल पर प्रत्येक दिन जाम की स्थिति बनी रहती है दिनांक 25.02.2021 को आरा पुल पर 06 कि0मी0 की दूरी 8 घंटे में तय की जा रही है ।

अत: उक्त पुल पर जाम से मुक्ति हेतु मैं सूचना देता हूं ।

श्री राम विशुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है । जगदीशपुर से आरा की दूरी 40 कि0मी0 है, जहां बच्चे/बच्चियों को पठन-पाठन करने हेतु जाना पड़ता है ।

अतएव जगदीशपुर अनुमण्डल में एक डिग्री कॉलेज खोलने की मांग सदन से करता हूं ।

सुश्री श्रेयशी सिंह: अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च, 2015 के बाद बहाल शिक्षकों का वेतन स्थगित होने से इनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है ।

अत: बिहार के अन्य सभी जिलों की तरह जमुई में भी 31 मार्च, 2015 के बाद बहाल शिक्षकों के स्थगित वेतन को उच्च न्यायालय के आदेशोपरांत चालू करने की मांग करती हूं ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के लौरिया प्रखंड स्थित बरवांकाला, बंगाली शरणार्थी कालोनी मटियरिया, बघलोचना, वृति मटियरिया, बेलवा टोला बसंतपुर योगापट्टी प्रखंड स्थित- जरलपुर, मंगलपुर, चौमुखा, बाढ़ के कटाव से विस्थापित हो सकता है ।

अत: बाढ़ पूर्व कटाव अवरोधी कार्य करवाने हेतु सरकार से आग्रह करता हूं ।

श्री विनय कुमार: अध्यक्ष महोदय, गया जिला के बोधगया दुमुंहाना से चेरकी, दरीयापुर, बैजूधाम होते हुए गुरूवा सड़क का चौड़ीकरण शीघ्र करवाया जाय । चूंकि वाराणसी से औरंगाबाद होते हुए बोधगया जाने के दौरान एन0एच0-2 जाम रहने के कारण पर्यटकों के अलावे रात्रि में आपातकालीन सेवा एंबुलेंस वाहनों का भी मगध मेडिकल कॉलेज, गया इलाज हेतु जाने का सुगम मार्ग है ।

अध्यक्ष: श्री रत्नेश सादा ।

(अनुपस्थित)

श्री संदीप सौरभ: अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के पालीगंज और दुल्हिन बाजार प्रखण्ड में स्थित सभी नहरों की हालत जर्जर है, पानी अंतिम छोर तक नहीं जा पाती है जिसके कारण किसानों को सिंचाई में भारी दिक्कत होती है । इन सभी नहरों की उड़ाही और पक्कीकरण कराने की मांग सदन के सामने रखता हूं ।

अध्यक्ष: श्री अजीत कुमार सिंह ।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: शून्यकाल समाप्त हुआ । भागीरथी देवी जी, बोल दीजिये । बोलिये आप ।

( इस अवसर पर भा0क0पा0 माले के कुछ माननीय सदस्यगण, बोलते हुये वेल में आ गये)

श्रीमती भागीरथी देवी: अध्यक्ष जी, आज राम नगर क्षेत्र में हुजूर हमारे यहां रामनगर हॉस्पिटल में जो दवा है, सरकार हमलोगों को दवा देते हुए, उनलोगों का जो ठेकेदार है मैनेजर दवा वाला, वह अलग से दवा मंगाकर और हॉस्पिटल में रखकर और दुगुना वह लोग बना रहा है हुजूर और जब बाहर से दवा मंगाते हैं लोग तो उसका कोटिशन मंगाया जाय और उसकी जांच कराई जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जायेगी ।

सूचना पढ़ी जा चुकी है । सरकार का उत्तर, माननीय मंत्री, पंचायती राज ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री पवन कुमार जायसवाल, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से

वक्तव्य

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, विभागीय आदेश संख्या-14, दिनांक-16.06.2020 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली टायड और अनटायड अनुदान की कुल संख्या- 5 हजार 18 करोड़ रुपये मात्र की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच क्रमश: 70:20:10 के अनुपात में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस योजना के कार्यान्वयन एवं राशि के व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संसूचित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार द्वारा अनुदान की राशि की किश्त दी गई है । 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की कुल 5 हजार 18 करोड़ रुपये मात्र में से 3663 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ

है । जिसे भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से संबंधित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के बैंक खातों में अंतरित कर दी गई है । पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अब तक उपलब्ध कराई गई अनुदान की राशि को पी0एफ0एम0एस0 इंटरफेंस के माध्यम से डी0एस0सी0 के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाना अनिवार्य शर्त निर्धारित है । इस शर्त के अनुपालन किये जाने के उपरांत ही पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आगामी किश्त की राशि वितरित की जा सकेगी । अत: पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त होने वाली अनुशंसा के अनुदान की किश्तों की राशि के अभियुक्त हेतु निर्धारित बिंदु शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है लेकिन माननीय सदस्य ने यह आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय कि पुरानी प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाय तो हम एक पत्र भारत सरकार से अनुमति मांग रहे हैं पत्र देकर कि पुरानी प्रक्रिया क्योंकि हम भी देख रहे हैं खर्चा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है कि पुरानी प्रक्रिया से इसको किया जाये तो हम एक पत्र भेजकर भारत सरकार से इसकी अनुमति मांगता हूं।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सुन लीजिए । कल राजस्व की मांग पर आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा । अभी बैठ जाइये । यह भी जनहित से जुड़ा मुद्दा है । आप बैठ जाइये कल तो आपको मौका मिलेगा राजस्व की मांग पर आप अपनी बात रखेंगे । बैठ जाइये। चलिये पूरक ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो बिहार विधान सभा के इतिहास में पहली बार इतना शून्यकाल लेने के लिए आपको सदन की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं हमलोग और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को जो पैसा गया 5 हजार 18 करोड़ ये 28 मार्च तक राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है । मेरा यह कहना है कि जब भारत सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से यह कहा है कि एक अप्रील से पूर्णत: इसको लागू किया जाना है तो माननीय मंत्री जी विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा क्या राज्य के सभी डी0डी0सी0 को, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से 31 मार्च तक पुरानी व्यवस्था से लागू करने का आदेश नहीं दे सकते हैं जब भारत सरकार कह रही है चूंकि ये राशि...

अध्यक्ष: आप सुझाव दे रहे हैं या पूरक पूछ रहे हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: नहीं, पूरक पूछ रहे हैं । 31 मार्च तक पुरानी व्यवस्था से राशि खर्च करने के लिए भारत सरकार की तर्ज पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आदेश निर्गत करा दिया जाय, मंत्री जी क्या इस पर विचार रखते हैं ।

अध्यक्ष: निर्गत कराना चाहते हैं ?

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: जरूर खर्चा कराना चाहते हैं क्योंकि पंचायती राज विभाग खर्चा कराना चाहती है । हम एक पत्र भारत सरकार को भेजकर और जो माननीय सदस्य ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से यह आग्रह किया जाय तो हमलोग करेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में यह कहा गया है कि एक अप्रील से इसको पूर्णतः लागू किया जाना है तो क्या इस राज्य में यह व्यवस्था 31 मार्च के लिए स्थगित नहीं हो सकती है । मंत्री जी से हम चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से तत्काल इस राशि को...

अध्यक्ष: जवाब दे दिया गया है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, 5 हजार 18 करोड़ रुपया का मामला है । पंचायती राज का चुनाव होना है । पुराने जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं । यह सदन का भी फर्ज बनता है । आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि इस राशि को पुरानी व्यवस्था से 31 मार्च तक खर्च करने के लिए भारत सरकार की तर्ज पर माननीय मंत्री जी आदेश देने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत करेंगे । एक पत्र भी भेजेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसको भी करेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय सदस्य डॉ0 संजीव कुमार अपनी सूचना पढ़ें ।

टर्न-10/सत्येन्द्र/03-03-21

डॉ0 संजीव कुमार, श्री राजेश कुमार सिंह एवं अन्य तेरह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य

---

डॉ0 संजीव कुमार: अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने पिछले 6 वर्षों से टोपो लैंड की बंदोबस्ती और खरीद बिक्री पर रोक लगा रखी है जिस कारण गैरमजरूआ जमीन का रसीद नहीं काटा जा रहा है। जो किसान या उनके पूर्वज 70 साल से उक्त जमीन पर निवास और खेती कर रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित लगान दे रहे थे उन किसानों को काफी कठिनाईयों

का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में बिहार के पटना, सारण, लखीसराय, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, गोपालगंज, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण जिला में टोपो लैंड अवस्थित है।

अत: लाखों किसानों के हित के लिए पूर्व की भांति जिन किसानों के पास जमीन का रसीद है उनके लिए सरकार द्वारा लगान निर्धारित करने तथा टोपो लैंड की बंदोबस्ती एवं खरीद-बिक्री पुन: आरम्भ करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

एक मिनट । माननीय सदस्यगण, ये भी जमीन का मामला है । आप गरीब के हित की बात कर रहे हैं तो अपने स्थान पर बैठें और इनका जवाब सुनें । आप जाईए, गरीब की हित की बात करते हैं, गरीब से जुड़ा हुआ यह मामला है । आपलोग सुनिये अपने स्थान पर जाकर । बोलिये माननीय मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

श्री राम सूरत कुमार,मंत्री: सर, ये लोग गरीब के दुश्मन हैं..

अध्यक्ष: आपलोग अपने अपने स्थान पर जाईए ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(माले)के माननीय सदस्यगण अपनी अपनी सीट पर वापस लौटे)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये लोग दोस्त नहीं हैं गरीब के। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि असर्वेक्षित भूमि के स्वामित्व एवं अधिकार के संबंध में विभाग के स्तर से विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है । विधि विभाग के द्वारा अपने परामर्श में न्यायालय के एक विनियमन का उल्लेख किया गया है जो Privy Council in the matter of Tarakdas Acharajee Choudhary Vrs. Secretary of State Reported in AIR 1935 P.C.125 से संबंधित है, जिसमें निम्न आदेश अंकित किये गये हैं:-

" …….. It is beyond question that the bed of a public Navigable river and river Ganges undoubtedly belongs to that Category, Is presumed to be the property of the Government, and not that of a private person." माननीय महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी अपनी राय में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है। इस प्रकार की भूमि को सरकार के दखल एवं स्वामित्व में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

उक्त के आलोक में असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैंड पर अग्रतर नीति निर्धारण संगत पक्षों से अभिमत प्राप्त कर की जायेगी । तत्सम्मत कार्रवाई सम्प्रति विचाराधीन है।

डॉ0 संजीव कुमार: अध्यक्ष महोदय, पूरक है, पूछना है मुझे ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

डॉ0 संजीव कुमार: महबूब साहव, आपलोग हल्ला करने के लिए खाली आये हैं क्या, सुनिये, ऐसे डिस्टर्व करते रहते हैं आपलोग एकदम । महोदय..

अध्यक्ष: आप इधर देखिये, आपस में बात मत करिये ।

डॉ0 संजीव कुमार: डिस्टर्बिंग ऐलीमेंट हैं ये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि असर्वेक्षित जमीन वह टोपो लैंड है महोदय जो झार झंकार था 1901 के सर्वेक्षण में, अंग्रजों द्वारा सर्वेक्षण नहीं हो पाया था वैसा जमीन जो नदी के किनारे था और जो नदी के धार बदलने से वहां के लोकल जो किसान थे, किसान सब जितने थे वह सब मिलकर के अपना मेहनत कर के उस जमीन को फसल के योग्य बनाये और आजादी के बाद जब सरकार का गठन हुआ तो बिहार सरकार ने उनका लगान निर्धारित किया और तब से उनको स्वामित्व का प्रभार मिला । मेरा ये कहना है कि खरीद और बिक्री का भी उनको राईट था..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये।

डॉ0 संजीव कुमार: मैं पूरक ही पूछ रहा हूॅ माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि आप इसके लिए एक कमिटी बनायें और टाल मटोल नहीं करें । मेरा सरकार से यही कहना है कि अगर टालमटोल किया जायेगा तो फिर ...

अध्यक्ष: आप सुझाव दे रहे हैं या पूरक पूछेंगे ?

डॉ0 संजीव कुमार: दोनों चीज मैं पूछ रहा हूॅ कि आप कबतक उसका बतायेंगे पिछले तीन साल पहले भी...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री,कबतक कमिटी बनाकर समाधान करेंगे वह बतलाईए?

डॉ0 संजीव कुमार: मेरा सिर्फ कहना है जिनके पास रसीद है,कोई भी प्रुफ है जमीन का, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हमलोग जो विधायक बने हैं किसान के प्रवक्ता हैं, जनता के प्रवक्ता हैं तो हमें उनलोगों ने जीताकर भेजा है प्रवक्ता के रूप में अपनी बातों को रखने के लिए ।

अध्यक्ष: बताईए,माननीय मंत्री जी।

ये गंभीर पूरे बिहार के अन्दर का मामला है इसके समाधान के लिए सरकार क्या विचार रखती है और कबतक, यही न पूरक है?

डॉ0 संजीव कुमार: जी, यही है।

श्री राम सूरत कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट वक्तव्य देना चाहता हूॅं और साथियों से आग्रह करना चाहता हूॅं, मेरी बात को सुने और कल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी वक्तव्य आने वाला है और बतलायेंगे भी आपलोगों को, अगर आप जनता के हित खासकर के विपक्षी भाई को बताना चाहेंगे कि अगर आप उनके दोस्त है...

अध्यक्ष: आप इधर देखिये आसन की ओर।

(व्यवधान)

आप उनके चक्कर में न पड़े, आसन की ओर देखें।

(व्यवधान)

श्री राम सूरत कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: इतना इम्पोंटेंट विषय है, आप बैठ जाईए । इस इम्पोंटेंट विषय पर आप गंभीरता से सुनें।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, टोपो लैंड और सर्वेक्षित भूमि के अधीन चौर, दियारा, गंगबरार तथा वन भूमि भी है। टोपो लैंड पर मालिकाना हक एवं अधिकार बिन्दु पर विभाग स्तर पर एक कमिटी का गठन किया गया है। कमिटी के तौर पर तैयार किये गये ड्राफ्ट पौलिसी पर जल संसाधन विभाग तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अभिमत प्राप्त हुआ है। उक्त दोनों विभाग से प्राप्त अभिमत तथा एतद् संबंधी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा सदृश मामलों में पारित आदेश की समीक्षा विभाग स्तर पर की जा रही है। विभाग के स्तर पर समीक्षोपरांत अंतिम रूप से टोपो लैंड पर विभागीय अभिमत का गठन किया जायेगा, तदोपरांत विधि एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 70 वर्ष का मामला नहीं है, यह उससे भी पुराना मामला है क्योंकि 100 वर्ष के पहले का भी मामला है और नदी, चौर होने के कारण उस समय विभाग के द्वारा और सदस्य के द्वारा जो कहा गया है तो निश्चित रूप से सरकार चिन्तित है और सरकार इस पर काम करना चाहती है इसलिए कमिटी का गठन भी किया है जो मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, टोपो लैंड और सर्वेक्षित भूमि के सर्वेक्षण, भूमि के रैयतीकरण के संबंध में नीति निर्धारण, प्रारूप गठन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 443-8 रा0, दिनांक 24-7-2019 के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति एवं अन्यत्र स्थानांतरण के कारण नये सिरे से समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन बिहार सचिव सह अध्यक्ष होंगे। श्री कंचन कपूर, सदस्य सचिव होंगे, श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव सदस्य होंगे, श्री मुकूल कुमार, उप

सचिव सदस्य होंगे, श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू-अर्जन सदस्य होंगे, श्री सुवोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे एवं समिति द्वारा नीति निर्धारण प्रारूप गठन में आवश्यकतानुसार किसी विशेष आमंत्रित सदस्य की सेवा ली जायेगी। तीसरा समिति द्वारा आवश्यकतानुसार राजस्व मामलों के विशेषज्ञ किसी सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी अथवा किसी वरीय अधिवक्ता सेवा प्रारूप गठन में लिया जायेगा। यह समिति इस विषय पर जल संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर से प्राप्त अभिमत पर विचार करते हुए नीति प्रारूप का गठन कर अपर मुख्य सचिव के समक्ष दिनांक 19-3-21 तक उपस्थापित करेगा। इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा कि यह पूरे बिहार का गंभीर मामला है। माननीय हमारे साथी 14 जिला का मामला उठाये हैं जिसमें से 10 जिला का हमारे पास रेकर्ड है जिस पर हमलोग संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे।

श्री पवन कुमार यादव: महोदय, जबतक निर्णय नहीं हो जाता, 6 वर्ष पहले की तरह दखल खारीज और रसीद काटने का आदेश दिया जाय और आगे जो समिति का निर्णय होगा उसको मान्य होगा।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: जबतक जांच होकर के नहीं आता है क्योंकि इसमें बहुत सारा समस्या आयेगा कि किनके पास दखल कब्जा है किनके पास नहीं है तो यह जबतक कमिटी जांच कर नहीं बतलायेगी, तबतक इस पर कोई आदेश निर्गत नहीं किया जा सकता।

डॉ0 संजीव कुमार: अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि इसमें समय निर्धारित किया जाय। कमिटी का निर्णय आने में काफी लेट हो जायेगा इसलिए कमिटी का समय निर्धारित किया जाय जांच रिपोर्ट के लिए ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: हुजूर, ये कोई 10-20 बीघा, 10-20 एकड़ का सवाल नहीं है। बिहार में लगभग जहां से गंगा शुरू होती है और जहां समाप्त होता है वहां तक के लाखों हेक्टेयर जमीन का मामला है तो 2-4 दिन का मामला यह नहीं है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जल्द ही इसका..

अध्यक्ष: अगले वित्तीय वर्ष तक है संभव?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: जांच शुरू करवा देंगे, यह संभव है हुजूर ।

श्री देवश कान्त सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कहना यह है कि दाखिल खारीज हो चाहे नहीं हो, रसीद कटता रहेगा, एल0पी0सी0 मिलता रहेगा तो किसान को जो लाभ मिल रहा है जो उससे अवरूद्ध हो गया है, कम से कम वह तो चालू रहे । जब आपका रिपोर्ट आयेगा, आप बंद करवा दीजियेगा। वर्त्तमान में किसान को जो लाभ मिलना है सरकार के

रसीद और एल0सी0पी0 के आधार पर, वह जबतक खेती कर रहा है तो उसको वह सुविधा मिले ।

टर्न-11/मधुप/03.03.2021

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : एल0पी0सी0 और रसीद उसी को मिलता है जिसका जमाबंदी कायम रहता है । किसी कारण से उसको रोक दिया गया है । इसको जॉचोपरांत ही हम इस कार्रवाई को शुरू करेंगे । अगर विशेष कुछ व्यवस्था बनेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि जनता के हित में निर्णय लिया जाय ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, 100 साल से जिसका रसीद कट रहा था, आज भी 2-3 साल मात्र से रसीद नहीं कट रहा है, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ उसका रसीद कटवाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें । आज किसी के बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बाप का श्राद्ध नहीं हो पा रहा है, किसी को सरकारी लाभ मिलता था वह लाभ नहीं मिल रहा है । माननीय मंत्री जी उसको रखें, उसकी व्यवस्था करवायें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, हमारी बात को पंकज जी ने नहीं सुना, मैंने कहा है कि नियम-संगत अगर उचित होगा तो उसपर विचार करके कार्रवाई किया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी लोग नहीं पूछ सकते हैं । जिनका हस्ताक्षर इसमें है, वही पूछेंगे । राज कुमार जी, एक मिनट बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कहलगॉव विधान सभा क्षेत्र और पीरपैंती में इस तरह का बहुत ही ज्यादा जमीन है, इसपर अविलम्ब दिखवाया जाय क्योंकि रोज खून-खराबा हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप बोल चुके । बैठिए । महबूब जी, आपका हस्ताक्षर नहीं है फिर भी...

श्री महबूब आलम : महोदय, 50 लाख गरीबों को उजाड़ने का सरकार ने नोटिस दिया है और अभी जो मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे, 1948 में जो पी0पी0एस0टी0 ऐक्ट बनी है, उस ऐक्ट को दरकिनार करके 50 लाख भूमिहीन गरीबों को उसके घर-द्वार से उजाड़ने की नोटिस दी गई है.....

अध्यक्ष : अब आप विषय से विषयांतर होकर बोल रहे हैं ।

माननीय मंत्री जी, यह मामला काफी गंभीर है । रसीद कब से कटना बंद हुआ है ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : जो मुझे जानकारी है, विगत 5-6 वर्ष के पहले से यह बंद है और मैंने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि जबतक जॉच नहीं होती है तबतक नहीं होना है लेकिन फिर भी किसानों के हित में हमलोग काम करते हैं, गरीबों के हित में काम करते हैं । बीच में ऐसा कोई..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिए ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : उसके तहत अगर कोई प्रावधान व्यवस्था बनती है तो हम बात करके उच्चस्तरीय कमिटी बनाकर जॉच कराकर हम चालू करने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : किसानों के हित में लघु और मध्यम वर्गीय किसानों का ज्यादातर मामला इसके अन्तर्गत आता है, वे कृषि कार्य करते रहे हैं, सरकार के अनुदान का लाभ मिले, वह गरीब आगे उसमें खेती-बाड़ी करे, इसको ध्यान में रखकर आप अगले वित्तीय वर्ष कोई निर्णय पर पहुँचें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : सभी लोग उसपर कृषि कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है ।

सर्वश्री कुंदन कुमार, सूर्यकान्त पासवान एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [पर्यटन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेगुसराय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का मौका दिया है । महोदय, बेगुसराय पूरे विश्व में तीन चीजों के लिए जाना जाता है ।

अध्यक्ष : आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है । पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके कारकों को सुरक्षित रखा जाना है, जिसमें झील, वन्य प्राणी, पक्षी आदि हैं । इसी तरह की एक विश्व प्रसिद्ध झील बेगुसराय जिले में है । बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा इसे 1989 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया है । इसका कुल क्षेत्रफल 63 वर्ग किलोमीटर विस्तार लिये हुए है । यहॉ लाखों प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं । भू-जल स्तर नीचे जाने के कारण यह झील जल संकट से जूझ रही है । बिहार के बेहतरीन पर्यटक स्थलों में इसका शुमार हो सकता है परन्तु पर्यटकीय विकास नहीं हो सकने के कारण यह उपेक्षित पड़ा हुआ है । पाल वंश में स्थापित एक मंदिर भी इस झील के निकट ही जयमंगलागढ़ के नाम से विख्यात है । इस काबर झील और जयमंगलागढ़ को विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे यह पर्यटन के दृष्टिकोण से विश्व के मानचित्र पर स्थापित होगा ।

अत: विश्व प्रसिद्ध काबर झील एवं जयमंगलगढ़ को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जिला पदाधिकारी, बेगुसराय से पत्रांक-411 दिनांक-02.03.2021 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

बिहार में अवस्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है । पर्यटन विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थलों का विकास किया जा रहा है । जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत पर्यटकीय दृष्टिकोण से उक्त स्थल को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं अन्य सम्बद्ध विभागों से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : आपको पूरक नहीं न पूछना है । ठीक है । आप पूछिये । आपका हस्ताक्षर इसमें है ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, 12.5 हजार एकड़ जमीन काबर झील की अतिक्रमित हो गई है। लोग उसको दखल करके खेती-बाड़ी कर रहे हैं । सरकार से हम जानना चाहते हैं कि कबतक उसको मुक्त करायेगी ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की गई है । प्रतिवेदन आने के बाद अन्य और जो विभाग इससे संबंधित हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके समीक्षा करके आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, आज ही नहीं, हम समझते हैं कि पक्षी विहार के नाम से वह झील घोषित किया गया था लेकिन सरकार का ध्यान अभी तक उस ओर नहीं गया है । एक और महत्वपूर्ण बात है महोदय....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । कितने कम शब्दों में आपके पहले माननीय सदस्य ने पूरक पूछा । आप पूरक पूछिये, भूमिका नहीं बनाइये ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : पूरक ही है महोदय । अति महत्वपूर्ण सवाल है । यह जो काबर झील है, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने सर्वे कराकर लगभग भू-भाग को झील के अंदर दे दिया है । महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि बहुत बड़े बसावटों को भी झील में दे दिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, पूरक है । इसका उदाहरण है कि जयमंगला उच्च विद्यालय भी उसी झील के अंदर दे दिया गया है । यह आश्चर्य की बात है । मैं सरकार से माँग करता हूँ कि पुन: पैमाइश कराकर उस जमीन को जो झील के अंदर है....

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बताया कि प्रतिवेदन मँगा रहे हैं । आप बैठ जाइये । आप पूछिये, राज कुमार जी ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार काबर झील एवं जयमंगला गढ़ को एक समेकित पर्यटन कोरिडोर के स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है ? यदि है, तो इसके लिए डी0पी0आर0 की प्रक्रिया कबतक शुरू कर सकती है ? इसी से संबंधित दूसरा है कि क्या सरकार ऐसी समझ रखती है कि इस प्रकार के पर्यटन स्थल के विकास से पर्यटन का विकास एवं पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और इससे बेरोजगारी की जो समस्या है, उसका भी समाधान होगा ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो ध्यानाकर्षण है, बहुत महत्वपूर्ण है । इसके महत्व को देखते हुए सरकार ने जवाब दिया है और जिन प्रश्नों को माननीय सदस्य राज कुमार बाबू पूछ रहे हैं, पर्यटकीय दृष्टिकोण से जितने भी राज्य में हमारे धरोहर हैं, सभी पर्यटक स्थलों का विकास हो रहा है और विकसित करने की सरकार की मंशा भी है । उसमें जो अन्य प्रश्न उठे हैं, मैंने कहा है कि जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन आ जायेगा और संबंधित जो अन्य विभाग से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, उनको बुलाकर उसकी समीक्षा की जायेगी और समीक्षा के उपरांत इसका निर्णय लिया जायेगा ।

टर्न-12/आजाद/03.03.2021

श्री कुंदन कुमार : महोदय, ...

अध्यक्ष : अब आगे बढ़ गये, अब आप कैसे पूछेंगे बताइए ?

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 1989 में ही इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया । उसके बाद क्या-क्या कदम लिये गये इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए......

अध्यक्ष : सारे विषय वे बता दिये हैं ।
माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

<u>सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना</u>

श्री अजीत शर्मा,सभापति,प्रत्यायुक्त विधान समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211(1) के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

अन्तराल

टर्न-13/शंभु/03.03.21

(अन्तराल के उपरान्त)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे । वित्तीय कार्य । माननीय सदस्यगण, शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | -56 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी | -55 मिनट |
| जनता दल युनाइटेड | -33 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | -14 मिनट |
| सी0पी0आइ0एम0एल0 | -09 मिनट |
| ए0आइ0एम0आइ0एम0 | -04 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | -03 मिनट |
| विकासशील इंसान पार्टी | -03 मिनट |
| सी0पी0आइ0एम0 | -01 मिनट |
| सी0पी0आइ0 | -01 मिनट |
| लोक जनशक्ति पार्टी | -01 मिनट |

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 380,35,92,80,000/-(तीन सौ अस्सी अरब पैंतीस करोड़ बानवे लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अख्तरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं जिसपर सभी माननीय सदस्य विचार- विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटायी जाय ।''

मान्यवर, सरकार ने शिक्षा मंत्री जी ने जो मांग प्रस्तुत किया है । महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि राज्य में शिक्षा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो या हायर शिक्षा हो । उसमें नीतीश जी के 15 साल के हुकूमत में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ और यह सुधार मैं मानता हूँ इसलिए नहीं हुआ कि नीतीश जी और उनकी सरकार शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी क्षमतावान हैं, कर सकते हैं, लेकिन इनकी इच्छाशक्ति का अभाव है । यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ महोदय, एक उदाहरण पेश करके कि अनबोलता पशुओं के युनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नीतीश जी के ही राज्य में उसकी पदस्थापना हुई और एक व्यक्ति के ठीक होने से भी स्थिति में व्यापक सुधार हो सकता है । आज अनबोलता पशुओं के अस्पताल के जर्जर अवस्था को सुधारकर के वहां की पढ़ाई को ठीक करके इलाज में गुणात्मक सुधार हुआ है, इन्हीं के कार्यकाल में इसलिए महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अनबोलता पशुओं के चिकित्सा में पशुपालन युनिवर्सिटी में सुधार जब हो सकता है तो मानव बल के सृजन के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी हो सकता है । महोदय, किसी भी राज्य के अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी की जबर्दस्त आवश्यकता है और मानव पूंजी का विकास तब होगा जब वह शिक्षित होगा, सबल होगा, उसकी शिक्षा तकनीकी शिक्षित होगा तभी राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है । महोदय, मेरा समय तो अभी....

अध्यक्ष : 4 मिनट है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, विजय चौधरी जी अध्यक्ष थे, कट मोशन में प्रथम वक्ता 20 मिनट बोलता था ।

अध्यक्ष : आपके दल के लोग ही लिखकर दिये हैं ।

श्री विजय शंकर दूबे : हमारे दल का कटौती होगा थोड़ा उपर नीचे होगा, हम कर लेंगे । महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य की शिक्षा में सुधार होना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप हाईस्कूलों में, इंटर कॉलेज में, वित्त रहित कॉलेजों में कमिटी में इन्वोल्व करना चाहते हैं । महोदय, कोई सरकुलर नहीं है, पैसे की निकासी प्रिंसपल और वर्कर कर लेगा, खाते में सरकार का आदेश हुआ कि खाते में प्रिंसपल और वर्कर दो ही रहेंगे फिर अपने मनमाने ढंग से पैसे की निकासी करते हैं, व्यय करते हैं, समिति के हस्तक्षेप का कहीं कोई नियम में प्रावधान नहीं है । इसलिए मैं विजय चौधरी जी से हाईस्कूलों के व्यवस्था में जहां आप विधायकों से कार्य लेना चाहते हैं उसमें भी विकास निधि में निकासी प्रधानाध्यापक और वर्कर शिक्षक मिलकर कर लेंगे, विधायक जी क्या कर सकते हैं । हाईस्कूल कहीं न कहीं 15-20 एक ब्लॉक में हैं । इसलिए उसमें विधायक सब जगह अध्यक्ष तो होंगे नहीं, नोमिनी रखेंगे । इसलिए महोदय, अगर नियत

ठीक है और सुधार करना चाहते हैं तो विजय चौधरी जी कानून में व्यवस्था में जो सरकुलर है उसमें प्रावधान तो करें । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ । वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में, इंटरमीडियेट कॉलेज में भी जो प्राइवेट है समिति को इन्वोल्व करते, अखबारों में कहते हैं कि समिति को वित्तीय अनुदान की राशि में बंटावारे पर कार्रवाई करेंगे अगर गड़बड़ी होगी तो बांटेगा कौन प्रिंसपल और वर्कर ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी से कि इसके लिए सरकुलर जारी करें ।

अध्यक्ष : ठीक है बैठ जाएं अब ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, अंतिम में मैं अपने क्षेत्र के एक-दो बातों की ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । दो ब्लॉक है महाराजगंज और भगवानपुर हाट- भगवानपुर हाट में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है । महोदय, टोटल हमारे प्रमंडल में 90 हजार हर डिग्री के लिए आवेदन पड़े छपरा, सिवान, गोपालगंज में सीटें कितनी है 33 हजार और अब वे बच्चे जायेंगे कहां ? बच्चे और बच्चियां पढ़ना चाहते हैं सीट आप बढ़ा नहीं रहे हैं । महोदय, जे0पी0 युनिवर्सिटी जब से खुला एक ही युनिवर्सिटी है छपरा, सिवान गोपालगंज में तीन साल ग्रेजुएशन का टर्म जो फिक्स है वहां तीन साल में बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं । वहां पांच साल, सात साल लग जाता है ग्रेजुएट करने में, परीक्षा समय पर नहीं होती है । इसलिए मैं चौधरी जी का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-14/ज्योति/03-03-2021

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का माईक खराब है या आवाज खराब है हमको समझ में बात आयी नहीं, माईक देखवा लीजिये, हो सकता है कि माईक खराब हो ।

अध्यक्ष : श्री अवध बिहारी चौधरी, 20 मिनट का समय है ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग का जो बजट है, उपबंध है और उसमें जो माननीय विरोधी दल के सदस्यों द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, 15 वर्षों के शासन काल में एन. डी.ए. के द्वारा शिक्षा विभाग में मंत्री बनते रहे हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शिक्षा की योजना और शिक्षा में सुधार के लिए बजट का प्रोविजन होते रहा है परन्तु शिक्षा की जो दुर्गति है, उस दुर्गति के बारे में आप इस राज्य के विद्वानों से, इस राज्य के सामाजिक, शैक्षणिक संस्थान में जो काम करने वाले लोग हो, खेत में खलिहान में

रहने वाले लोग हों, किसी पेशा में काम करने वाले लोग हों, उनके द्वारा यही चर्चा रहती है कि 15 वर्षों में इस सरकार ने शिक्षा को चौपट करने का काम किया है । महोदय, शिक्षा के बजट बनते रहे हैं, बनते रहेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं जो उच्च आई.ए.एस. पदाधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा बजट बनाने का काम होता है, वह बजट बनाते हैं और आप उसका अनुमोदन करते हैं मंत्रिपरिषद में और संयुक्त जिम्मेवारी मंत्री, मिनिस्टर की होती है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी कि बजट को आप चूँकि शिक्षा के मंत्री बने हुए हैं इस राजय के तो उसको गंभीरता से देखने और अध्ययन करने का काम होना चाहिए । आखिर बिहार के गांवों में शिक्षा की क्या स्थिति है ? बिहार में शिक्षा की क्या गुणवता है और जो हम बजटरी प्रोविजन हम करने जा रहे हैं, उस उपबंध से बिहार की शिक्षा में गुणवता आयेगी या नहीं आयेगी या बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो योजना बन रही हैं उनसे वंचित हो जायेगी या उनको ऊपर उठाने का काम यह बजट करेगा । मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं होता है । हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री चौधरी जी हैं और इनको मैं जानता हूँ, 1985 में ये विधान सभा में जीत कर आए थे, मैं भी जीत कर आया था और उस समय मरहूम हो गए जो बड़े ही अच्छे मुख्यमंत्री बने थे जो सब की बात को सुनते थे स्वर्गीय बिन्देश्वरी दूबे जी, उस जमाने से मैं इनको जानता हूँ लेकिन जो बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी उसको गंभीरता से आप निश्चित देखते तो जो शिक्षा पर इस राज्य की बेहतरी के लिए जो बजट में प्रोविजन किया गया है तो मैं समझता हूँ कि यह जो बजट का जो आकार है, जो इसमें योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इस पैसे से खर्च करके हम क्या बिहार में शिक्षा की जो दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति से उबार सकते हैं क्या ? परन्तु शिक्षा में आपने सर्वाधिक बजट देने का काम किया है । लेकिन नया कुछ दिखलायी नहीं देता । लगता यही है कि शिक्षा में कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है बल्कि यह दिखलायी देता है कि इतनी बड़ी रकम को जिसतरह से पहले से अनियमितता होती आ रही है वैसी स्थिति इस बार भी होने वाली है । माननीय हमारे साथी बिजेन्द्र बाबू, मैं हकीकत को कह रहा हूँ और हकीकत को सुनना चाहिए और विरोधी पक्ष कटौती देता रहा है उसके औचित्स भी होते हैं और सरकार के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को सही तरीके से कार्यान्वयन के लिए सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो बजट बनाने का काम किया है । पूर्व में भी 2018-19 में 32125 करोड़ 63 लाख आपने उपबंध लिया था । 2019-20 में 34798 करोड़ 69 लाख फिर 2020-21 में 35191 करोड़ 5 लाख और 2021-22 में 38035 करोड़ 93 लाख कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपने बजट में प्रति वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर आपने

ज्यादा बजट देने का काम किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूॅं कि आपने जो 18-19 में, 19-20 में, 20-21 मे और फिर 21-22 में अभी तो 31 मार्च को 2020-2021 का वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा हैं । आपने तो जिक्र नहीं किया कि इस राज्य के गरीबों की गाढ़ी कमाई भिन्न भिन्न जो इन्कम का जो सोर्स है, उद्गम है उसमें आपने लेने का काम किया और जो बजट भिन्न भिन्न विभागों के लिए आपने बनाने का काम किया ।

क्रमशः

टर्न-15/पुलकित/अभिनीत/03.03.2021

(क्रमशः)

श्री अवध विहारी चौधरी: मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इस पैसे को खर्च कर के शिक्षा में किस तरह का सुधार करने का काम किया है ? कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है । मैं समझता हूँ कि आपके 2020-21 के बजट में जो प्रोविजन था, सरकार ने उस पैसे, उस राशि का कितना प्रतिशत अभी तक खर्च करने का काम है, यह बतलाने का काम आपने नहीं किया है । आंकड़ों के जाल में फंसा कर के बिहार की जनता को पूरा अंधकार में ले जाने का काम यह सरकार कर रही है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जो शिक्षा है और उस शिक्षा में आप जो सुधार करना चाहते हैं, सुधार के लिए ही यह बजट है लेकिन कैसे चलेगा । महोदय, 2021-22 के बजट में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है परंतु सरकार की ऐसी कोई दृष्टि परिलक्षित नहीं हो रही है कि वह किस तरह इस धन का सदुपयोग करेगी, यह एक सोचनीय विषय है । महोदय, सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है । वर्ष 1967 में एक कोठारी कमीशन बना था, 1967 में देश में कोठारी कमीशन का गठन हुआ था और कोठारी कमीशन ने अपनी अनुशंसा दी, सोचिए 1967 में माननीय मंत्रीजी, उसने कहा था कि देश में शिक्षा और शिक्षा की एकरूपता तभी संभव होगी, चाहे किसान का बेटा हो, दलित का बेटा हो, शोषित का बेटा हो, बड़े हाई समाज का बेटा हो, एम0एल0ए0 हो, एम0पी0 हो, आई0ए0एस0 हो, आई0पी0एस0 हो, जो उनका निवास स्थान है उस निवास स्थान के इलाके में स्कूल हैं, कॉलेज हैं उस स्कूल-कॉलेज में उनके बच्चों का भी दाखिला होना चाहिये, वहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिये ।

महोदय, इतने वर्ष बीत गये और भारत सरकार ने जो कोठारी आयोग का गठन किया, उसने जो अनुशंसा की शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए और शिक्षा में एकरूपता लाने और विषमता को दूर करने के लिए लेकिन उस पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार उसकी अनुशंसा को, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री विजय बाबू से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा कोठारी आयोग

के रिकमेंडेशन को, अनुशंसा को निश्चित रूप से थोड़ा देखें कि आज की परिस्थिति में 1967 के जो कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन थे वह क्या आज की परिस्थिति में शिक्षा के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं हैं ? महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए देश तथा राज्य में वार्ताएं चल रही हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में जो सोच और समझदारी है, इससे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थान हैं उनका भला होने वाला है । मैं कहना चाहता हूँ कि जो राइट टू एजुकेशन, संविधान की जो व्यवस्था है, जो निजी स्कूल हैं या सरकार के नियंत्रण में हैं गरीब के बेटे का, अभाव में जीने वाले के बेटे-बेटियों का उसमें नामांकन होता है ? नहीं होता है । महोदय, यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है पूरी तरह से शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों को निजी हाथों में सौंप देने की यह साजिश है । मैं कहूंगा कि इस पर माननीय अध्यक्ष जी, सदन को और शिक्षा मंत्रीजी को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है । ये निजी संस्थाएं जो शिक्षण देती हैं अगर निजी लोगों के हाथों में चली जायेंगी तो उसमें क्यों नहीं सरकार की सोच और समझदारी के मुताबिक गरीब बच्चों का भी नामांकन हो रहा है ? आप पता लगवायें कि जो प्राइवेट स्कूल हैं क्या उसमें आम लोगों के बच्चे और बच्चियों का नामांकन होता है ? नहीं होता है, इसलिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, चूंकि शिक्षा का बजट है, हर बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए।

महोदय, 1967 ई0 में जो प्राथमिक शिक्षा, मध्य शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की मैंने चर्चा की उनकी जो अनुशंसा है उसको मैंने कहा कि जरा उस पर भी पहल की जाय, जरा उसको भी देखा जाय लेकिन बाद में कोठारी आयोग की अनुशंसा को लागू किया ? नहीं किया । आपकी सरकार ने, एन0डी0ए0 गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक आयोग बनाने का काम किया और जिसमें देश के प्रख्यात शिक्षा शास्त्री अनिल सद गोपाल जी भी शामिल थे और अध्यक्ष बने थे । जो हमारे झा जी थे, शिक्षा सचिव अब नहीं रहें, दिवंगत हो गये । एम0एम0 झा साहब, उन्होंने भी अपनी अनुशंसा में कॉमन स्कूल सिस्टम के संबंध में अनुशंसा दी । क्या सरकार उनकी अनुशंसा में, कॉमन स्कूल सिस्टम की जो अनुशंसा है, जो एम0एम0 झा साहब के और जो आपके द्वारा बनाया गया कमीशन है, उस कमीशन का सरकार ने कार्यान्वयन किया ? नहीं किया तो मैं समझता हूं कि सरकार सिर्फ कमीशन बनाती है ।

टर्न-16/हेमन्त-धिरेन्द्र/03.03.2021

अध्यक्ष : अब आप संक्षिप्त करें ।

श्री अवध विहारी चौधरी : कि जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आयेगी, सबों का विकास नहीं होगा, तब तक यह राज्य समृद्धि की तरफ नहीं जा सकता है । राज्य को समृद्ध बनाने के लिए और आपकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रत्येक घर में शिक्षा का होना अति आवश्यक है लेकिन शिक्षा अभी कोसो दूर है । प्राइमरी स्कूल में आपने नियोजन पर, आपकी गाईडलाइन के मुताबिक शिक्षकों को नियोजित किया गया । महोदय, कैसे गुणवत्ता लायेंगे ? स्कूल बनाने से, डेस्क देने से, टेबल देने से, बेंच देने से शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आयेगी । महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी के लोग हैं, अपने समय में से थोड़ा समय मुझे देने का काम करें ।

श्री ललित यादव : महोदय, मेरी पार्टी की ओर से माननीय सदस्य जी का पांच मिनट समय और बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष : दो मिनट तो हो चुकी हैं इसमें एक्स्ट्रा ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, इसलिए जो....

अध्यक्ष : अब बोलिये, दस मिनट हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, आपने जो प्राथमिक शिक्षक में चार लाख शिक्षकों की नियुक्ति की । आपके निदेश पर, आपकी गाईडलाइन पर वह नियुक्त किये, बहाल किये गये । आखिर उसके जो पैसे मिलते हैं, वह कहां से आते हैं ? चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो इस राज्य का जो बजट है, उसकी व्यवस्था के तहत जो आपने तरीके बनाये हैं, पैसा सरकार देती है लेकिन उन लोगों का मन टूटा हुआ है, समान काम के लिए वह समान वेतन की मांग करते हैं और आपने, माननीय न्यायालय ने एफिडेविट किया कि हमारे कर्मचारी नहीं हैं । महोदय, यह दुखद बात है और आप शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं । महोदय, जो पढ़ाने वाला है, वह दुखी है, उसका दिल टूटा हुआ है, उसका पेट खाली है, उसका परिवार दुख की जिंदगी बिता रहा है, तो आप समान काम के लिए समान वेतन देने का काम करें । शिक्षकों की जो समस्या है, उस समस्या का निदान सरकार गम्भीरता से करेगी तो मैं समझता हूं कि शिक्षा में गुणवत्ता आयेगी । जब तक आप बात को डायवर्ट करते रहेंगे मैं समझता हूं कि समस्या का निदान नहीं होगा । माध्यमिक विद्यालय में 94 हजार शिक्षक और उन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते, पढ़ाने वाला नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, छत से पानी टपक रहा है । तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि इन 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करायें । आप कल प्रश्न का जवाब दे रहे थे, माननीय मंत्री जी, हम सुन रहे थे लेकिन न्यायसंगत फैसले हो जायं इसके लिए पर्सुवेशन करना सरकार की जिम्मेवारी है । उस काम को करके आप शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी करें ताकि स्कूल में पढ़ाई हो सके, गुणवत्ता हो सके । महोदय, पहले बिहार में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा ले

ली गयी, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बोर्ड ने बड़ी हड़बड़ी की । सालभर कोरोना काल में स्कूल बंद रहे और बच्चे पढ़ने नहीं गये परन्तु बिना पाठ्यक्रम को पूरा किये हड़बड़ी में आपने परीक्षा ले ली लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी परीक्षाएं पाठ्यक्रम पूरा कर मई में लेने की तैयारी में है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक उसके रिजल्ट नहीं होंगे तब तक आपके लड़कों का नामांकन नहीं हो सकता है । इसलिए इस बेचैनी के साथ आपको भी चाहिये था कि पाठ्य-पुस्तक और उसका जो सिलेबस है, पढ़ाई है, उसको पूरा कराना चाहिये । यह सरकार की खामी है, सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये । महोदय, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं उन लोगों ने नामांकन सीमित कर दिया है । अब बतलाइये, आपके जो इंटर पास हैं, मैट्रिक पास हैं, कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं होगा । आप सीट को बढ़ाइये, अगर आपकी प्रबल इच्छाशक्ति है, शिक्षा के प्रति आप गंभीर हैं, तो सभी जो आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आप इंटरमीडिएट कौंसिल को कहिये कि एडमिशन रोके नहीं, जो लड़के पास किये हैं, उनका नामांकन किया जाय । महोदय, आपके देश में उच्च शिक्षा में औसत नामांकन 26-30 प्रतिशत का लक्ष्य है परन्तु बिहार में इसे 10-11 प्रतिशत रखा गया है । अब बताइये कैसे लक्ष्य को पूरा करेंगे और ग्रॉस एलिजिबिलिटी आपका जो रेशो है, आप जनरल बजट में कहते हैं कि हमारा वर्ष 2030 में 50 प्रतिशत पूरा होगा, तब तो आपके लड़के बहुत बाहर हैं, यह दिक्कत है । इसलिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस पर विचार कीजिये कि स्कूल में टेबल नहीं है, डेस्क नहीं है, शिक्षक नहीं है और किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, मिड-डे-मील में लूट हो रही है, पैसे खर्च करने में बहुत सारे ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हैं । मिड-डे-मील, पोशाक और पाठ्य-पुस्तक का वितरण नहीं होता है, आप जब एडमिशन हो जाता है तब वितरण कीजियेगा । नहीं, आप पहले, समय पर वितरण कराइये । प्रबंध समिति है, उसको और मजबूत बनाने का काम कीजिये और प्रबंध समिति में छात्रों के नामांकन के आधार पर आप 75 हजार देते हैं, एक हजार से ऊपर होता है तो आप एक लाख देते हैं, उस राशि को समय से भिजवाने का काम करें और जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनको आप पावर देने का काम कीजिये, अगर हमारे विधायक अधिकार से वंचित रहेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं ।

अब, मैं मदरसा बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहता हूँ कि मदरसा बोर्ड में काफी अनियमितता सुनाई पड़ रही है। अपने तरीके से बोर्ड को, मदरसा कमेटी को भंग किया जा रहा है । वित्तीय रोक के बावजूद भी वित्त का उपयोग कर रहा है, हाईकोर्ट का आदेश, रोक लगने के बाद भी वह चेत नहीं रहे हैं । इसलिए, यह दुखद बात है, पूरी माइनोरिटी का सवाल है, बिहार का सवाल है । इसलिए, मदरसा बोर्ड को भी मंत्री जी जरूर देखने का काम करें और

कार्रवाई होनी चाहिए और अपने परिवार के ही लोगों को उसमें बहाल करने का काम कर रहे हैं । इसलिए, इन तमाम चीजों को आप देखेंगे । फिर, मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं उन्हें ए0सी0पी0 का लाभ मिला लेकिन प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं वह आज तक वंचित हैं, उनके दुख को दूर नहीं कीजियेगा तो शिक्षा में उजाला कैसे आयेगा ?

...क्रमश:...

टर्न-17/सुरज-संगीता/03.03.2021

...क्रमश:...

श्री अवध विहारी चौधरी : इसलिए आपके पदाधिकारी लोग भी इतना विलंब करते हैं कि शिक्षा विभाग में, माननीय न्यायालय में ज्यादा से ज्यादा वाद हो जाता है, केस हो जाते हैं इसलिए उदासीन शिक्षा विभाग के बिहार के पदाधिकारियों को आप बतलाने का काम कीजिए, समस्या है तो उसका निदान तेजी से होना चाहिए । महोदय, नामांकन की बात मैं कहता हूं, नामांकन के लिए आनलाईन नामांकन का आपने आदेश किया है, चाहे इंटरमिडिएट कौसिंल हो, चाहे..

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री अवध विहारी चौधरी : चाहे यूनिवर्सिटी हो, 300 रुपये आनलाईन देना पड़ता है और बहुत से वित्तरहित कॉलेज में न इंटर में कोई आंतरिक स्रोत है और न डिग्री में कोई आंतरिक स्रोत है...

अध्यक्ष : आप बैठ जायें, अब समय हो गया ।

श्री अवध विहारी चौधरी : इसलिए तीन सौ रुपया में एक सौ रुपया इंटर कौंसिल बोर्ड को और उसमें से एक सौ रुपया यूनिवर्सिटी को रख करके वह क्षतिपूर्ति जो है महाविद्यालय और इंटरमिडिएट स्कूल को भेज देना है परंतु आज तक नहीं भेजा गया है । समय से जब जाएगा तो कॉलेज के आंतरिक स्रोत बढेंगे और भूख से जो मर रहे हैं, शिक्षक उनकी भी भुमखरी दूर होगी और शिक्षा के प्रति उनकी रूचि बढ़ेगी इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिहार में फिजिकल टीचर हर स्कूल में, हमलोग भी पढ़ते थे तो फिजिकल टीचर होता था..

अध्यक्ष : और समय आपका बढ़ेगा क्या ?

श्री अवध विहारी चौधरी : लेकिन फिजिकल शिक्षक...

अध्यक्ष : बैठ जाएं अब ।

श्री अवध विहारी चौधरी : आपने परीक्षा लिया और फिजिकल शिक्षक का सेलेक्शन हुआ परंतु आज तक उनके तीन हजार से ज्यादा जो प्रशिक्षित, जो फिजिकल टीचर हैं जिनका नाम अब स्वास्थ्य अनुदेशक भी रखा गया है उसको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम कीजिए और

यूनिवर्सिटी को मजबूत कीजिए, भ्रष्टाचार को दूर कीजिए और सारे आधारभूत संरचना को चाहे प्राईमरी हो, सेकेंडरी हो या उच्चतर हो या उच्च हो उसमें आधारभूत संरचना शिक्षक प्लस जो मेटेरियल है उन तमाम जो उपस्कर है उसको देने का काम कीजिए । मैं समझता हूं कि सरकार की इच्छाशक्ति अगर मजबूत रहेगी जिस पर हमें शक है तो बिहार में शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, मजबूत बनेगा बिहार और यहां की जो गरीबी है उसको दूर करने में आर्थिक मदद में यह शिक्षा विभाग कारगर होगा और मैं कहना चाहता हूं कि जो 19 हजार आपने शिक्षकों को, पढ़े-लिखे लोगों को, नौजवनों को नौकरी देने का काम किया है कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शिक्षा में ज्यादा नौकरी दे सकते हैं इसलिए 19 लाख जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं उनको नौकरी देने का काम कीजिए । इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, बैठिये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : और मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह के सकारात्मक सोच रख करके सरकार की जो खामी है आपके माध्यम से सदन में उठाने का हम काम करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री भाई वीरेन्द्र : और सदन की तरफ से अपने तरफ से आपको भी बधाई देना चाहते हैं कि आपके पैनल के सदस्य थे उसका ख्याल आपने रखा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : चलिये, आपलोगों ने भी उनको 12 मिनट का एक्सट्रा समय दिया ।
श्री पवन कुमार जायसवाल जी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर सरकार के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले राष्ट्रपिता बापू की कर्मभूमि चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं जिनके सहयोग से इस सदन का सदस्य बने हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम अपने जो सुझाव दिये उसके संग्रह को सभा के पटल पर दे रहा हूं कि प्रोसिडिंग का पार्ट बने ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, खुशी के लिए काम करने पर केवल खुशी मिलती है लेकिन खुश होकर काम करने पर खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होती है । वर्ष 2005 के पहले लोग केवल अपनी खुशी के लिए काम करते थे इसलिए वर्ष 2005 के पहले वाले लोग, पहले के सरकार के लोग खुश होते थे और जनता दुखी होती थी । वर्ष 2005 के बाद एन०डी०ए० की सरकार खुश होकर काम करती है इसलिए

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : इसलिए माननीय सदस्य जी बिहार की जनता भी खुश है और आप भी इस सदन में खुश होकर बैठे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । सुदय यादव जी, कितना अच्छा से बोल रहे थे, लोग सुन रहे थे । बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले की सरकार की सोच थी कि राज्य में चरवाहा विद्यालय खुले । हम चंपारण से आते हैं वहां तेतरिया एक जगह है, श्यामबाबू भाई का विधानसभा क्षेत्र है, वहां चरवाहा विद्यालय जहां खुला था, वर्ष 2005 के बाद एन०डी०ए० की सरकार ने वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया यही अंतर है एन०डी०ए० की सरकार में और वर्ष 2005 के पहले की सरकार में । अध्यक्ष महोदय,.....

श्री आलोक कुमार मेहता : अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर चरवाहा विद्यालय की प्रशंसा हुई है...

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : अभी पूरी बात वे अभी कहे कहां है, सुनिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, जब मेरी बात समाप्त हो जायेगी तब माननीय सदस्य तो वरीय हैं आलोक भाई अपनी बात को रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, हम उस जिले से आते हैं, हम तो आलोक भाई को निमंत्रण देते हैं कि एक बार आप चलिए तेतरिया, चलिए मलाही के चरवाहा विद्यालय में । चलकर देखिए कि आपने वहां जो चरवाहा विद्यालय खोला, वहां के आज चरवाहा समाज के लोगों के उत्थान के लिए आपने कौन-सा काम अपने राजपाट में करने का काम किया, कौन सा काम, कौन बिल्डिंग बना वहां, किस काम के लिए भवन बना था ? कैसी योजना आई थी, अगर योजना आई तो आपने उत्थान के लिए कौन सा काम किया, जरा बताने का काम कीजिएगा जब आपके अगले वक्ता आयेंगे तब । अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले साढ़े बारह परसेंट बच्चे विद्यालय से बाहर थे, आज एक परसेंट बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, यह एन०डी०ए० की सरकार की उपलब्धि है । आप 4 हजार 366 करोड़ का बजट लाते थे, आज एन०डी०ए० की सरकार 37 हजार 357 करोड़ का बजट प्रस्तुत करती है । इसका 20 परसेंट केवल शिक्षा पर खर्च होता है, यही एन०डी०ए० सरकार की उपलब्धि है और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक पैमाना दिखता है ।

अध्यक्ष महोदय, फुलवरिया मेरा घर है, ढाका विधानसभा क्षेत्र में । हमारे दादाजी जिस विद्यालय का जमीन दान किए थे प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया, हम वर्ष 2001 में जब जिला पार्षद हुए तो उसका भवन जर्जर होता था । ऐसा भवन था कि टूटे जर्जर भवनों से विद्यालय की पहचान होती थी कि यह सरकारी विद्यालय, यह प्राईमरी, मिडिल और हाई स्कूल है और आज सबसे सुंदर और सबसे ऊंचे भवन से विद्यालय

भवनों की पहचान होती है कि यह प्राइमरी स्कूल है, यह मिडिल स्कूल है और यह हाई स्कूल है । महोदय, अंतर तो दिखता है, अंतर तो दिखता है । पहले माननीय अनिल भाई आप राज्यसभा के मेम्बर रहे हैं.........

(व्यवधान)

अनिल भाई आप राज्यसभा के मेम्बर रहे हैं, पहले उपलब्धि कैसे समझ में नहीं आएगी ? पहले आप पांच हाई स्कूल के अध्यक्ष हुआ करते थे विद्यालय प्रबंध समिति के और आज आप हर पंचायत के हाई स्कूल के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं । अपने आप में भी झांकने की जरूरत है । पहले कितने विद्यालय के अध्यक्ष आप होते थे ? पहले गिने चुने हाई स्कूल होते थे, तीन चार हाई स्कूल आपके विधानसभा क्षेत्र में होता था आज हर पंचायत में हाईस्कूल हुआ, उत्क्रमित उच्च विद्यालय हुआ और जहां नहीं हुआ वहां नवम के विद्यालय का संचालन हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपको जब मौका मिलेगा तब अपनी बात को रखिएगा । अध्यक्ष महोदय, हमको समझ में नहीं आता है जब हमलोग विधायक पहली बार बने तो हमलोगों को लगता था विपक्ष के लोग आईना होते हैं सरकार का । जब ये बोलते हैं तो सरकार को एक आईना दिखता है कि भाई यह सुधार करने की जरूरत है लेकिन यहां जितना बात होता है, जितना प्रस्ताव आ रहा है यह निरर्थक आ रहा है । यह जनता के पैसे का दुरूपयोग ये लोग करते हैं, कहीं कोई सार्थक बात ये लोग रख नहीं पाते हैं । जब हमलोग कहते हैं सुरज पूरब में है तो ये कहते हैं पश्चिम में है । अध्यक्ष महोदय, हमलोग कहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए ये कहते हैं कि शराब चालू कर देना है, हमलोग कहते हैं कि शिक्षा पर जोर देना है ये कहते हैं कि शिक्षा नीति सही नहीं है, आपकी नीति कैसी थी, किस नीति पर आप काम करते थे ? अध्यक्ष महोदय, इनके टाइम में न तो पोशाक का पैसा था न इनके टाइम में छात्रवृत्ति मिल पाता था, न इनके टाइम में मध्याह्न भोजन था, इनके टाइम में क्या था महोदय, इनके टाइम में पाठ्यपुस्तक फ्री नहीं मिलते थे, आज की सरकार ने इन सारी व्यवस्थाओं को भी लागू किया ।

...क्रमशः...

टर्न-18/ मुकुल-राहुल/03.03.2021

क्रमशः

श्री पवन कुमार जायसवालः और पारदर्शी तरीके से छात्र-छात्राओं तक पहुंचने के लिए उनके खाते में भेजने की व्यवस्था की ताकि दलाली प्रथा बंद हो जाय । आपके तरह तो सिस्टम भी नहीं था और घोटाले पर घोटाले हो जा रहे थे सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी से इन कामों को

किया है । अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति, प्रतिस्पर्धा से छात्र-छात्राओं में दिलचस्पी बढ़ती है, सरकार ने कहा कि हम 25 हजार रुपया महिलाओं को देंगे, 50 हजार रुपया स्नातक करने पर देंगे, आपके समय में छात्र-छात्राओं को एक चॉकलेट देने की योजना नहीं थी, आपने चॉकलेट से भी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करने का काम नहीं किया, आज की सरकार 25 हजार, 50 हजार रुपया देने का काम करती है । अभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन विद्यालयों में 100 परसेंट छात्राओं की उपस्थिति होगी उनको भी 5 हजार, 10 हजार रुपया पुरस्कृत करने की योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाई गयी है । अध्यक्ष महोदय, नवसृजित विद्यालय आपके समय में खुलते कहां थे, आपके समय में तो विद्यालय की जरूरत थी नहीं । एन0डी0ए0 की सरकार ने राज्य में नवसृजित विद्यालय को खोलने का काम किया, एन0डी0ए0 की सरकार ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय करने का काम किया और एन0डी0ए0 की सरकार ने हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी खोलने का काम किया । हमारे यहां ढाका विधान सभा में एक महिला कन्या उच्च विद्यालय है कड़मावा, घोड़ा साहन में एक प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है और आज हमारे यहां 15 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं मैं फिर से एन0डी0ए0 की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हम भी इस सदन के मेम्बर के रूप में एन0डी0ए0 की सरकार के प्रतिभागी हैं । महोदय, पहले काम क्या होता था । अध्यक्ष महोदय, कस्तूरबा विद्यालय, आपकी सोच क्या थी, आपके समय में तो लड़कियों, छात्राओं और लोगों को दिन में चलने में परेशानी होती थी और आज एन0डी0ए0 की सरकार ने कस्तूरबा-1, कस्तूरबा-2, कस्तूरबा-3 और कस्तूरबा-4 तक जाने का काम किया । आठवीं तक की लड़कियों के लिए, 8 से 10 तक की लड़कियों के लिए और अब 10+2 की लड़कियों के लिए भी कस्तूरबा विद्यालय की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था हुई है, जहां खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, तोसक-तकिया से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं । आप तो माननीय सदस्य कभी जाते नहीं होंगे आपका तो काम विरोध करना है, आप में से एक कोई माननीय सदस्य बता दें कि किसी कस्तूरबा विद्यालय में गये हों, वहां की व्यवस्था को आपने कभी देखा हो, आप अगर गये हैं तो आप जब गये हैं, अध्यक्ष महोदय, जब यह गये हैं तो जब इनको मौका मिलेगा तो कस्तूरबा विद्यालय की योजनाओं के बारे में ये इस सदन को जानकारी दें कि कस्तूरबा में आता क्या है, कस्तूरबा का संचालन कैसे होता है, उसके वार्डन कितने हैं, उसमें कूक कितने हैं, उसमें आदेशपाल कितने होते हैं, कितने हैं-कितने नहीं हैं ? आपने सदन में इस संबंध में प्रश्न करने का काम नहीं किया है, क्योंकि आपको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार की कमी रहती है, विभागों में कमी होती है हम लोग अपनी बातों को रखते हैं ।

अध्यक्षः आप अपनी बात संक्षिप्त करें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, हम संक्षिप्त कर रहे हैं । मेरा कुछ सुझाव भी होगा, माननीय मंत्री जी बैठे हैं । सरकार की नीति आई थी कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल खुलेगा, पहले हुआ कि जहां पर स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय है वहां पर हाई स्कूल नहीं खुलेगा उसी को मानकर चला जायेगा लेकिन बाद में जहां स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय था वहां भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय खोल दिया गया, नॉर्म का संचालन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दो हो गया है एक ही हो और जहां स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय है उसी को उच्च विद्यालय की मान्यता मिलनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, विद्यालय प्रबंधन समिति है, शिक्षा विभाग में दो तरह का मामला है एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को पैसा प्राप्त होता है, एक तो विद्यालय प्रबंधन समिति के स्तर पर है, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो पैसा जाता है इस पर कोई निगरानी नहीं हो पाती है । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, पिछले दिनों माननीय सदस्यों ने सवाल लाया था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विद्यालय प्रबंधन समिति से बाहर नहीं हो सकता है, समिति अलग रहे लेकिन उसका अनुश्रवण और निगरानी विद्यालय प्रबंधन समिति के जिम्मे दिया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में कम्प्यूटर ट्रेनिंग शुरू हुआ था हाई स्कूलों में, 2017 तक की योजना थी, 2017 के बाद यह कम्प्यूटर ट्रेनिंग बंद हो गयी, सारे कम्प्यूटर पड़े हुए हैं स्कूलों में । अध्यक्ष महोदय, हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि अविलंब जो कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हाई स्कूलों में चालू हुए थे जहां कम्प्यूटर सामग्री है वह विद्यालय का हो गया और वह किसी एजेंसी को मिला था । अब एजेंसी का जब समय समाप्त हो गया तो अब उसको चलाने के लिए अलग से दूसरे एजेंसी की व्यवस्था हो या कम्प्यूटर संचालन के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था हो । अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक आधारभूत संरचना है जिसके माध्यम से डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये में हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, हम तो धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री जी कि अब जो आप टेंडर करने जा रहे हैं उसमें आपने पूरे सामान को भी शामिल कर दिया है, कुर्सी, टेबल से लेकर सभी चीजों को शायद आप लोगों ने उसी टेंडर में शामिल कर दिया है । लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं जैसे मेसौरा बाजार है...

अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, जब बत्ती जलेगी तब हम बैठ जाएंगे । बहरवा फतेह मोहम्मद है, पुरनयिया है यहां भवन बना, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको यह नहीं पता है कि भवन कैसे बना, इसको हेन्डओवर, टेकओवर कैसे करना है? मेरा आपसे आग्रह होगा कि शैक्षणिक आधारभूत संरचना को जिला शिक्षा पदाधिकारी से टैग करने की जरूरत है, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों से टैग करने की जरूरत है कि भवन

जब बने तो बनने के साथ-साथ उसके हेन्डओवर, टेकओवर की कार्रवाई भी हो जाए । हमारे मित्र हैं और विज्ञान प्रोद्यौगिकी मंत्री हैं श्री सुमित जी उनका भी है उनको हम धन्यवाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं कि नौजवान हैं आप अपने विभाग को और अच्छे ढंग से चलाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: श्रीमती शालिनी मिश्रा जी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री की विभागीय मांग का समर्थन एवं मांग की कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । महोदय, मैं आपके, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी कि मुख्य सचेतक आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं कि इस विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया है । महोदय, अपने केसरिया विधान सभा की जनता के प्रति भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर में मुझे आने का अवसर दिया और मैं आज आप लोगों के सामने यहां खड़ी हूं । मैं अपने पिताजी, पूर्व सांसद स्व0 श्री कमला मिश्र मधुकर जी एवं माताजी के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने यह सपना देखा कि मैं जनता की सेवा में अपना जीवन लगा दूं । महोदय, आज मेरा पहला स्पीच विधान सभा में है आशा करती हूं कि कुछ त्रुटि होगी तो माननीय सदस्य इसको इग्नोर कर देंगे । महोदय, शिक्षा किसी भी सरकार की रीढ़ है, शिक्षा के स्तर से ही किसी भी सरकार को आंका जाता है इसीलिए किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि शिक्षा को पहली प्राथमिकता दे जो कि बहुत ही बखूबी हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और इस बजट में अगर किसी विभाग को सबसे बजट मिला है तो वह शिक्षा विभाग का है इसके लिए मैं बिहार सरकार का आभार प्रकट करती हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी आभार प्रकट करती हूं । महोदय, शिक्षा के लिए कुछ आधारभूत संरचनाए होती हैं जैसे कि भवन...

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण जब आपका समय आएगा तब आप भी बोलिएगा, आपसे आग्रह है कि प्लीज मुझे बोलने दें ।

अध्यक्ष: आप बोलते जाएं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: आधारभूत संरचनाएं, भवन, उपस्कर एवं प्रयोगशालाएं । अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों को याद दिलाना चाहती हूं कि 2005 के कालखंड में जब हम किसी शहर से, गांव से, पंचायत और कस्बे से गुजरते थे महोदय, तो उस गांव कस्बे पंचायत का सबसे जीर्णशीर्ण खंडर जैसा जो मकान होता था उसको देखते ही बिना पूछे ही हम समझ जाते थे कि यह विद्यालय का भवन है जबकि आज खुबशूरती ये है कि उस जगह की सबसे चमचमाती बिल्डिंग विद्यालय की होती है और हम गर्व से कह सकते हैं कि ये

हमारा विद्यालय है, बिहार सरकार का विद्यालय है । महोदय, पहले जहां पर विद्यालयों में भैंस, बकरियों और गाय का बसेरा हुआ करता था, कई विद्यालय पेड़ के नीचे भी चलते थे अब विद्यालयों में भवन, उपस्कर, प्रयोगशाला, शिक्षक, छात्र और पढ़ाई बखूबी से होती है । महोदय, वर्ष 1990 से 2005 का ही कालखंड था जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बहुत ही जोर-शोर चरवाह विद्यालय की स्थापना करवा रहे थे और गरीबों, शोसितों, वंचितों को भैंस के साथ और जानवरों के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे । महोदय, ठीक उसी समय जब वे यह महान कार्य कर रहे थे..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: पहली बार बोल रही हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: महोदय जब वे...

(व्यवधान)

टर्न-19/यानपति-अंजली/03.03.2021

(व्यवधान)

अध्यक्ष: पहली बार बोल रही हैं । अब दो मिनट बचा है, अपना समापन करें । ये पहली बार बोल रही हैं । मौका मिलेगा आपको ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: ठीक है । महोदय, आग्रह है आपलोग सुनें मेरी बात को । विडंबना यह है कि ठीक उसी समय जब वह गरीबों, शोषितों, वंचितों को इस महान कार्य के लिए इस भैंस के विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, अपने सुपुत्र जो सौभाग्य से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं आज माननीय तेजस्वी यादव जी को भारत के एक सबसे बड़े विद्यालय डी0पी0एस0 आर0के0 पुरम में पढ़ा रहे थे । ये कैसा दोहरा मापदंड था महोदय, ये कैसी विडंबना थी कि एक तरफ गरीबों को तो आप चरवाहा विद्यालय में भैंसों के साथ पढ़ा रहे हैं ।

अध्यक्ष: अब संक्षिप्त कर लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: जी महोदय, मैं करती हूं । बिहार में महिला शिक्षा के लिए जो काम आदरणीय मुख्यमंत्रीजी ने और बिहार सरकार ने किया है वह उल्लेखनीय है महोदय । जब महिलायें जाती हैं स्कूल, लड़कियां जाती हैं स्कूल जब साइकिल की योजना शुरू की गई उसकी खूबसूरती देखते बनती है और जब लड़कियां बड़ी हुई छठे क्लास के बाद महोदय तो मुख्यमंत्रीजी की संवेदनशीलता देखिए कि उन्होंने जब देखा कि उनके पास उपयुक्त कपड़े नहीं हैं उन्होंने पोशाक योजना भी शुरू की । शिक्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता के लिए मैं उनको सलाम करती हूं । महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं

महोदय जिसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने रखती हूं । हमारे क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना की जाय । महोदय, इसके साथ-साथ लोकशिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत जरूरी है । टोला सेवकों की बहाली की जाय जो बाकी हैं, विज्ञान प्रावैद्यिकी माननीय मुख्यमंत्रीजी से कहना चाहती हूं...

अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: एक मिनट महोदय, पहली बार बोल रही हूं । एक मिनट मौका दीजिए महोदय । आंध्र, तेलंगाना की तरह अगर हम बिहार में भी आई0टी0 हब स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम शिक्षा की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे । हम संप्रभुता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे । माननीय महोदय, समय-समय पर अगर केसरिया विधान सभा सहित पूरे बिहार में अगर शिक्षकों को समय पर स्कूल जाने और पढ़ाने के लिए हम और ज्यादा प्रेरित करेंगे तो शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार होगा । संस्कृत को अगर हम बढ़ावा देते हैं और मेन शिक्षा धारा में लेकर आते हैं तो इससे गतिशीलता बढ़ेगी और...

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: बहुत-बहुत धन्यवाद । आपको मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं । बस एक बात कहना चाहती हूं कि मैंने सुना है कि संगत का बहुत असर होता है महोदय । माननीय मुख्यमंत्रीजी के साथ, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी साथ में काम किया है । एक शेर उनके लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के लिए -

''कहते हैं कि हो जाता है, कहते हैं कि हो जाता है,
संगत का असर, पर कांटों को आज तक नहीं
आया महकने का सलीका ।''

अध्यक्ष: चलिये अब बैठ जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय, सरकार का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं ।

अध्यक्ष: अब श्री सतीश कुमार । 10 मिनट का समय है । श्री सतीश कुमार ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: विचारधारा को सीमा में बांधा नहीं जा सकता है ।

श्री सतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले अपनी पार्टी को और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं जिसने मुझे सदन में भेजा और शिक्षा पर बहस आज मैं कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उसकी शुरुआत कहां से करूं ।

अध्यक्ष: तो समझ लें पहले ।

श्री सतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, भगत सिंह जब, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, वही सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं महोदय भगत सिंह 1928 में छात्रों के नाम चिट्ठी लिखते हैं जो कृति में छपता है महोदय वह कहते हैं शिक्षा के बारे में कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है । तो यह जो शिक्षा व्यवस्था है महोदय यह उसी की ओर इशारा कर रहे हैं । आज 15 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है, जो बेबसी है इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है महोदय । एक विद्यालय की चर्चा मैं करना चाहता हूं जो स्वर्गीय श्रीकृष्ण सिंह इसी विधान सभा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके नाम पर बेगूसराय में महिला महाविद्यालय है जहां पर महोदय 15 हजार छात्राएं पढ़ती हैं लेकिन उन छात्राओं को पढ़ाने के लिये मात्र 19 प्रधानाध्यापक हैं मात्र 19 टीचर हैं महोदय तो 800 बच्चों को पढ़ाने के लिये एक टीचर और 8 कमरे में महाविद्यालय चल रहा है महोदय ।

अध्यक्षः आप इधर-उधर न देखें आसन की तरफ देखें ।

श्री सतीश कुमारः महोदय, आठ कमरे में यह विद्यालय चल रहा है । एक कमरे में 15 सौ बच्चियों के बैठने की व्यवस्था है । महोदय, यही शिक्षा का 15 साल का आईना है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पहले पटना साइंस कॉलेज हुआ करता था, बी0एन0 कॉलेज हुआ करता था महोदय और उसके साथ मुजफ्फरपुर का एल0एस0 कॉलेज, आर0डी0एस0 कॉलेज, दरभंगा का सी0एम साइंस कॉलेज, भागलपुर का टी0एन0बी0 कॉलेज, गया का गया कॉलेज जिसमें प्रेम कुमार जी पढ़े हैं और अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज जिसमें राज्य के बाहर के भी बच्चे 2005 के पहले पढ़ने आते थे लेकिन 2005 के बाद एक भी राज्य के बच्चे इन कॉलेजों में नामांकन करने के लायक नहीं समझते हैं बच्चे । यह स्थिति बिहार के विश्वविद्यालयों का हो गया है महोदय तो अब नयी शिक्षा नीति की बात की जा रही है महोदय नयी शिक्षा नीति की बजट में भी बात की गयी है तो नयी शिक्षा नीति के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि 'नयी है शिक्षा नीति का और नया बना कानून और पढ़नेवाले तीन जो मित्र हैं तीन पढ़ेंगे जाकर देहरादून कि बाकी भैंस चरायेगा' यही स्थिति उत्पन्न की जा रही है महोदय । हम कहना चाहते हैं कि जब बिहार में छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उसी छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी भी । आज लालू प्रसाद यादव जी के चरवाहा विद्यालय पर टीका-टिप्पणी और उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है जिसपर यूनेस्को में भी रिसर्च हो रहा है महोदय । हम यह कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की सोच को समझिए । उन्होंने कहा ऐ सूअर चराने वालो, ऐ भेड़ चराने वालो, ऐ भैंस चराने वालो, ऐ बकरी चराने वालो, ऐ जूता बनाने वालो, ऐ तार पर चढ़ने वालो, ऐ बैंगन बेचने वालो

पढ़ना लिखना सीखो । लेकिन आज 15 साल में नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं ऐ मैट्रिक करने वालो, ऐ इंटर करने वालो, ऐ बी0ए0 करने वालो, ऐ पी0जी0 करने वालो, ऐ एम0बी0ए0 करने वालो, ऐ इंजीनियरिंग करने वालो बकरी चराना सीखो और भैंस चराना सीखो । यह अंतर है लालू प्रसाद यादव जी में और नीतीश कुमार जी में यह अंतर है महोदय कि वह भैंस चराने वालों को पढ़ाना चाहते थे लेकिन आप पढ़ा-लिखाकर उनको भैंस चरवाना चाहते हैं इसीलिए आपने कहा है कि पांच लाख रुपये का लोन देंगे और उससे वे भैंस का खटाल खोलेंगे और बकरी का खटाल खोलेंगे । इसीलिए बी0ए0 और एम0बी0ए0 कर रहे हैं महोदय । पकौड़ा योजना तो इनका महत्वाकांक्षी योजना है महोदय, इसपर भी यूनेस्को में हो सकता है रिसर्च हो ।

अध्यक्ष: समीर साहब, हिंट न करें, आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री सतीश कुमार: इसलिए महोदय, आज पटना यूनिवर्सिटी जो 100 साल 2017 में पूरा कर लिया था महोदय नीतीश कुमार जी की बेबसी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है महोदय जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे थे उसकी सौंवी सालगिरह के प्रोग्राम में और नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ा रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो हठधर्मिता थी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला महोदय, यदि वह दर्जा मिला होता तो आज हजारों छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा होता महोदय । लेकिन यह नहीं हो सका है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

इसलिए महोदय, हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन के बारे में जो हमारे समाज में है एजुकेशन इज द टाइप ऑफ थर्मामीटर व्हिच मेजर द नैचर एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी । महोदय, इस तमाम एजुकेशन से ही दुनिया में सब चीज नापा और तौला जा सकता है । इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा है बुद्धम शरणम् गच्छामि । डॉ0 अम्बेदकर ने भी कहा है शिक्षित बनो, राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है दो बातें मोटी-मोटी सब को शिक्षा सब को रोटी । लेकिन महोदय क्या यहां सब को शिक्षा मिल पा रही है । अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि बड़ी चमचमाती बिल्डिंग अब नजर आ रही है । मैं कहना चाहता हूं 15 साल में जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का यह हालात बना दिया गया है । यहां पर पॉलिसी मेकर के एक भी बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं न उसको पढ़ने लायक ही समझते हैं और 2005 के बाद जब दलित, पिछड़े के बच्चे तेजी से इस विद्यालय की तरफ लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से जब जाने लगे तो तेजी से सरकारी विद्यालयों को नष्ट किया जाने लगा है, बर्बाद किया जाने लगा और निजी

विद्यालय के लिए दरवाजे खोल दिये गये महोदय । आज बिहार में माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं बताइये कि जो 5 हजार रुपया से ज्यादा का इनकम कमाता है वह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता है महोदय यह स्थिति आ गई है । हम पूछना चाहते हैं कि वही नीतीश कुमार जी, वही पटना यूनिवर्सिटी में जब संघर्ष कर रहे होते थे तो जोर-जोर से नारा लगा रहे होते थे कि राष्ट्रपति का बेटा, यह भंगी की संतान सब की शिक्षा एक समान लागू करने की लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ओर एक कदम इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था खासकर के प्राइमरी स्कूलों की हालात बहुत जर्जर है महोदय और निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

टर्न-20/सत्येन्द्र/03-03-2021

श्री सतीश कुमार(क्रमशः): और निजी स्कूल अभी के हकीकत बन गये हैं लेकिन निजी स्कूलों के फीस के नियंत्रण पर, स्कूल की गुणवत्ता पर, वहां के टीचर के गुणवत्ता पर, वहां के कैम्पस की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितना स्कूल को मन होता है...

सभापति(श्री प्रेम कुमार)माननीय सदस्य, बैठ जायें। अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सतीश कुमार: महोदय नये सदस्य हूॅं महोदय, एक मिनट और दिया जाय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार)समय तय है न, सभी दलों का समय तय है ।

श्री सतीश कुमार: आप हीं के क्षेत्र से आता हूॅं महोदय..

सभापति(श्री प्रेम कुमार)कृपया बैठ जायें ।

श्री सतीश कुमार: तो महोदय, मैं चाहता हूॅं कि प्राईवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए एक कमिटी बने बिहार में ताकि वह मनमाना फीस नहीं वसूल सके, शिक्षा के नाम पर बच्चों से ठगी नहीं कर सके ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) माननीय सदस्य, श्री छत्रपति यादव जी ।

श्री छत्रपति यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का खगड़िया विधान-सभा की ओर से आभार प्रकट करता हूॅं कि आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया, साथ ही मैं विधान-सभा के सभी सदस्यगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूॅं। मैं अपने कांग्रेस पार्टी के लीडर और सचेतक महोदय का भी आभार प्रकट करता हूॅं । महोदय, इस शुभ वेला में मैं परम आदरणीय पूज्य पिता स्व0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, बिहार सरकार को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन करता हूॅं जिनके प्रेरणा एवं संस्कार से मुझे इस सदन के सदस्य होने का अवसर प्राप्त हुआ है । महोदय, सदन का समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपका ध्यान बिहार के वर्त्तमान शिक्षा प्रणाली की ओर आकृष्ट करता हूॅं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) आपका समय मात्र 2 मिनट है ।

श्री छत्रपति यादव: जी सर, आजादी के 70 साल भी साक्षरता का दर महोदय 80 प्रतिशत नहीं है। महोदय, मैं आपका ध्यान खगड़िया विधान-सभा क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ । उदाहरण के तौर पर खगड़िया विधान-सभा में 9 हाई स्कूल है जिसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर बनी हुई है इसलिए इन सब की इंक्वायरी कराने की जरूरत है, नेशनल स्कूल का देखिये, हालत खराब है, बालिका उच्च विद्यालय में बाऊंड्री नहीं है। 15-20 सालों से आपकी वहां जद(यू0) की विधायिका भी रही है पांच वर्षों से, पूरे क्षेत्र की इंक्वायरी कराने की जरूरत है कि वहां विद्यालय की क्या हालत है महोदय। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक कमिटी बनाकर के खगड़िया विधान-सभा के सभी विद्यालयों की जांच कराकर उसका विकास कार्य कराने का काम करें। यह अपनी ओर से मांग करता हूँ साथ ही साथ जितने भी उत्क्रमित विद्यालय बनाया गया है वहां शिक्षक का घोर अभाव है,आज भी वहां मिडिल स्कूल के शिक्षक ही पढ़ाते हैं। अभी हमारे यहां मंशी घरारी में नई बिल्डिंग बनी है लेकिन वहां बेंच डेस्क नहीं है और विद्यालय को शिक्षा विभाग की ओर से दवाब दिया जा रहा है कि पढ़ाई शुरू करो । महोदय, अधिकांश विद्यालय में बाऊंड्री नहीं है, पूराना बिल्डिंग बना हुआ है जिसका छत ढह रहा है। सदन की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहेंगे कि एक कमिटी बनाकर के पूरे खगड़िया विधान-सभा में जो 20 वर्षों से विद्यालय में प्रगति हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच करायी जाय और काम नहीं हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाय।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) अब स्थान ग्रहण करें ।

श्री छत्रपति यादव: इसी के साथ ही आपको धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूँ ।

श्री राजेश कुमार: महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इनको पांच मिनट समय आवंटित किया था और..

सभापति(श्री प्रेम कुमार) माननीय सदस्य, श्री विजय शंकर दूबे जी ज्यादा समय बोल चुके हैं, उनका समय बढ़ गया था इसीलिए।

श्री संजय कुमार सिंह: सभापति महोदय, आज मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ कि बिहार के विधान-सभा में बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी जनता को, उनलोगों का जिन्होंने प्रचंड बहुमत से लालगंज की ऐतिहासिक धरती से मुझे इस बिहार की विधान-सभा में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है। मैं स्मरण करता हूँ अपने उस पूज्य पिता को जिन्होंने जीवनपर्यन्त मुझे संघर्षपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है। मैं स्मरण करता हूँ अपनी पूज्य माता का जिनकी प्रेरणा से मैं सरकारी नौकरी छोड़कर समाज की सेवा में आज इस सदन का सदस्य बनने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। महोदय, आज जब शिक्षा की बात चल रही है तो हमको बिहार की उस

नालंदा विश्वविद्यालय की कौंध दिखाई पड़ती है, नजरों के सामने उसका वैभवशाली इतिहास दिखाई पड़ता है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय के आलोक से दुनिया आलोकित होती रही है, जिस नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान से दुनिया को ज्ञान प्राप्त होता रहा है, जिस वैशाली की धरती ने जिस गणतंत्र का ज्ञान सारी दुनिया को दिया, आज जिस चाणक्य ने सारी दुनिया को नीति सिखाया, उस बिहार की स्थिति वर्ष 2005 के पहले के लोगों ने क्या कर दी थी, यह देखकर मन में दुर्दशा आता है। सभापति महोदय,वर्ष 2005 के पहले की जो सरकारें थीं वह किस प्रकार की सरकार थी, उस समय कैसी शिक्षा बिहार के अंदर चल रही थीं, हमने अपने आंखों के सामने शिक्षकों को किराना के दुकानदार के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि इस बार राशन का सामान दे दीजिये मुझे जैसे ही वेतन मिलेगा वैसे पैसा दे दूंगा। ये गिड़गिड़ाते हुए मैंने शिक्षकों को देखा है। हमने ऐस विद्यालय देखें हैं, ऐसे जर्जर विद्यालय देखें है, मित्रों, सभापति महोदय, मैंने वह विद्यालय देखा है जिसके ऊपर छप्पर नहीं है, विद्यार्थियों को नीम गाछ के नीचे शिक्षा प्राप्त करते हुए देखा है। मैंने देखा है बिहार के विद्यालय में छप्पर नहीं, छप्पर पर खपड़ा फेरने के लिए बिहार की सरकार ने पैसा नहीं देती थी, ऐसी दूर्दशा से निकाल कर हमारे नेतृत्वकर्त्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार चमचमाती हुई सड़कें बनायी चमचमाती हुई सड़कें अगर बिहार को दी तो चमचमाती हुई स्कूल बिल्डिंग भी बिहार को दिया है, ऐसी सरकार हमारी है। हम इस सरकार को धन्यवाद देते हैं जिसने शिक्षा को सुदृढ़ किया है । हमारे अवध बिहारी बाबू अभी चर्चा कर रहे थे कोठारी कमीशन की, कोठारी कमीशन में क्या हुआ था, कोठारी कमीशन के बारे में ईमानदारी पूर्वक अगर कहा जाय तो आप सीने पर हाथ रखकर देखिये कोठारी कमीशन को लागू करने से आपको किसने रोका था, आपकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी के लोगों की सरकार थी जो आज आपके साथ बैठे हैं, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से आपको किसने रोका था। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद जी इस सदन के सदस्य रहे हैं, इस सदन के नेता रहे हैं और कोठारी कमीशन को अगर लागू नहीं किया गया तो उनके लड़के जो आज यहां प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह दिल्ली के आर0के0पूरम स्थित विद्यालय में पढ़ते थे और कोठारी कमीशन की बात कर रहे हैं, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, आपने ईमानदारीपूर्वक लागू नहीं किया, आपने इसको रोका है। मित्रों, मैं इस बात को कहना चाहूंगा।

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार)शांति बनाये रखिये।

श्री संजय कुमार सिंह: उनकी आदत बनी हुई है बैठे बैठे बोलने की, बुजुर्ग हैं आदत बनी हुई हैं। मैं मांग करता हूँ आज के इस

(व्यवधान)

हमारी सरकार ने कहा है, हम विश्वास करते हैं कि एक बेटी पढ़ेगी तो हमारी सात पुरख तरेगी। हम काम करने वाले लोग हैं इसीलिए हमने अपने लड़कियों को कहा है कि जो इंटर पास करेगी उसको 25 हजार रू0 वजीफा देंगे और जो स्नातक पास करेंगी उसको 50 हाजर रू0 वजीफा देंगे। यह विकास करने वाली हमारी सरकार है यह सरकार काम करने वाली सरकार है। मित्रों, हम कहते हैं हमको वैभवशाली बिहार चाहिए, हमको समृद्ध बिहार चाहिए इसलिए मैं कहता हूॅ कि हम गौरवशाली बिहार चाहते हैं। हमको इस गौरव से दूर करने का काम किसने किया ? रूस और चाईना से प्रेरणा प्राप्त करने वाले इतिहासकारों ने हमको अपने गौरवशाली इतिहास से बाहर किया है। हमारे गुरू गोबिंद सिंह जिनके दोनों बेटे (व्यवधान) जिंदा दिवालों में चुरवा दिये गये, हमको सभापति महोदय अकबर महान है, ये पाठ मुझको पढ़ाया गया परन्तु घास की रोटी खाकर भी पराधीनता स्वीकार नहीं करने वाले महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों से महरूम कर दिये गये। ऐसा इतिहास कम्युनिष्टों ने हमको पढ़ाया है इसलिए हम चाहते हैं सभापति महोदय कि बिहार की धरती के शान गुरू गोबिंद सिंह जी जिनके दोनों बेटे जिंदा दिवाल में चुरवा दिये गये उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाय, उनको यथावत स्थान दिया जाय । हम चाहते हैं सभापति महोदय, हम समृद्धशाली बिहार बनाना चाहते हैं और ये बामपंथी लोगों को, इनको इससे कुलबुलाहट होती है, हम गौरवशाली बिहार बनाना चाहते हैं। सभापति महोदय, बाजपेयी जी ने कहा था

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) शांति बनाये रखें।

श्री संजय कुमार सिंह: सभापति महोदय, बाजपेयी जी ने कहा था- हारे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता । इन कम्युनिष्ट पार्टी के लोगों ने कम्युनिष्ट विचारधारा से प्रभावित होकर इतिहासकारकों ने हमें हारे हुए मन का बना दिया, हमको टूटे हुए मन का बना दिया और अब इसके खिलाफ हमें संघर्ष करना है इसलिए हम मांग करते हैं अपने शिक्षा मंत्री जी से, हम मांग करते हैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि इतिहास के पन्नों को समृद्ध करिये।(क्रमशः)

टर्न-21/मधुप/03.03.2021

...क्रमशः..

श्री संजय कुमार सिंह : इतिहास का पुनर्लेखन कराइये और हमारे गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने खड़ा करिये ।

इतनी बात कहते हुए अपने क्षेत्र की महान जनता का एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं । धन्यवाद ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी जी । 7 मिनट ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय जगदा बाबू जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जिन्होंने इस महिला को पहली बार महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए आजादी के बाद मोहनिया की प्रथम महिला विधायक बनने का मुझे अवसर प्रदान किया । मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी पार्टी को, साथ-ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय विधान सभा के समस्त जनता का मैं तहेदिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर प्रदान किया । मैं इसके लिए आजीवन आभारी रहूँगी । सभी माननीय सदस्यों के बीच में मैं पहली बार बोल रही हूँ, इसलिए मैं आप सभी को भी सादर प्रणाम करती हूँ ।

महोदय, शिक्षा की बात चली है और शिक्षा के प्रस्तुत बजट पर पेश कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर मिला है । शिक्षा की बात हुई और बार-बार माननीय सदस्यों के द्वारा शिक्षा की बात कही जा रही है । महोदय, शिक्षा की नींव पर ही किसी राज्य की बुलंद इमारत खड़ी होती है । शिक्षा हमारे ज्ञान कुशलता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार लाती है, शिक्षा ही मानव में मानवता के सही मार्ग को दर्शाती है लेकिन वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल जो है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूं, चाहे मैं उच्च शिक्षा की बात करूं, हर दिशा में यह सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, वह सब गर्त में है । बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को विवश हो गए हैं । सवाल उठता है कि आप शिक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा का स्तर आज के समय में क्या है ? आप भवनों की बात करते हैं, जिस मिड-डे-मील की बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, हम चाहें उन्हें जिस आकार में ढाल दें लेकिन पहली से पांचवीं तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, आज सरकारी विद्यालयों की मैं बात करना चाहूंगी, आज बच्चे एजुकेशन की बात नहीं करते, आप उसकी व्यवस्था करते हैं कि कुपोषण के शिकार जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उन बच्चों के खाद्यान्न के लिए, तो दोपहर में आप देखेंगे, अपराह्न में बच्चे खाली थाली और चम्मच बजाते दिखते हैं कि उन्हें भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा । जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात

सरकार करती है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भवन है, कुर्सी नहीं है, मैं कैमूर जिले से आती हूँ, भभुआ के वार्ड नं0 14 के अम्बेडकर नगर का दलित बस्ती है, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय का भवन आज भी अगर कोई देखे तो जर्जर अवस्था में है । सरकारें आती हैं और वहाँ की कभी किसी ने सुध नहीं ली । इसलिए सुध नहीं ली क्योंकि दलित बस्ती का वह विद्यालय है । जिस चरवाहा विद्यालय का आप अपमान कर रहे हैं, उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार से ही आज मैं विधान सभा में खड़े होने के लायक बनी हूँ । उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार ने ही मुझे इस योग्य बनाया है और भूलिये मत, वह विद्यालय समाज के दबे-कुचले और शोषितों को मुख्यधारा में जोड़ने की बात की । सरकारी विद्यालयों में आपके बच्चे नहीं नहीं होते हैं, आप महानुभावों के बच्चे नहीं होते हैं, माननीय सदस्या ने एक बात कही, आप जब गाँव में जाती होंगी तो आप एक टूर करने जाती होंगी, आप गाँव की निवासी नहीं हैं जो आपने छप्पर की बात कही है, आपने उस समाज के दबे-कुचले लोगों की बात की, हमने घोघा चुनने वालों, जूता सीने वाले का मनोबल बढ़ाया और कहा कि आओ शिक्षा ग्रहण करो, तुम भी जागरूक बनो, तुम भी समझो कि तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान की परिकल्पना की थी, उस संविधान में तुम्हारे क्या अधिकार हैं । सामाजिक समीकरण को भी याद करना होगा । माननीय सभापति महोदय, इस सदन में एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, 2005 की बात बहुत माननीय सदस्य कर रहे हैं लेकिन सामाजिक समीकरण को आप इगनोर नहीं कर सकते हैं । कहीं न कहीं उन संघर्षों की बदौलत ही आज भी जब आप देखेंगे, समाज के उन बच्चों की आवाज में जो बुलंदी आई है, यह बुलंदी पहले नहीं थी । इस बुलंदी को लाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया है तब यह बुलंदी आई है और जिन भावनाओं की बात आप करते हैं, हमारे चैनपुर के माननीय मंत्री जी भी अभी यहाँ पर हैं, चैनपुर में हाता में एक विद्यालय है जहाँ बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। हमारा जो भभुआ जिला है वहाँ के नगरपालिका में जो मध्य विद्यालय हैं वहाँ बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं । जिस महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की बात करते हैं, कैमूर जिले में एक भी अंगीभूत सरकारी महिला कॉलेज नहीं है । कहाँ हैं महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले ?

महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस शिक्षा की आप बात करते हैं, भवन नहीं है, आपने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में हमने कर दिया लेकिन उच्च शिक्षा में शिक्षा कहाँ है । विद्यालयों में एक ही शिक्षक सारे विषयों की शिक्षा देता है । अगर फिजिकल एजुकेशन का टीचर, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देने वाला भी टीचर है तो वह एक ही टीचर सभी विषयों को पढ़ाता है तब सवाल उठता है कि राईट टु

एजुकेशन आपका कहाँ है ? जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप करते हैं, वह कहाँ है?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमारी पार्टी का जो शेष समय बचा है, संगीता कुमारी जी को पार्टी का शेष समय दे दिया जाय ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग में सरकार दावा करती है कि बजट में प्रावधान किया जा रहा है लेकिन शिक्षण कार्य को छोड़कर । एक माँग मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि सभी गैर शैक्षणिक कार्य जो आज के परिवेश में शिक्षकगण कर रहे हैं चाहे वह जनगणना हो, मिड-डे-मील हो, भवन निर्माण हो, शिक्षक को आपने शिक्षा कार्य के लिए लगाया है या मतगणना, जनगणना और भवन निर्माण के लिए लगाया है । शिक्षक का काम शिक्षा देना होता है । गुरू की महत्ता हमारे समाज में बहुत ही उच्च कोटि की होती है तो शिक्षक को जब आप मतगणना में, जाति गणना में लगा देंगे और ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति कर देंगे तो सवाल उठता है कि राइट टु एजुकेशन की बात करने वाली सरकार के सामने यह सवाल उठता है कि राइट टु टीचर क्या है, बताइये । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप खाने के लिए अलग से एन0जी0ओ0 के माध्यम से व्यवस्था करें । शिक्षक को शिक्षण कार्य में ही लगाये रहें तो निश्चित रूप से एक नई दिशा तय होगी ।

महोदय, राइट टु एजुकेशन में गरीब बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक देने का प्रावधान किया गया है लेकिन समय पर नहीं मिलता है । क्यों नहीं समय से सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व किताबें दी जाती हैं ? भवनों की मैं बात करना चाहती हूँ । 35 प्रतिशत शिक्षण संस्थानों में शिक्षक की कमी है । आज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है । आपके 10 प्रतिशत स्कूलों में भवन नहीं है, 50 प्रतिशत में चाहरदिवारी नहीं है, 30 प्रतिशत में खेल के मैदान नहीं हैं, 10 प्रतिशत में शौचालय नहीं हैं तो सवाल उठता है कि यह कौन-सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था है । 2005 की बात करते हैं ? विश्वविद्यालयों की बात आप देखेंगे कि बच्चे उत्तीर्ण होकर बैठे हुए हैं लेकिन 7-7 साल तक इंतजार करते रहते हैं कि अब हमें डिग्री मिलेगी । यह स्थिति है विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की । शिक्षकों की भी कमी है ।

महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मैं कैमूर जिले से आती हूँ और जिस परिवेश से मैं आती हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं जिस समाज से आती हूँ शायद इस राजनीतिक परिपाटी में मैं पहली आई हूँ । एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चियों के लिए अगर महाविद्यालय खोल दिया जाता है तो निश्चित रूप से महिलाएँ/बच्चियाँ और सशक्त होंगी । एक मैं

पहल करना चाहती हूँ । अगर ट्यूशन जाती हैं तो कई तरह की छेड़खानी और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस तरह आये-दिन समाचार-पत्रों में देखने को मिलता है । जबतक महिलाएँ सशक्त नहीं होंगी, किसी भी समाज की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं । आधी आबादी को सशक्त करना बहुत ही जरूरी है, महोदय । इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि महिला महाविद्यालय हमारे जिले में खोला जाय । बच्चियों के लिए एजुकेशन की हर पंचायत में व्यवस्था की जाय और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ -

''तुम्हें है शौक अगर बिजलियाँ गिराने का,
तो हमारा काम भी है आशियां बनाने का ।
सुना है आप हैं माहिर हवा चलाने में,
हुनर न छोड़ेंगे हम भी दीए जलाने का ।''

एक बार पुनः आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : अब माननीय सदस्य श्री विनय चौधरी जी । आपका 4 मिनट है ।
श्री ललित कुमार यादव : महोदय, अगर हमारी पार्टी का समय बच गया हो तो मुकेश जी को दे देंगे।

टर्न-22/आजाद/03.03.2021

श्री विनय कुमार चौधरी : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपनी ओर से और बेनीपुर विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया । साथ ही मैं अपने नेता और अभिभावक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तथा बेनीपुर की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जिनकी वजह से मैं सदन का सदस्य बन सका । मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं सबसे पहले अपनी श्रेयसी सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी वजह से यह तो पता चला कि प्रतिपक्ष के नेता चरवाहा विद्यालय या पहलवान विद्यालय में न पढ़कर के दिल्ली के एक बड़े स्कूल में पढ़े हैं । वह दिगर बात है कि वे डिग्री नहीं प्राप्त कर सके । यह सही बोल रहे हैं, ये पूछते है यह ठीक है लेकिन चरवाहा विद्यालय जिसके लिए आप कहते हैं कि अन्तरार्ष्टीय स्तर पर उसकी पहचान है, उसकी ख्याति प्राप्त है । XXX

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : अनिल बाबू, बैठ जाइए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : ये गरीब-गुरबे की बात करते हैं और चरवाहा विद्यालय खोलते हैं । लेकिन अपने बच्चे के नामांकन के समय में जब मौका मिलता है तो उसमें वे नामांकन नहीं लेते हैं ....

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जायं । माननीय सदस्य, बैठिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : और ये लोग अपने बच्चे का बड़े विद्यालयों में नामांकन जाकर के कराते हैं । यह दिगर बात है कि उनके बच्चे डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं । जिस विद्यालय की स्थापना वे खुद करते हैं उसकी पढ़ाई की व्यवस्था पर उनको खुद का भरोसा नहीं रहता है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए । हम देखवा लेंगे ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, विपक्ष के नेता हिन्दुस्तान टाईम्स में एक लेख, एक आर्टिकल लिखे थे, आर्टिकल को पढ़ने का मुझे मौका मिला । डिग्री तो वे माध्यमिक स्तर तक प्राप्त नहीं कर सके लेकिन पेपर में कॉलम लिखते हैं, कैसे

XXX : आसन के आदेश से अंश विलोपित किया गया ।

लिखा यह तो वे बेहतर ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ । लेकिन मुझे पढ़ने का मौका मिला । जिसमें इन्होंने कहा है कि ''He gave powers to mukhiya (headmen) to directly recruit teachers and set the terrible precedent of hiring on a contractual basis. ''

मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ही शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की थी । आप जब ये लेख लिखते हैं कि वह मुखिया सही नहीं किया तो आपने क्यों दिया यह अधिकार । महोदय, मैं सदन में आने से पहले एक अखबार है, जिसमें बतौर ब्यूरोप्रमुख में कार्य करता था । जिसमें दो पेज का समाचार लिखने का मौका मिलता था .....

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो रहा है, अब आप कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री विनय कुमार चौधरी : एक मिनट सर । अन्त में आपके माध्यम ललित नारायाण मिथिला...

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपसे आग्रह है कि कृपया आप बैठ जायं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया आप बैठ जायं, आपका समय समाप्त हो गया । श्री संदीप सौरव जी, आप शुरू कीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय सदस्य ने हम पर टिप्पणी की, हम उनको जानकारी बताना चाहेंगे कि दो-दो मुख्यमंत्री के हम पुत्र हैं, शायद ही ऐसा नसीब और ऐसा भाग्य किसी को मिला हो । ये लोग कहते हैं जंगल राज, जंगल राज दो-दो मुख्यमंत्री का बेटा के पास भी फर्जी डिग्री नहीं है, यह ऑनेस्टी है । XXX

(व्यवधान)

महोदय, जहां तक सरकारी स्कूल की बात है । इनको पता नहीं है, हमारी सात बहनें हैं और मेरे बड़े भाई सभी लोग ज्यादातर सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं और जहां तक डिग्री का सवाल है,

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : नेता प्रतिपक्ष, अब कृपया आप बैठ जायं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, शायद ही बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकता है......

XXX : आसन के आदेश से अंश विलोपित किया गया ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, इसलिए हमने सोचा कि जरा जस्टिफाई कर दें, ज्यादा जानकारी आपलोगों को नहीं है । हमारा तो जन्म ही चपरासी क्वार्टर में हुआ है वेटनरी में ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : अब बैठ जायं, कृपया निजी टिका-टिप्पणी न करें । अब नेता प्रतिपक्ष, कृपया बैठ जायं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सभापति महोदय, इन लोगों को पूरी जानकारी मिलती नहीं है, इसलिए उन्होंने जो बोला है, उसको रेकोर्ड से निकलवाया जाय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : देखवा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम लिया और देश के केन्द्रीय मंत्री का नाम लिया, उसको प्रोसिडिंग्स से निकलवाया जाय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : हटा दिया जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : निदेश दिया जाय सर ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : बिल्कुल हटा दिया जायेगा । माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, फर्जी डिग्री पर बोला गया है, फर्जी डिग्री दिखावें न ......

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : वो विषय समाप्त हो गया । अब आप बैठ जाइए । प्रोसिडिंग्स से निकल गया । माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी बोलिए ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में यहां पर बात रख रहा हूँ ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर बाबू, प्लीज बैठ जाइए । संजय जी, बैठिए ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, जिस तरीके से सदन का कस्टोडियन आप है, वैसे ही इस देश का कस्टोडियन और इस देश का लोकतंत्र का कस्टोडियन यहां का संविधान है । संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में यह कहा गया है कि समान शिक्षा दिये वगैर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं । अगर इकुअल एजुकेशन नहीं देंगे तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे और पूरी दुनिया में इसका कोई अपवाद नहीं है । लेकिन आज पूरे देश के भीतर और बिहार के भीतर शिक्षा को बाजार का सामन बनाकर के और बाजार के वस्तु बनाकर के हमने बिहार के और देश के तमाम करोड़ों छात्रों को, बच्चों को गरीब और अमीर में बांट दिया है । एक तरफ वो लोग हैं जिनमें नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए महंगे स्कूलों में एक-एक लाख रू0 लग जा रहे हैं । उन स्कूलों में तमाम ऐसे फीश हैं, वो स्कूल बाद में है महोदय, पहले वह दुकान है और उस दुकान में जो मध्यम दर्जे के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वे अपना पेट काटकर के पढ़ा रहे हैं । उन स्कूलों में अगर दसवीं तक की पढ़ाई के लिए कोई 10 लाख रू0 खर्च कर दे रहा है तो आप समझिए कि वह बच्चा आगे चलकर वो जो इनवेस्टमेंट उनका है, उसको ब्याज सहित निकालेगा और इसीलिए हम यह मांग करेंगे कि यह जो प्राइवेट स्कूलों का पूरा चक्रजाल देश के अन्दर बिछा हुआ है, बिहार के अन्दर बिछा हुआ है उसके खिलाफ एक कठोर कानून यहां से सदन से पारित हो ताकि उसपर अंकुश लगाया जाय । दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की स्थिति पर हम यह कहना चाहेंगे कि वहां की पढ़ाई-लिखाई है, वह बेहद घटिया किस्म की है । वो अदृश्य पढ़ाई-लिखाई है और जब हम अदृश्य पढ़ाई-लिखाई कह रहे हैं, अधूरा कह रहे हैं तो उसका एक बिहार सरकार का रिपोर्ट है 8 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है । इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के भीतर स्कूलों में जो उपस्थिति होती है बच्चों की, वह एभरेज 28 प्रतिशत है, सिर्फ 28 प्रतिशत । 11वीं ओर 12वीं के बच्चों का एटैंडेन्स का परसेनटेज है वह 3.67 प्रतिशत, 3.67 परसेंट एलेवेन्थ और ट्वेल्थ में बच्चे एटैंडेन्स बनाने जा रहे हैं क्लास में । अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप हमें यह बताइए, हम माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि तब यह पोशाक कौन पहन रहा है, यह साईकिल कौन चला रहा है । बच्चे जब स्कूल नहीं जायेंगे तो आप क्या लेंगे ? असल में बिहार के भीतर यह जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का जो एक

बड़ा गैप होते जा रहा है । हमें लगता है कि इस गैप को बिना भरे, इसको बिना दुरूस्त किये आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते रहे वो सिर्फ ढिढ़ोरा होगा और कुछ नहीं होगा । इसीलिए मैं इस सदन में यह प्रस्ताव रखता हूँ कि कॉमन स्कूल सिस्टम को बिहार के अन्दर लागू करने की तैयारी की जाय । कॉमन स्कूल सिस्टम के कई आधार हैं । उसमें यह नियम बनाया जाय कि आपको अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से अपने घर से सबसे नजदीकी सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा । हमें यह कानून बनाना चाहिए और इसके कुछ आधार हमारे पास हैं । 2007 में बिहार सरकार ने मुचकुन दूबे कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने यह कहा कि बिहार जैसे राज्य में शिक्षा को अगर बेहतर करना है तो आपको कॉमन स्कूल सिस्टम से ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है, यह उस कमेटी का रिकोमेंडेशन कहता है महोदय और हमने देखा है कि यूरोप का एक बहुत पिछड़ा देश, यूरोप का शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा देश फीनलैंड है । 1970 के दशक तक वह सबसे पीछे वाला देश था लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम वहां हुआ एक आन्दोलन के बाद और 30 साल के भीतर वह यूरोप का पहला देश बना शिक्षा के मामले में और पूरी दुनिया में आज फीनलैंड जो है, वह अपना स्कॉलर को प्रोवाईड करता है, वह अपना स्कॉलर भेजता है और उससे उसकी आमदनी हो रही है तो यह हम चाहते हैं ।

..... क्रमशः ......

टर्न-23/ज्योति/03-03-2021

क्रमशः

श्री संदीप सौरभ : जी-8 जो आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है उसमें अगर इंग्लैंड को छोड़ दिया जाय तो बाकी जो 7 देश हैं वहॉं कॉमन स्कूल सिस्टम और नेबरहुड स्कूल सिस्टम लागू है । इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार के अंदर भी बिहार इसकी शुरुआत करे और पूरे देश को एक रोशनी दिखाए इसलिए इस प्रस्ताव को हम यहॉं पर रख रहे हैं । आजादी के 70 साल हो गए महोदय, और देश के करोड़ों बच्चे और उनके जो पैरेंट्स हैं वो जस्टिस के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको न्याय चाहिए और शिक्षा के मामले में न्याय तब ही संभव होगा जब आप कॉमन स्कूल सिस्टम को समान शिक्षा प्रणाली को बिहार के अंदर और देश के अंदर लागू करेंगे इसलिए इस प्रस्ताव को हम यहॉं पर रखना चाहते हैं । इस सदन के सामने मैं एक दूसरी बात की

तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । हमने देखा हैं सरकार का एक टर्म यूज होता है पारा टीचर । जिसका हिंदी में मतलब हुआ अर्द्ध शिक्षक और सरकार अर्द्ध शिक्षक की नियुक्ति कर रही है, शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर रही है । शिक्षा सेवक की नियुक्ति कर रही है । टोला सेवक और तालिमी मरकज की नियुक्ति कर रही है लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है क्योंकि जब आप शिक्षक की नियुक्ति करने लगेंगे तो आप समझिये कि उनको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा उनको पूरा अधिकार देना पड़ेगा । पूरे बिहार के भीतर साढ़े तीन लाख शिक्षक हैं जो समान काम के, समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं । संविधान का आर्टिक्ल 39 का 'ख' सेक्शन जो है, बी सेक्शन जो है वह कह रहा है कि आप एक काम के लिए दो दो वेतन नहीं दे सकते हैं । महोदय, हम इस सदन में यह बात कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक यहाँ पर जितने हमलोग मौजूद हें अगर यह नियम बन जाय कि आधे विधायकों को पूरा पेमेंट पूरा टी.ए. डी.ए. मिले और आधे विधायकों को कोई टी.ए. डी.ए. नहीं मिले सिर्फ आधा वेतन मिले तो आप समझिये कि इस सदन के अंदर किस तरह का माहौल होगा, सदन का लोकतंत्र कैसा होगा, यह समझना चाहिए उन तमाम शिक्षकों के लिए वह चाहे टोला सेवक हों, तालिमी मरकज हों या गेस्ट फैकल्टी हों या गेस्ट टीचर हों, उनके लिए स्कूलों में यही माहौल बनाकर रख दिया गया है इसलिए हम चाहेंगे कि उन तमाम शिक्षकों की जो मांगें हैं, उसको पूरा किया जाय और मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करें । यह हम सदन के सामने कहना चाहते हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो देश के अंदर उच्च शिक्षा की जो हालत है बिहार उसमें सबसे बदतर स्थिति में है । उच्च शिक्षा का इनरौलमेंट रेट जो है राष्ट्रीय स्तर पर वह 26.3 है लेकिन हमारे बिहार में वो 10 और 11 परसेंट के आसपास जाकर लटक गया है । हम यहाँ नया विश्वविद्यालय नहीं खोल रहे हें । पूरे बजट के भीतर पॉलिटेक्नीक और आई.टी.आई. से आगे की बात नहीं की गयी है और हम धड़ाघड़ स्कूलों को, कॉलेजों को बंद करते जा रहे हैं । किशनगंज में सीमांचल के किशनगंज में ए.एम.यू खोलने की बात थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ खोलने की बात थी लेकिन अभीतक वह मामला पेन्डिग पड़ा हुआ है । मगध यूनिवर्सिटी के 118 एकड़ जमीन को सरकार ने आई.आई.एम. को दे दिया है । यूनिवर्सिटी कैम्पस के अंदर के 6 छात्रावास एक स्टेडियम और 32 जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं वह आई.आई. एम. को चला गया है । नया विश्वविद्यालय नहीं खोल रहे हैं लेकिन जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनको धड़ाघड़ एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं इसलिए महोदय, मैं मगध विश्वविद्यालय के तमाम लाखों छात्रों की तरफ से और जो पूर्ववर्ती

छात्र हैं उन तमाम छात्रों के बिहाफ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस निर्णय को सरकार तुरत वापस ले और आई.आई.एम. को कहीं और शिफ्ट किया जाय । इसके अलावे जब शिक्षा की बात हो रही है तो महोदय, मैं दो प्वायंट कह कर बैठ जाऊंगा । जब शिक्षा पर बात हो रही है तो निश्चित तौर से परीक्षा पर बात होनी चाहिए । शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों का जो रोजगार का मसला है उस पर बात होनी चाहिए । 94 हजार टीचर को लेकर इस सदन में कई बार बात हुई । मंत्री महोदय ने कहा कि उस पर सरकार काम कर रही है । आई.ए. फाईल हो गया है कोर्ट के अंदर लेकिन उसका मेन्शनिंग नहीं हो रहा है जबतक मेन्शनिंग नहीं होगा तबतक कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी तबतक उनकी नियुक्ति नहीं होगी इसलिए मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उसकी मेन्शनिंग जल्द से जल्द करवायी जाय । दारोगा बहाली का महोदय, दारोगा बहाली के पी.टी. में और मेंस में दोनों जगह खुलेआम धांधली हुई है । अखबार में छपा और सोशल मीडिया में उसका सबूत घूम रहा है । उसमें स्टूडेंट्स को न तो क्वेश्चन पेपर दिया गया और न कार्बन कॉपी जो एम.आर. शीट की थी वह उनको दिया गया और न तो रिजल्ट के प्रकाशन में कोई कट औफ दिया गया है और न तो कोई मोड्ल आंसर शीट दिया गया है । एक इंकवायरी हो और वह बहाली रद्द हो ।

सभापति ( श्री प्रेम कुमार ) : आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी ।

श्री अख्तरुल ईमान : माननीय सभापति महोदय, मैं इस वकत बिहार की तालिमी पॉलिसी और शिक्षा के कटौती बजट के तारुफ से जनता की पीड़ा और मौजूदा वक्त बिहार की तालिमी सूरत-ए-हाल पर अपने ख्यालात के इजहार के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं मंत्री जी को मोबारकवाद देता हूँ ये संजीदा आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं और अबकी बार बजट में अच्छा खासा पैसा भी दिया गया है हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के गरीबों, दलितों, पिछड़ों और एस.सी., एस.टी. के बच्चों के तालिम के लिए काम करने में अपना दयानतदार का रोल अदा करेंगे । लेकिन मुझे शक है कि 2014-15 में बजट का 18.8 फीसदी पैसा दिया गया था और 2020 में उसमें 1 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है । महोदय, मैं जरा सरकार को कुछ आईना दिखाना चाहता हूँ अगर इसको सुनने की शक्ति है और वह यह है कि 2012-13 में 154 लाख बच्चों का इनरौलमेंट था, 2018-19 में घटकर 141 लाख 3.5 का हो गया है यानी 1 करोड़ 41 लाख बच्चों का यानी 10 लाख बच्चों की कमी आयी है आखिर सरकार एजूकेशन पर काम कर रही है तो ऐसा क्यों है ? इस वक्त न्यू एजूकेशन पॉलिसी की बात कही जा रही है । 30 बच्चों पर एक टीचर की बात कही जा रही है और पटने में 53 बच्चों पर

और 51 बच्चों पर मुंगेर में और पूर्णिया में 75 बच्चों पर एक टीचर है और हमारे यहाँ हफनिया हाई स्कूल में 6 सौ बच्चों के लिए सिर्फ दो टीचर है यह कहाँ का पैमाना है । हम यह बात बताना चाह रहे हैं । महोदय, टीचरों की कमी है । आप तालिम के लिए बेहतर सोच रहे हैं तो टीचरों का स्वागत करना चाहिए । उसे डंडे मार रहे हैं । जो लोग टी.ई.टी. पास किए हैं क्वालिफाई किए हैं उनकी बहाली का रास्ता साफ होना चाहिए । उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हुई उनको बहाल करना चाहिए तालिमी मरकज के टीचरों को मत हटाईये । ट्रेनिंग कॉलेज में उर्दू टीचरों की कमी है उनको बहाल कीजिये । आपने क्या किया । मदरसा एजूकेशन के बारे में, अकलियत के बारे में हुकूमत संजीदा है तो 2459 प्लस एक एक जुमले के 814 मदरसे में जिसिके बारे में डी.ई.ओ. की रिपोर्ट आ गयी है, आज सरकार उनको मानदेय नहीं दे रही है ऐसा क्यूं कर रही है । हाई कोर्ट ने मदरसे के टीचरों को पेंशन देने की बात कही है । उसके बावजूद भी आप पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है । वित्त रहित पॉलिसी अभी खत्म नहीं हो पा रही है तो बिहार का तालिमी इंतजाम किधर जा रहा है । बिहार में अकलियतों की हालत उर्दू आबादी की हालत सबसे खराब है और उर्दू आबादी के तारुफ से सरकार का यह दोहरा रवैया क्यों हैं । अभी इन लोगों ने एक लेटर जारी किया है जिस लेटर के जरिये से मई, 2020 में लेटर नंबर 779 के जरिये से इसमें उर्दू सब्जेक्ट को औप्शनल सब्जेक्ट करार दे दिया है और उर्दू की पढ़ाई का रास्ता बंद कर दिया है । 2006 में इसी सरकार ने फारसी को बंद कर दिया, उर्दू सरकार की दूसरी सरकारी जुबान है और बिहार के तकरीबन दो करोड़ लोगों की मादरी जुबान है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान की बुनियादी तालिम उर्दू में दी जायेगी । लेकिन उर्दू, महोदय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अख्तरुल ईमान : यह पीड़ा की बात है, आप शिक्षा के प्रेमी है शत्रु नहीं है आपको सुन लेना पड़ेगा । गवर्नमेंट लायब्रेरी में उर्दू जानने वाले की अबतक बहाली नहीं हुई है । समसुल होदा पुराना मदरसा है वहाँ पर 9 टीचरों की जगह पर 3 टीचर है। जूनियर सेक्शन में 12 टीचर की जगह पर एक टीचर है । उूर्द तहकीकात अरबी और फारसी में टीचरों की कमी है । उूर्द की छपाई नहीं हो रही है । महोदय, आपको पीड़ा सुननी पड़ेगी ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार ) : आपका समय समाप्त हो गया है । कृप्या बैठ जांय । माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार जी ।

श्री अनिल कुमार : सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग के 2021 के बजट के माध्यम से मांग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं शिक्षा बजट के समर्थन में अपनी पार्टी की तरफ से बोलने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने कुशल नेतृत्व में किस तरह चौपट हो चुके शिक्षा व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का काम किया वह अत्यंत सराहनीय है । महोदय, शिक्षा का हाल क्या हो गया था । सूबे बिहार 2005 के पूर्व कैसा था यह किसी से छिपा नहीं है । महोदय, 2005 के पहले कोई ऐसा बिहार में संस्थान नहीं था जहॉं बिहार के बच्चे पढ़ते, अच्छे डिग्री लेते और न बिहार के बाहर के बच्चे आते थे । बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर पढ़ते थे जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता था लेकिन उसी बिहार में हमारी सरकार ने दर्जनों संस्थान खोल कर देश भर के बच्चे को पढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर देने का किया है । उदाहरण के तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय , चाणक्या लॉ कॉलेज , आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय , चाणक्या लॉ कॉलेज, आई.आई.टी.,पटना, ट्रिपल आई. टी. भागलपुर सहित सात निजी विश्वविद्यालय, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सहित राष्ट्रीय स्तर मैनेजमेंट संस्थान, बोधगया में खोले हैं । महोदय, इन संस्थानों में जाकर देखें तो देश भर के बच्चे चाहे तमिलनाडु हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हों , चाहे पश्चिम बंगाल हो देश भर के बच्चे बिहार के इन छात्रावासों में रह रहे हैं और अध्ययन का काम कर रहे हैं । एक शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का जो देश भर में कोई नाम नहीं सुनना चाहता था पूरे देश के बच्चों को देश भर में  हीन भावना से देखता था ।

क्रमशः

टर्न-24 /अभिनीत/पुलकित/03.03.2021

(क्रमशः)

श्री अनिल कुमारः पूरे देश के बच्चों को देशभर में हीन भावना से देखा जाता था । आज देशभर के दो-चार संस्थान, मद्रास में हो, मुम्बई में हो, दिल्ली में हो इन जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना का नाम रौशन हुआ है, पूरे देश में नाम रौशन हुआ है । 58 वर्षों तक बिहार में कोई संस्थान नहीं खुला था जहां बिहार के बाहर के बच्चे आकर पढ़ते हों, सिर्फ बिहार के बच्चे पलायन करते थे । महोदय, 2005 में जहां शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपये था आज 37,357 करोड़ है । वर्तमान में कुल बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा केवल शिक्षा पर खर्च हो रहा है जो पूरे देश में सर्वाधिक है । 2005 में साढ़े 12 प्रतिशत बच्चे जहां स्कूल से बाहर थे, आज मात्र एक

प्रतिशत बिहार के बच्चे स्कूल से बाहर हैं और उसके लिए भी अभियान चलाकर बच्चों का नामांकन कराया जा रहा है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आपका समय समाप्त हुआ, बैठ जाइये ।

श्री अनिल कुमार: एक मिनट महोदय, जहां 19 हजार 641 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया । महोदय, अनेक कार्यक्रमों के माध्यमों से शिक्षा का विस्तार हो रहा है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य अब आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार: सभापति महोदय, मैं शिक्षा बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूँ । अभी सरकार की तरफ से बहुत सारे हमारे मित्रों ने लंबी-लंबी बातें की हैं । मैं उनको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ कि सरकार ने फैसला लिया था हर बच्चे के नामांकन की हम गारंटी करेंगे और उसके लिए हर मुहल्ले में, उनके अपने मुहल्ले में स्कूल खोलने का फैसला लिया था । सरकार ने फैसला तो लिया लेकिन उसको भवन और जमीन नहीं दी जिस कारण सरकार ने खुद ही 1700 प्राथमिक विद्यालयों को डिमोलिस कर दिया, किसी बगल के स्कूल में उसको पोजेस्ट कर दिया और बच्चों को स्कूल जाने से रोकने का काम किया है । हम यह बताना चाहते हैं कि 3 हजार हाईस्कूल अपग्रेड किये गये लेकिन सरकार ने उसके लिए प्रबंधन की कोई कार्रवाई नहीं की । इसके लिए न विद्यालय, न शिक्षक और न उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की । नतीजा यह हुआ, मैं एक स्कूल का नाम लेकर कहना चाहता हूँ, गंगोली विभूतिपुर में एक स्कूल है जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, एक क्लास है, 9th और 10th की पढ़ाई अब वहां होगी लेकिन कहां पढ़ाई होगी । 9th के बच्चें तो बैठते हैं लेकिन 10th के बच्चे कहां बैठेंगे । क्या वे खेत में जाकर पढ़ेंगे ? सरकार को जवाब देना चाहिए...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य अब आप बैठ जायं । आपका समय समाप्त हो चुका । माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव जी ।

श्री अजय कुमार: मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ । 2014-15 विभूतिपुर में एक बसौना हाईस्कूल खोला गया था लेकिन आज तक उस स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): कृपया आप अब बैठ जायं । श्री मुकेश कुमार यादव जी ।

श्री मुकेश कुमार यादव: सभापति महोदय, मैं सदन में विपक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के लिए लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, सबसे पहले मैं गरीबो के मसीहा, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के उद्धारक, बेजुबानों के जुबान आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जिन्होंने मुझ जैसा अदना सा छोटा किसान के बेटा को इस सदन में पहुंचने व खड़ा होने का मौका दिया । महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुख्य सचेतक श्री ललित कुमार यादव जी का जिन्होंने मुझे बोलने हेतु समय दिया है । मैं आभार प्रकट करता हूँ 27 बाजपट्टी विधान सभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का जिन्होंने मुझ पर अटूट भरोसा और विश्वास जताया ।

महोदय, आज शिक्षा के बजट की खामियों के बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ-

''शिक्षा है प्रकाश समाज का,
जिससे जीवन जगमग होता है ।
मुस्कुराता है ज्ञान जहां,
अज्ञान भाग्य पर रोता है ।''

महोदय, ठीक इसके विपरीत आज बिहार में शिक्षा की दशा को देखकर जगहंसाई हो रही है ।

'जब से एन0डी0ए0 की सरकार आयी है, शिक्षा की जगहंसाई है । गुरू को बना दिया गया खिचड़ी, शिक्षा विद्यालय से गायब है ।'

सभापति महोदय, वर्ष 1990 से 2005 तक सात नये विश्वविद्यालय बनाये गये जबकि इनके शासकाल में 2005 से 2020 तक मात्र दो विश्वविद्यालय बनाये गये । महोदय, 1990 से 2005 के बीच बी0पी0एस0सी0 से 60 हजार शिक्षकों की बहाली हुई थी, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हैं और आज भी ये शिक्षा की रीढ़ कहे जाते हैं । महोदय, 1990 से 2005 के बीच विश्वविद्यालयों की सूची में देश स्तर पर पटना विश्वविद्यालय का अपना महत्वपूर्ण स्थान था जो आज अस्तित्वविहीन हो चुका है । महोदय, शिक्षक, गुरू का स्थान काफी ऊंचा और सम्मानीय होता है । महोदय, 1990 से लेकर 2005 तक जब कोई शिक्षक रास्ते से गुजरते थे तो लोग उनको काफी सम्मान करते थे, ठीक उसके विपरीत आज समाज में उनकी मर्यादा काफी कम हो गयी है, जिसका एक मात्र कारण यह सरकार है । महोदय, आपने पंचायत स्तर पर मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय बना दिये हैं लेकिन उन विद्यालयों में शिक्षकों का स्थान 15, 18, 20 के अनुसार कहीं दो, कहीं तीन, कहीं शून्य है । महोदय, यह कैसी शिक्षा नीति है । महोदय, यह सरकार गरीबों, शोषितों को शिक्षा नहीं देना चाहती है । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं सरकार एक भी सरकारी विद्यालय बताये जहां किसी विधायक, सांसद, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा उस सरकारी विद्यालय में पढ़ता है । महोदय, मैं सत्ता पक्ष के

उन माननीय विधायकों से जो मेज थपथपाते हैं पूछना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा नीति ठीक है तो आप अपने बेटे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार यादव जी आपका एक मिनट समय बचा है ।

श्री मुकेश कुमार यादव: सभापति महोदय, अभी पांच लाख से ऊपर शिक्षकों के पद रिक्त हैं, यह कैसी शिक्षा नीति है । महोदय, मैं शायर इकबाल की एक शायरी को बोलकर अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं ।

''रजिलों की रजालत से शरीफों की, शराफत कम नहीं होती
करो सोने के सौ टुकड़े, पर कीमत कम नहीं होती । ''

सभापति महोदय, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सोना का वह टुकड़ा है जिस पर आप जितना प्रहार करेंगे चमक उतनी बढ़ेगी और उनके नेतृत्व में बिहार की जनता के हित में हम लोग आपकी गलत शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करते हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री लखेंद्र कुमार रौशन जी, आपका समय 9 मिनट है ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: सभापति महोदय, इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रथम बार सदस्य होने के नाते मुझे खड़ा होने का मौका मिला है, इसके लिए मैं सबसे पहले वैशाली जिला के पातेपुर की जनता और अपनी पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, साथ ही इस सदन के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं । महोदय, जब मैं सदन से, जब छोटे सदन जिला में था तो उस समय हमलोगों के मन में, जो नए विधायक बनकर आये हैं, हमलोगों के मन में एक ललक होती थी कि जब भी कभी राजनीतिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, जब हमको मौका मिलेगा बिहार के उच्च सदन में जाने का तो उच्च सदन में जाकर निश्चित रूप से अपनी मर्यादा का पाठ पढ़ने का काम करेंगे । मैं जब इस सदन में पातेपुर की जनता और अपनी पार्टी के आशीर्वाद से आया और इस सदन में आकर जनता की आवाज बनकर अपनी बातों को रखने का जब मौका मिला तो मैं देखता हूं, एक चीज लिखी हुई है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग होते हैं, यह किताब में भी हम पढ़ते थे ।

मैं नमन करता हूं देश के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिन्होंने कहा था कि देश के दलितों शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो । महोदय, मैं विपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष में भी बहुत सारे नए सदस्य जीतकर आये हैं और जब विपक्ष के नए सदस्यों को भी मौका मिलता है तो एक भी सत्ता पक्ष के लोग आपकी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी सभ्यता, संस्कृति सीखिए । हम नए लोग जीतकर आये हैं, थोड़ा-सा आपसे भी सीखने का मौका हमको

मिलेगा । महोदय, देश में आजादी से लेकर 1990 तक बिहार में, साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार थी ।

(क्रमशः)

टर्न-25/हेमन्त-धिरेन्द्र/03.03.2021

...क्रमशः...

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : हमें लग रहा है कि 1967 से 1980 तक, बीच में छोड़ दिया जाय तो 57-58 वर्षों तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन 58 वर्षों में 20 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं लेकिन 1990 के बाद 95 के बाद 2005 तक बिहार में एक ही दल आर0जे0डी0 की सरकार रही है और मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं । यदि कांग्रेस के सत्र को और माननीय लालू जी के सत्र को जोड़ दिया जाय, तो 72 वर्ष बिहार में शासन करना और शिक्षा में सुधार करने के लिए एक बहुत-सा समय होता है लेकिन 72 वर्षों में, महोदय यदि इनके द्वारा 70-72 वर्षों में

(व्यवधान)

बैठ जाइये, बैठ जाइये...

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : महोदय, 72 वर्षों में विकास करने के लिए यदि....

(व्यवधान जारी)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जायं आप लोग ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : मैं गरीब का बेटा, मैं अपने क्षेत्र से आया हूं, महोदय...

(व्यवधान जारी)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : महोदय, हम लोग बोरा, मैट पर जब स्कूल में पढ़ते थे, तो मैट बिछाते थे अपने गांव के स्कूलों में....

(व्यवधान जारी)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जायं ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : और मैट बिछाकर, अपने झौला में बोरा लाते थे, महोदय, और बोरा बिछाकर पढ़ने का काम करते थे गांव के स्कूलों में । गांव के स्कूलों में जब बैग से बौरा निकालते थे, तो उस समय मन में एक जज्बा होता था कि काश विद्यालय में बैंच होती,

तो हमें अपने बैग से बोरा निकालकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती । महोदय, यदि विद्यालय में भवन होता तो एक टूटी हुई झोंपड़ी और चरवाहा विद्यालय में बैठने का मौका हमको नहीं मिलता । महोदय, उस समय अपने बैग में बोरा लेकर आते थे । हम लोग गरीब परिवार से आते हैं । महोदय, उस गरीब परिवार से आते हैं, मैं बताता हूं । मैं अपनी पंचायत में, अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सदन को, प्रतिपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि टूटे हुए चश्मे के आइने से कभी आपको विकास दिखाई नहीं देगा । यदि बिहार में विकास ही देखना है, तो अपने टूटे हुए चश्मे का आइना ही बदल लो, तब आपको विकास दिखाई देगा । महोदय, 72 वर्षों का जब इनका शासन था, तो उस समय बिहार में, 2005 में जब शिक्षा का बजट था, तो उस समय 2005 में 4366 करोड़ रुपया शिक्षा में बजट आता था । लेकिन आज एन0डी0ए0 की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र मोदी जी की छत्रछाया में बिहार का जो विकास हुआ है, महोदय, आज बिहार का बजट 37 हजार 357 करोड़ रुपया है । महोदय, यह शिक्षा में विकास करने के लिए कम नहीं है, यह बहुत है । महोदय, जब बिहार में कांग्रेस और आर0जे0डी0 की सरकार थी, उस समय विद्यालय में भवन नहीं थे । महोदय, उस समय विद्यालय में, हमारे और आपके गांव की बच्ची आज जब विद्यालय में पढ़ने जाती है, तो हम जब गांव में रहते हैं, तो देखते हैं कि विद्यालय के लिए गांव से एक सैंकड़ा में हमारे घर की बच्ची जब साइकिल से निकलती है तो लगता है कि विद्यालय के प्रति सरकार की सोच दिखायी दे रही है । महोदय, जब आज.. ...

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया बोलने दीजिए उनको, बैठ जायं ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : जिस चरवाहा के ये लोग प्राजेक्ट हैं, वह चरवाहा विद्यालय के अलावा और कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं । महोदय, आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जब ये लोग सत्ता में थे तो बिहार में विद्यार्थियों को, जो गरीब-गुरबा हैं, चाहे वह किसी भी समाज के विद्यार्थी क्यों न हों, उसको पढ़ने के लिए, जिसके गार्जियन, जिसके माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये जो असहाय महसूस करते थे, उनके लिये सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लायी और बिहार में गरीब के बच्चे भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं । महोदय, यह एन0डी0ए0 की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । महोदय, वर्ष 2005 में, शिक्षा की स्थिति में, जिस समय बिहार में बच्चियां पढ़ने के लिए घर से बहुत कम निकलती थी और आज रिजल्ट देख लीजिये, सदन में जो मेम्बर बैठे हुए हैं, इनके टोले पड़ोस में और घर की ही बच्चियां पढ़ रही हैं।

कलेजे पर हाथ रख कर बोल दें, यदि इनके घर के बगल की बच्चियां आज लड़कों की अपेक्षा अच्छा रिजल्ट नहीं करती होंगी ।

महोदय, आज बिहार में शिक्षा की स्थिति में जो सुधार हुआ है, कभी-कभी ईमानदारी की बात भी बोलनी चाहिये लेकिन विपक्ष को केवल ईमानदारी की बात बोलना नहीं है, टूटे हुए चश्मे से केवल विकास का आइना इनको दिखाई नहीं देगा । इसलिए, आज बिहार के अंदर....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया बैठ जायं ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, प्रथम बार जीत कर आये हैं, नये लोग हैं, आपका संरक्षण चाहिये। केवल एक मिनट ।

महोदय, आज बिहार सरकार ने और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के शिक्षा मंत्री जी को । ईमानदारी से विपक्ष के लोग भी बोलेंगे तो इनको लगेगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री बहुत ही स्वज और सहज हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार को शिक्षा मिली है । अब माननीय महोदय, अभी जो बच्ची पढ़ती है उसको 25 हजार रुपया और जो अविवाहित महिला ग्रेजुएशन करती हैं उसको 50 हजार रुपया सरकार ने देने के लिये निर्णय लिया, यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है । महोदय, विपक्ष को केवल हंगामा खड़ा करना है, अगर उतना ही समय यदि पॉजिटिव सोच लेकर अपने क्षेत्र में विकास की बात करें, लोगों को बतायें कि अपने बच्चों को पढ़ाइये और अपनी बच्चियों को पढ़ाइये । आपकी बच्चियों को भी साईकिल मिलेगी...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप आसन ग्रहण करें ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, आपकी बच्चियों को भी 25 हजार और 50 हजारा रुपया का लाभ मिलेगा, तो वह बहुत ऊपर की सोच है । महोदय, हमें मौका मिला इसके लिए मैं आपको, सदन को, अपनी पार्टी को और साथ में विपक्ष को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, श्री सुर्यकान्त पासवान जी ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ । महोदय, राज्य सरकार द्वारा लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की जा रही है, यह जनता के साथ महज एक धोखा है । महोदय, एक रिपार्ट के मुताबिक बिहार में मात्र 13.6 फीसदी छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, मैट्रिक तक आते-आते 30 फीसदी छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं । महोदय, राज्य के करीब 96.4 फीसदी विद्यालयों में शिक्षक और छात्र का अनुपात ठीक नहीं है, करीब 52.3 फीसदी विद्यालयों में शिक्षक और कक्षा का अनुपात ठीक नहीं है । महोदय, विद्यालयों में शौचालय, 45 फीसदी विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं हैं । महोदय, विद्यालय में 39 फीसदी प्राथमिक स्तर के और 35 फीसदी

माध्यमिक स्तर के शिक्षक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं । महोदय, एक समय में, विश्व को नालंदा और विक्रमशीला जैसे अद्वितीय विश्वविद्यालय देने वाली बिहार की धरती पर, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों की हालत कैसी है, आज किसी से छिपा हुआ नहीं है । महोदय, हमारे विश्वविद्यालयों में न तो शिक्षक हैं और न ही मूलभूत संसाधन । हमारे विश्वविद्यालय...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया । कृपया बैठ जायं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमारे विश्वविद्यालय आज महज डिग्री बांटने का मसीहा बन कर रह गये हैं..

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया । कृपया बैठ जायं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, विश्वविद्यालय में नया नेटवर्क संचालन तो दूर, समय पर परीक्षा भी नहीं हो रही है । अंत में, मैं आपके माध्यम से सरकार....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : पासवान जी, आप बैठ जाइये । श्री पंकज कुमार मिश्र जी ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बजट के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ । आज मैं धन्यवान देना चाहता हूँ अपने पार्टी के नेता को और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने बोलने का मौका दिया ।

...क्रमशः...

टर्न-26/सुरज-संगीता/03.03.2021

...क्रमशः...

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पार्टी के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे लोगों को टिकट दिया, छोटे लोगों को और आज मैं रून्निसैदपुर विधानसभा से जीत कर मैं आज सदन में आने का काम किया हूं, उसके लिए मैं अपने पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज बोलने का मौका हमको दिए । माननीय श्रवण बाबू उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य के विकास को अगर देखना है तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि उस राज्य में शिक्षा की उन्नति के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गये हैं । वर्ष 2005 में जहां शिक्षा का बजट 4 हजार 366 करोड़ रुपये था, आज बढ़ करके वर्ष 2020-21 में 37 हजार 357 करोड़ रुपया हो गया है यह बजट प्रमाणित करता है कि हमारी सरकार शिक्षा के गुणात्मक सुधार और सर्वव्यापी बनाने के लिए संकल्पित है । वर्ष 2005 से पहले नारी शिक्षा पर पिछली सरकार का ध्यान गया ही नहीं । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही बिहार में शिक्षा के क्रांतिकारी

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात बालिका पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के कारण आज की बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ा और आज जो हमारी जो बच्चियां हैं जब रोड पर चलती हैं झुण्ड बांध करके, घंटी बजाते हुए जब चलती हैं हमारी सरकार में तो लोग जब देखते हैं, विपक्ष अपने आईने में देखे क्योंकि उनके भी क्षेत्र से वह बच्चियां चलती हैं और आज हमारी सरकार की यह उपलब्धि है । महोदय, बेटियां आज पूरे विश्वास के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, स्मार्ट वर्ग प्रारंभ कर दिया गया है । वर्ष 2005 से पहले हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए बच्चों को भारी पैदल चलना पड़ता था आज हर पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना हो गई है । जहां शेष डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से छात्रों की राशि सीधे उनके खाते में जा रही है । बिहार में आज भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्र-छात्राओं को ऋण दिया जा रहा है ताकि धन के अभाव में किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित न हो सके । आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पहले गर्व होता था यह बिहार के स्वाभिमान का प्रतीक है । नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, इंटर पास बालिकाओं को 25 हजार रुपया जबकि बी0ए0 पास बालिकाओं को 50 हजार रुपये सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जिसकी सराहना हो रही है । शिक्षा संस्थान के आधार पर सुदृढ़ किया जा रहा है । वर्ष 2005 की तुलना में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है । नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो बिहार को सम्मान दिलाता है ।

''कदम थके नहीं झुके नहीं
अभी कहां आराम बदा, यह मौन निमंत्रण छलना है
अरे अभी तो मिलों मुझको, मीलों मुझको चलना है ।''
बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन जी, आपका समय 2 मिनट है ।

श्री इजहारूल हुसैन : बहुत-बहुत शुक्रिया माननीय सभापति महोदय कि आपने हमें पहली बार शिक्षा बजट कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया और खासकर मैं किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की सभी जनता का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से आपकी आवाज बनकर मैं यहां सदन के पटल पर खड़ा हूं । आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं हमेशा आपकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूं और आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं । महोदय, मैं इजहारूल हुसैन किशनगंज विधानसभा से निर्वाचित होकर आया हूं जो बिहार

ही नहीं बल्कि पिछड़े सीमांचल का आखिरी जिला है । महोदय, मैं अपनी बात इस शायरी से आरम्भ करता हूं ।

''बहुत रंजिश है यहां लोगों के दरमियान
मुनासिब है हर शख्स को प्यार चाहिए।
बहुत ऊंची है यहां मजहबों की दीवारें,
इसे गिराने को शिक्षा का हथियार चाहिए ।''

महोदय, किशनगंज जिला जो 1884 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 7 प्रखण्ड है, यहां की आबादी लगभग 18 लाख से अधिक है । बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार इन दावों पर विफल है । शिक्षा के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर चल रहा है तो बिहार का किशनगंज भी प्रदेश का सबसे निरक्षर जिला है । 18 लाख से अधिक की आबादी में लगभग 2 लाख के करीब युवा हैं, जिसमें मात्र दो डिग्री कॉलेज हैं । एक मारबाड़ी कॉलेज और दूसरा जवाहर लाल नेहरू डिग्री कॉलेज । जवाहर लाल नेहरू कॉलेज जो बहादुरगंज प्रखण्ड में स्थित है । यहां 4 शिक्षकों के सहारे करीब 3 हजार छात्र अध्ययनरत हैं वहीं मारबाड़ी कॉलेज जो किशनगंज मुख्यालय में स्थित है, इसकी स्थापना 1960 ई॰ में हुई थी। कॉलेज में कुल 17 विभाग हैं, यहां 34 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं जहां मात्र 10 शिक्षकों के सहारे लगभग 8 हजार छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं । इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस डिग्री कॉलेज में 17 विभागों की पढ़ाई मात्र 10 शिक्षकों के सहारे चल रही हो तो शिक्षा का स्तर क्या होगा ? महोदय, यही समस्या डा॰ कलाम कृषि महाविद्यालय की है जहां स्वीकृत 42 पदों के एवज में 16 शिक्षकों तथा फिशरी में 80 स्वीकृत पदों के एवज में मात्र 8 शिक्षक कार्यरत हैं...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप कृपया बैठ जायें । आपका समय समाप्त हो गया । माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव जी ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, खासकर मैं किशनगंज के वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि.....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप हुसैन साहब बैठ जायें ।

श्री इजहारूल हुसैन : आपने हमारे यहां अबुल कलाम कृषि महाविद्यालय खोलकर एक सराहनीय कार्य किया है जो हमारा ही नहीं पूरे बिहार का एक धरोहर है.....

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जायें आप । आसन ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हो गया है । माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव ।

श्री मिश्री लाल यादव : मान्यवर अध्यक्ष जी, राज्य के महत्वपूर्ण विषय शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर दिया गया इसके लिए मान्यवर अध्यक्ष जी को और सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं । महोदय, आज शिक्षा पर, शिक्षा बजट पर वाद विवाद हो रहा है....

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, मुझे और समय दिया जाय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : समय तय था, उसी समय के हिसाब से आपको समय दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, मुझे मालूम है जो 3 मिनट है और मैं बताना चाहता हूं आज वास्तविक में सभी क्षेत्रों में बिहार सरकार का चहुमुंखी विकास चर्चा में है । मैं शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं । महोदय, मैं भी गांव गवंई से आया हूं और मैं जिस गांव में रहता था वहां से लगभग 5 किलोमीटर पर एक हाईस्कूल था और फिर दूसरा हाईस्कूल भी 5 किलोमीटर पर था, हमलोगों को जाने में बड़ी परेशानी होती थी । आज मान्यवर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज हमें अपार खुशी है जो हरेक पंचायत में एक हाईस्कूल खोलकर गरीब के बच्चों को गांव में पढ़ने का मौका दिया है । महोदय, मैं बताना चाहता हूं जो आपको मालूम होगा जो पहले बच्चियां किसी भी सामान्य परिवार की हों, सतवां, अठवां, छठा मैट्रिक तक कोई पास नहीं कर पाती थीं । महोदय, हमें आज अपार खुशी है कि बिहार सरकार के नेतृत्व में साईकिल योजना, पोशाक योजना चलाकर तमाम बच्चियों को प्रोत्साहन दिया, आज कोई घर बाकी नहीं है जिसकी बेटियां मैट्रिक और आई0ए0 पास करके देश दुनिया में नाम रौशन नहीं कर रही हैं बिहार का । महोदय, मैं बताना चाहता हूं वही नहीं आपको मालूम होगा सदन को, सारे साथियों को मालूम होगा कि आज की तारीख में जब हमारी बेटी, हमारी बहनें साईकिल पर बैठ जाती थीं तो समाज के लोग ऊंगली उठाते थे लेकिन मान्यवर नीतीश कुमार जी ने उन बच्चियों को साहस दिया और बच्चियों को साईकिल देकर पढ़ाने का काम किया । आज हजारों की हजार संख्या में पूरे बिहार की सड़कों पर झुंड बनाकर लड़कियां चलती हैं । मान्यवर अध्यक्ष जी, एक ओर जहां हमारी बच्चियां ऊंची शिक्षा प्राप्त करती हैं साईकिल पर चढ़कर और सर्टिफिकेट के आधार पर सेना में बहाल होती हैं । एक तरफ साइकिल चलाती और एक तरफ हिंदुस्तान के बॉर्डरों पर अपने दुश्मनों को गोली चलाकर छाती को छलनी करती हैं, नारी सशक्तिकरण भी यहां हुआ है । महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इंटर जो पास महिलाएं हैं, लड़कियां हैं उनको 25 हजार रुपया देने का सरकार ने संकल्प लिया है और बी0ए0 पास करने पर 50 हजार रुपया । महोदय, वर्ष 2020-21 के बजट पर सरकार ने स्पेशली इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट इसमें प्रावधान किया है ।

टर्न-27/ मुकुल-राहुल/03.03.2021

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया आप बैठ जायं ।

श्री मिश्री लाल यादव: महोदय, हम अपनी बात को समाप्त करेंगे और यह बात कहूंगा कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एन0डी0ए0 के नेतृत्व में शिक्षा ही नहीं पूरी योजनाओं में चहुंमुखी विकास हो रहा है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री उमाकांत सिंह जी ।

श्री उमाकांत सिंह: सभापति महोदय के द्वारा आज पहली बार इस विधान सभा में बोलने का मौका मिला, पहली बार टिकट मिला, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार मौका मिला । इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल जी और पार्टी के शीर्ष नेता माननीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, नीतीश कुमार जी और एन0डी0ए0 की सरकार के द्वारा यह मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, मैं जहां से आता हूं पश्चिम चम्पारण की धरती, वाल्मीकि की तपोभूमि, सीता की शरण स्थली और लव-कुश की जन्मभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि में चनपटिया विधान सभा की जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं । महोदय, जब हम सभी लोग शपथ ग्रहण लेते हैं और शपथ ग्रहण में जो बातें हम लोग कहते हैं, उन्हें सदन में हम लोग भूल जाते हैं । महोदय, सांसद, विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन महोदय, एक अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है इसलिए कि :-

''इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है,
लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है ।
यूं ही नहीं लोग जाते मंदिरों में,
आस्था तो पत्थर को भगवान बना देती है ।''

मित्रों, इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि:-

''लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और,
बिना कुछ किये जय-जयकार नहीं होती ।''

मित्रों, 15 साल आपने सरकार चलाया और 15 साल हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी के समर्थन में एन0डी0ए0 गठबंधन की सरकार चली । माननीय मैं आपको 15 साल आपकी और 15 साल मेरी बात थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं । माननीय महोदय, विगत वर्षों में जब हमारी एन0डी0ए0 की सरकार आई तब शिक्षा की उन्नति के लिए अनेकों ठोस कार्य किये गये, जब वर्ष 2005 में बिहार की जनता ने राजद, कांग्रेस की सरकार को नकार दिया उस समय जहां शिक्षा का बजट 4,336 करोड़

था आज वह बजट एन0डी0ए0 की वित्तीय वर्ष 2021-22 में 38035.93 करोड़ रुपया हो गया । महोदय, वर्ष 2005 में जब इनकी सरकार थी तो साढ़े 12 परसेंट विद्यार्थी प्रति वर्ष विद्यालयों में ग्रहण से वंचित थे आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में दृढ़संकल्प के कारण वर्तमान में केवल एक प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी विद्यालयों में ग्रहण से वंचित रह गये हैं । महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार बहुत शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में सफलता प्राप्त करेगी । महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चहता हूं कि राजद, कांग्रेस के 15 वर्षों के शासनकाल में जहां 10 हजार शिक्षकों की नियुक्ति, बहाली हुई थी वहीं इस एन0डी0ए0 गठबंधन की सरकार में बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं जो साढ़े तीन लाख शिक्षकों की नियुक्ति और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की गई । महोदय, मैं सदन के माध्यम से हमारी एन0डी0ए0 की सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों का आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं, वर्ष 2005 में राज्य में केवल लगभग 2,800 हाई स्कूल थे वहीं महोदय वर्ष 2021 में हाई स्कूलों की संख्या 6,300 हो गई और साथ ही लगभग 2,948 ऐसे विद्यालय हैं जहां नवमी तक की पढ़ाई हो रही है । महोदय, बहुत बात चल रही है हमारे नियोजित शिक्षकों की बात की बहुत नुमाइंदगी यह सरकार कर रही है । महोदय, वर्ष 2003 में हम जब मुखिया थे और इन्हीं के आदेश से हम लोगों ने शिक्षा मित्रों की बहाली की थी, उस समय इन्हीं के आदेश से 1500 रुपया हम लोग उनको सालभर-दो साल पर वेतन देते थे । वह 1500 रुपया दो महीना का वेतन आता था और कैसे शिक्षक पढ़ाते थे आप महोदय सोच नहीं सकते थे । 3,000 रुपया दो महीना का, 4500 रुपया तीन महीना का साल दो साल पर पैसा आता था तब हम लोग उनको वेतन देते थे, तनख्वाह देते थे, उस समय हम लोग मुखिया थे । महोदय, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2005 में सत्ता संभालकर वर्ष 2006 में जब उन्होंने बजट पेश किया तो उस समय 1500 रुपया शिक्षा मित्रों को जो वेतन मिलता था और जो बी0पी0एस0सी0 से एग्जाम देकर के वर्ष 1994 के टीचर आए थे ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, उनको वर्ष 2006 में 18,000 रुपया, 20,000 रुपया वेतन मिलता था उनका वेतन बढ़कर चौगुना हो गया, 80,000/-, 75,000/- हो गया । महोदय, आज उन शिक्षकों का वेतन बढ़कर, 1500 वालों का 30,000/- हो गया, जिनकी हिमायत कर रहे हैं जो 1500 रुपया वेतन देते थे और जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं हमारे भाईसाहब माले माकपा के माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि ऐ सुअर चराने वाले, ऐ बकरी चराने वाले, ऐ गय्या चराने वाले । उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी बोलते थे कि ऐ सुअर चराने वालों, ऐ गय्या चराने वालों, ऐ बकरी चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो । विद्यालय में

भवन नहीं थे, शिक्षक नहीं थे और छात्र भी नहीं थे, ऐसे विद्यालय थे, ऐसी इनकी व्यवस्था 15 साल में थी । आज जिस रोजगार की, 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं । महोदय, जो 10 दस लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, हमारे बिहारी कलाकार गाना बनाए थे कि मिल नहीं रही है नौकरी ये कैसी सरकार है, यह देखो एम0ए0 करके बकरी चरा रहे हैं, बाप रे बाप ऐसी सरकार थी कि भोजपुरी कलाकार पूरा गाना बनाये थे जहां गड्ढा-गुड्ढी आए समझिए कि बिहार आ गया और जगह-जगह पर जात पूछा जाने लगा, गरीबों की रोटी छिनाने लगा । ऐसा ऐसा गाना बिहार में और यहां बैठते हैं भोजपुरी कलाकार विनय बिहारी ये भी गाना बनाए थे और मनोज तिवारी सारे लोग गाना बनाये थे । उनकी जो बात कर रहे हैं हमलोग बिहार से बाहर जाते थे तो हमलोग अपमानित होते थे XXX

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये बैठ जाइये आपकी बात बहुत देर से हम सुन रहे थे आप बैठ जाइये । बिहार का जो बखान हमलोग करते थे, लोग पूछते थे कि कहिये बिहार का क्या हाल चाल है । महोदय, हमलोग कहते थे उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, बीच में नरसंहार है, युवक बेरोजगार हैं, कर्मचारी लाचार हैं, व्यवसायी फरार हैं, कृषि पर मिया बीबी अबसार है, यही मेरा बिहार है, यही मेरा बिहार है इसी बिहार के नाम से हम जाने जाते थे । आज शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढाई लाख कमरों का निर्माण किया है सारे विद्यालय में और उन्होंने उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इतना काम किया कि आज पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है । 15 साल में तो काम हुआ नहीं अब इनकी छाती फट रही है । जो लोग अपने बच्चे लोगों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाए अच्छी डिग्री नहीं दे पाए, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं...

अध्यक्षः अब समाप्त कीजिए ।

श्री उमाकांत सिंहः बहुत दुख की बात है इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए तमाम माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा कुछ आपत्तिजनक बातें बोली गईं हैं, उनको प्रोसीडिंग से निकाला जाय । जंगल राज और इस तरह की बातें बोले हैं उसको प्रोसीडिंग से निकाला जाय ।

अध्यक्षः वह पहले से ही निर्देशित है । अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।

---

XXX आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आज ही हमने सदन में शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग 380 अरब 35 करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि की मांग रखी थी, जिस पर सदन पिछले लगभग ढाई घंटे से विमर्श कर रहा है । महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं उन 19 माननीय सदस्यों का जिन्होंने विशेष रूप से इस विमर्श में शिक्षा विभाग की मांग पर अपनी राय रखी है । क्रमशः

टर्न-28/यानपति-अंजली/03.03.2021

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: इस विमर्श में हिस्सा लिया है । विशेष रूप से मैं उन माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहली दफा इस सदन में बोलने के लिए शिक्षा विभाग की मांग पर विमर्श का अवसर चुना है इसलिए मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जिन्होंने खुद बताया है कि वे पहली बार इस सदन में बोल रहे हैं और विशेष रूप से जो हमारे उमाकांत सिंह जी हैं या जो दो महिला सदस्यों ने शालिनी मिश्रा जी ने और संगीता कुमारी जी ने जो अपने विचार रखे और तीनों ने जिस प्रभावकारी तरीके से अपने विचार रखे हैं, मैं उनको विभाग की तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं । महोदय, हमने जैसा कि कहा 19 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । सब ने अपने-अपने सुझाव भी दिये हैं । हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कुछ सुझाव के साथ कुछ ऐसी बातें भी कहीं हैं जिसके बारे में मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा लेकिन अभी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे एक बात का संतोष है और इत्मीनान है कि जितने भी माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी हैं सब के मन में इतना जरूर है कि शिक्षा पूरे समाज के विकास की नींव है और रीढ़ है और जब तक शिक्षा में हमलोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा समाज या हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है, ये लगभग सभी की बातों से ये जाहिर हो रहा था और ये परिलक्षित हो रहा था । महोदय, इसे मैं विभाग की तरफ से शुभ संकेत के रूप में ले रहा हूं और ये भी मानता हूं उन्होंने जितनी बातें सुझाव के रूप में कही हैं मैं सभी माननीय सदस्यों को और सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि उनके सुझावों पर सकारात्मक रूप से अमल शिक्षा विभाग निश्चित रूप से करेगा क्योंकि ये सरकार की मंशा है, जिस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं ये घोषित नीति है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बढ़े भी हैं और और आगे बढ़ना चाहते हैं । पर शिक्षा के महत्व से कौन इंकार कर सकता है । खासतौर से अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं सुन रहा था, मैं एक-एक की बात गौर से सुना हूं । 19 सदस्यों ने अपने विचार रखे

हैं और सब की बात जो उनके सुझाव थे, कहीं-कहीं बोलने के क्रम में सरकार की तरफ उनकी उंगलियां भी उठ जाती थीं । अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद वह उनकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी वरना उनके दिल में भी तो कसक शिक्षा को आगे बढ़ाने की ही है जो उनके सुझावों के रूप में आई है, तो सुझावों को तो हम निश्चित रूप से जो सरकार की नीतियों पर हम अमल करेंगे, कार्यक्रम बनायेंगे उसमें हम शामिल करने की कोशिश करेंगे । महोदय, शिक्षा सब ने कहा है और भारतीय संस्कृति में हमारी आपकी जो संस्कृति है उसमें तो शिक्षा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है । शिक्षा से शिक्षित होने से जिसको कहिये ज्ञान या विद्या अर्जित करने से बड़ा कोई न पुण्य है और न इससे बड़ा कोई धन होता है व्यक्ति के पास, अगर आप शिक्षित हैं, ज्ञानवान हैं तो इससे बड़ा कोई धन नहीं है । हमारे शास्त्रों में महोदय कहा गया है कि ''विद्या धनम् सर्वधनं प्रधानम् श्रेष्ठतम् च'' । मतलब विद्या धन जो है महोदय वह सभी धन से श्रेष्ठ है, सबसे प्रधान है, सबसे अहम् है, सबसे महत्वपूर्ण है और ये कोई हम लोगों की संस्कृति की बात नहीं है । अखतरूल ईमान जी लगता है बाहर चले गये हैं, इस्लाम में भी शिक्षा का उतना ही भारी महत्व है । नेहालउद्दीन साहब बैठे हैं । इस्लाम में भी शिक्षा के आगे किसी दूसरी चीज को अहमियत नहीं दी गई है और हमारे प्रॉफेट साहब ने हुजूर साहब ने ही फरमाया कि माँ की गोद से लहद तक, मतलब कब्र तक इल्म हासिल मतलब पैदाईश से लेकर मरने तक तुम शिक्षा ग्रहण करो, ज्ञान हासिल करो, विद्या अर्जित करो क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है और स्वाभाविक रूप से जब हमारी सरकार जो पिछले समय से लगातार हम महोदय बिहार की तस्वीर और सूरत बदलने में लगे हैं तो इतना तो सरकार को एहसास है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा को हम आगे नहीं बढ़ायेंगे, हम अपने बच्चों को शुरू से शिक्षित नहीं करेंगे तो हम बिहार को तरक्की के उस मुकाम पर नहीं पहुंचा सकते हैं जो हमने अपना लक्ष्य बना रखा है और आज मुझे पूरे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है महोदय कि इसीलिए हमने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो 21.94 प्रतिशत है महोदय यह लगभग 22 प्रतिशत है इस बजट का हिस्सा जो शिक्षा विभाग पर हम खर्च करने जा रहे हैं आखिर यही तो महोदय सरकार की मंशा दर्शाता है जो हम शिक्षा को कितनी अहमियत देते हैं कितनी प्रधानता देते हैं और शायद हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह जानकर अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी कि नयी शिक्षा नीति में जो पूरे देश के लिये शिक्षा पर खर्च करने की जो सीमा या जो लक्ष्य जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत रखा गया है बिहार में शिक्षा पर खर्च का वह जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत लगभग आज ही हम प्राप्त कर चुके हैं और आज ही हम उस स्थिति में पहुंच गये हैं महोदय जो नयी शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है । महोदय, मैं इसलिए सिर्फ यह कहना चाह रहा था कि हमलोग तो हमारी सरकार

शिक्षा को पहली अहमियत देकर अपने सारे बच्चों को शिक्षित करके पूरे प्रदेश और देश स्तर की स्पर्द्धा में हम अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं । इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना काम कर रहे हैं । महोदय, आज एक सुखद संयोग भी है कि आज 3 मार्च का दिन है, 3 मार्च की अहमियत एक यह भी है कि 3 मार्च 1939 को गांधीजी ने गुजरात में जो उस समय की देशी रियासतें थीं वह अंग्रेजी हुकूमत से मिलकर आम जनता पर काफी अत्याचार और तानाशाही रवैया अपनाए हुए थी उसके खिलाफ गांधी जी ने तीन मार्च 1939 को भूख हड़ताल की थी और महोदय तीन दिन की ही भूख हड़ताल में उस देशी रियासत के महाराजा और ब्रिटिश हुकूमत जो उनका साथ दे रही थी तो उनको झुकना पड़ा था तो आज का दिन तो सीधे गांधी जी से जुड़ा हुआ दिन है और महोदय आज हम जब गांधी जी को याद करते हैं तीन मार्च को तो हमें इस बात की भी हमें इस बात का भी अहसास हो रहा है कि जो जितने भी आधुनिक विचारक हैं, आज दुनिया के जितने भी आधुनिक विचारक, चिंतक जितने भी हुए हैं शिक्षा के महत्व को या शिक्षा को जितने व्यावहारिक रूप से महात्मा गांधी ने परिभाषित किया है महोदय उतनी व्यावहारिक परिभाषा शायद ही किसी ने शिक्षा की दी है क्योंकि गांधीजी शिक्षा और साक्षरता में फर्क मानते थे । उनके हिसाब से साक्षरता शिक्षा नहीं होती है, साक्षरता में सिर्फ अक्षर ज्ञान होता है लेकिन शिक्षा को उन्होंने एक बड़े पैमाने पर परिभाषित किया था और उनका कहना था कि शिक्षा का लक्ष्य होता है किसी भी व्यक्ति या छात्र के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र में जो उसकी अंदर की क्षमता है उसके सर्वोत्तम विकास के लिये जो वातावरण या ऐसी चीज दी जाती है वही शिक्षा हो सकती है ।

टर्न-29/सत्येन्द्र/03-03-21

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री:(क्रमशः) इसलिए आज जब हम गांधी जी को याद करते हैं तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और महोदय शिक्षा के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी और कितना फर्क करते थे शिक्षा और साक्षरता में और बिना नैतिक शिक्षा के शिक्षा का क्या हश्र होता है, गांधी जी के विचार इन चार पांच शब्दों में महोदय इस विधान-सभा के दीवारों पर अंकित है और हम धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने गांधी जी के सात सामाजिक पाप जो हैं महोदय, उसको इन्होंने विधान-सभा के अंदर लिखवाया है। विधान-सभा ही नहीं, चारों तरफ सभी सरकारी संस्थानों और सभी सरकारी इमारतों पर इस बात का जिक्र है और यह बात लिखा गया है। उसमें महोदय, देखिये सात सामाजिक पाप जो हैं, उसके ठीक बीच में, मध्य में चरित्र के बिना ज्ञान है, मतलब अगर आप ज्ञान अर्जित करते हैं अगर आप विद्या अर्जित करते हैं और वह बिना चरित्र के है तो समझिये ज्ञान के

मिसियूज होने या गलत दिशा में बहकने की संभावना बनी रहती है इसीलिए गांधी ने कहा था कि शिक्षा को हम सिर्फ साक्षरता, अक्षर ज्ञान या दूसरे चीजों तक सीमित नहीं कर सकते हैं । जबतक हम नैतिक रूप से भी आगे नहीं बढ़ेंगे तबतक शिक्षा को सही दिशा में सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और जब गांधी जी की बात महोदय हमें स्मरण करनी है तो गांधी जी की वह उक्ति भी हमें याद हो जाती है कि गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही देनी चाहिए, मातृभाषा की जगह दूसरी कोई भाषा नहीं ले सकती है और महोदय संयोग से कल ही, आज 3 मार्च है कल 4 मार्च को जो महान लेखक और बिहार के महान सपूत श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उनका जन्म दिवस है और ये कोई सामान्य जन्म दिवस नहीं है उनका शताब्दी जन्म दिवस है, शताब्दी जयंती है 4 मार्च को और महोदय उनकी जो कालजयी रचना है, आज 3 मार्च को हमलोग बात कर रहे हैं, 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु जी का शताब्दी जयंती है और फनीश्वर नाथ रेणु जी की जितनी भी कालजयी रचना है महोदय जो मातृभाषा है या आंचलिक भाषाओं के विकास या उसकी भाषा, उसके शब्दाबली, उसके मुहावरे ,उसकी लोकोक्ति इन सब को शामिल करते हुए उनकी जो रचनाएं है वह आज भी सब लोगों को प्रभावित करती है । महोदय इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने फैसला लिया है  गांधी जी को याद करने का और फनीश्वर नाथ रेणु जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये फैसला है कि महोदय हमलोग, यह सरकार आने वाले समय में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जिसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वह हमलोग जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, चाहे जो भी है प्रारंभिक शिक्षा हमलोग उसकी भाषा जो स्थानीय भाषा है, हम उसके माध्यम से करायेंगे। यह सरकार ने फैसला लिया है और हम गांधी जी से लेकर उनको इसी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं । सब लोग समझते हैं और बच्चों में जो उनमें कंस्च्युलाईजेशन का जो फर्क जो उनके मातृभाषा में उनको समझाया जायेगा वह दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते हैं इसलिए उनको सहज रूप से सभी चीज का ज्ञान उनके अंदर स्थापित करने के लिए सरकार ने गांधी जी के आदर्शों को और रेणु जी की जो दिशा थी लिखने पढ़ने की, उसको सम्मानित प्रतिष्ठित करने के लिए हमलोग अब प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्थानीय भाषा है, मैथिली है, भोजपुरी है या मगही है, उसी भाषा को हमलोग महोदय अपनायेंगे। महोदय, हम अब शिक्षा विभाग की तरफ से  महोदय, अभी हमलोग पिछले लगभग साल भर से कोरोना बीमारी से हम सब लोग जूझते रहे हैं।

श्री महबूब आलमः महोदय, उर्दू भाषा भी है।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्रीः महोदय, महबूब आलम जी पता नहीं किस मानसिकता से उर्दू को इतना पीछे बैठा रहे हैं । अरे, उर्दू तो कहां से कहां पहुंच चूकी है ,उर्दू तो द्वितीय राजभाषा है आपके जेहन में नहीं है क्या ? महोदय, हमको लगता है कि महबूब जी को उर्दू से कुछ प्रेम है और ये उसको द्वितीय राजभाषा से उतारकर क्षेत्रीय आंचलिक भाषा में पहुंचा देना चाहते हैं । अरे, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? उर्दू से आपको क्या खीस और नफरत है। महोदय, पूरा सदन और हमारे सभी माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि इस कोरोना के दौर में पिछले एक साल से हमें मजबूरन सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद करना पड़ा था और अब धीरे धीरे जब परिस्थितियां सामान्य हो रही है तो हमने क्रमवार तरीके से जैसे हमने 4 जनवरी से जो हमारे माध्यमिक विद्यालय थे और उच्च माध्यमिक विद्यालय थे, हायर स्टडीज के जो केन्द्र थे, यूनिवर्सिटीज थे हमने उनको खोला फिर 8 फरवरी से जो हमारे मध्य विद्यालय थे हमने उसको प्रारंभ किया है । अभी महोदय परसों ही की बात है, परसों 1 मार्च से हमने प्राथमिक विद्यालयों को सरकार ने खोलने का निर्णय ले लिया है हालांकि उन सब में यह सरकार ने हिदायत दे रखी है कि ये सभी जो कोरोना के प्रोटोकोल है जो करोना में भारत सरकार द्वारा या कोरोना से बचने के लिए, चाहे छात्रों को बचाने के लिए जो भी उसकी हिदायतें हैं, वह सब पालन करते हुए हमारे विद्यालय खुलेंगे और वे चलेंगे इसलिए महोदय अब साल भर बीत चुका है और अब अधिक दिनों तक विद्यालय बंद रहे, ये लगभग किसी को नहीं, अभिभावकों के भी तरफ से और हम समझते हैं कि सभी माननीय सदस्यों से भी जो अनौपचारिक बातचीत में जो बातें आ रही थी उसमें सबों की इच्छा थी कि अब विद्यालयों को खोलकर स्थिति को सामान्य बनाने की तरफ आगे बढ़ाया जाय। इसी तरीके से अब जब हम विद्यालय खोल रहे हैं और महोदय इस बार के हमारे बजट में भी आपने देखा होगा कि हमने अपना लक्ष्य जो सुविधाएं हम दे रहे हैं महोदय, वह पिछले 15 साल से लगातार तीसरी सरकार में अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें बतायी जा चुकी हैं, हम उसको फिर से दोहराना, गिनवाना कि हमने कितने बच्चे को वजीफा दिया, कितना पहला क्लास में पोशाक में दिया, यह सब लोग जानते हैं और सब लोग सुनते हैं और अब यह जानने सुनने की बात नहीं है। हर सदस्य अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं से रू ब रू होकर उन चीजों की पुष्टि कर सकते हैं। अब हमलोग महोदय अपने सामने, सरकार के सामने लक्ष्य, लर्निंग आउटपुट जो है इसमें क्या हो रहा है, हमलोग सभी सुविधा दे रहे हैं, एक चीज जिस पर सदन भी सहमत होगा और हमारे माननीय सदस्य सहमत होंगे कि अब यह समय आ गया है, हम मानते हैं अब यह समय आ गया है कि अब हमें लर्निंग आउटकम पर भी ध्यान देना है। बच्चों में पढ़ने की स्थिति तो हमने पूर्णरूप से बना दी है और

महोदय, यह सब के लिए, सभी माननीय सदस्यों के लिए प्रसन्नता की बात होगी और ये बिहार और सदन के लिए गौरव की बात होगी ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, 40 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, इस पर भी मंत्री जी बतायें।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: शायद ललित जी, आंकड़ें कहीं से पढ़ लेते हैं और उसके आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ते हैं। ये महोदय ललित जी भूल गये (क्रमश:)

टर्न-30/मधुप/03.03.2021

..क्रमश:..

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : ललित जी, आप भूल गये, यह तो प्रश्न के रूप में आया था, अभी कल-परसों की बात है । एक-दो साल का नहीं था, चार-पाँच साल के अंदर जो बच्चों का नामांकन हुआ था, उसके बारे में हमने विस्तार से बताया था कि नामांकन में कमी के क्या कारण हो सकते हैं, उसके संबंध में हमने इतने कारण गिनाये थे और उसके निराकरण के लिए, उसके निवारण के लिए जो सरकार की तरफ से प्रयास किये जा रहे हैं, उन्हीं सबको न हम बिन्दुवार गिना रहे थे जिसमें आप उठकर कह रहे थे कि इतना लम्बा जवाब क्यों दे रहे हैं । जिसपर हम आपको कहे थे कि सरकार जितना, हम आपको बताये थे.. (व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि प्राइवेट विद्यालयों में जो छात्र पढ़ते हैं, कोरोना-काल में विद्यालय खुला नहीं लेकिन उसका फीस भी वसूला जा रहा है । सरकार इस दिशा में कौन-सी कार्रवाई कर रही है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी मैं कह रहा था कि अब जो विद्यालय खुले हैं और अब जो हम शिक्षा में सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें हमारा मुख्य बिन्दु है लर्निंग-आउटकम पर कि इतनी सारी व्यवस्था हमलोग कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं और उस हिसाब से हमारा लर्निंग-आउटकम क्या हो रहा है ? हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ? हम उसका भी सत्यापन करना चाहते हैं.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो प्रश्न पूर्व में आ चुके हैं उसपर जवाब दिया जा चुका है उसको दोहराना इस समय उचित नहीं है । (व्यवधान) आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी । समय कम है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जैसा कि हमने कहा, अब हम वास्तविक शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और यह सरकार मानती है कि शिक्षा व्यवस्था के केन्द्र में शिक्षक होते हैं ।

सरकार की तरफ से शिक्षकों को भी हम कहना चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को देखेगी लेकिन हमारे शिक्षक भी शिक्षा की समस्या को देखें । सरकार उनकी सभी समस्याओं को दूर करेगी लेकिन बिहार की जनता को भी अहसास होना चाहिए कि हमारे शिक्षक अपना शत-प्रतिशत शिक्षण कार्य में दे रहे हैं । महोदय, सरकार का मानना है कि अगर हमारे शिक्षक अपना शत-प्रतिशत शिक्षण कार्य में देंगे... (व्यवधान) इसलिए हम शिक्षकों के भी निवेदन करना चाहते हैं और हम अपने तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं कि वे अनावश्यक शिक्षकों को परेशान नहीं करें । शिक्षकों का जो ड्यू है, उनका जो बाजिव हक है, उसके लिए उनको परेशान नहीं किया जाय लेकिन हमारे शिक्षक जो आज माहौल है, जिसके कारण हमारे कतिपय सदस्यों की उंगलियाँ हमारे तरफ उठ जाती हैं उस समस्या का वे समाधान कर दें जिससे हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी संतुष्ट हो जायं । हम अपने शिक्षकों से भी अपील करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोगों को अवसर मिला है । बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हमने बालिका शिक्षा या महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में जो हमने सफलता प्राप्त की है, वह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मंत्री जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह समय भाषण का ही है । केवल यह भाषण का समय है । आप बैठिए, आपको बैठना है ।

अध्यक्ष : शिक्षा पर गम्भीर हैं तो सुनिये, शिक्षा पर गम्भीर हैं तो धैर्य से पूरी बात को पहले सुनिये।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे.... (व्यवधान) उर्दू पर बोलें या उर्दू में बोलें ? जो कहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ईमान जी, बैठ जाइये । अब यह उचित नहीं है, आपको अवसर मिला था, बैठिए अभी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि जो महिला शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में हमने सरकार की उपलब्धियों की जो चर्चा की है, हमने जो यह पुस्तिका आपको दी है, उसके कवर पृष्ठ पर और बैक पृष्ठ पर, यह जो दो तस्वीर छपी है, उसको जरूर गौर से देखिये कि पहले पृष्ठ पर जो तस्वीर छपी है, आपके पास भी है, अध्यक्ष महोदय, इसको उलट कर देख लीजिये कि जो पहले पृष्ठ पर तस्वीर है...(व्यवधान) आखिर हम बिहारवासी हैं, जब बिहार की बच्चियाँ अभी

कुछ दिन पहले तक, कुछ वर्ष पहले तक घर में ऐसी स्थिति होती थी कि उसके सारे अरमान, उसकी सारी प्रतिभा....

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उसकी सारी योग्यता सामाजिक बंधनों में वहीं दबकर घुटकर रह जाती थी, आज उसको आगे बढ़ने का मौका मिला है इसलिए महोदय, हमने फ्रंट पेज पर डाला है...

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लें ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपकी बात पर तो अभी हम आ ही रहे थे पेपर लीक वाला पर ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : उस समस्या का तो कोई हल होगा ही नहीं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसलिए अभी तो बहुत सारी बातें हैं, जो बची हुई चीज हैं, वह हम रख देते हैं.... (व्यवधान) महोदय, हम अपना लिखित भाषण सदन पटल पर रखते हैं, उसको मेरे वक्तव्य का हिस्सा बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : रख दीजिए ।

(माननीय मंत्री का लिखित भाषण -परिशिष्ट द्रष्टव्य)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसके साथ-ही, हम पूरे सदन से दरख्वास्त करते हैं कि हमने जो माँग रखी है उसको सर्वसम्मति से पास करिये । महोदय, विजय शंकर दूबे जी इस सदन के पुराने सदस्य हैं, हम समझते हैं कि हमलोग कुछ ही लोग हैं जो उस जमाने के 1980-85 बैच के यहाँ इस सदन में सदस्य हैं, आप उन सबका ख्याल रखते हुए अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लीजिए । हम आपसे आग्रह करते हैं ।

टर्न-31/आजाद/03.03.2021

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी : अध्यक्ष महोदय, एक बात रखना चाहते हैं । विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव लाया है .....

अध्यक्ष : प्रश्न यह है...... समय हो रहा है, अब समय 5.00 बजे फिक्स है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : अब थोड़ा सा सुन लिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : 5.00 बजे निश्चित है, निर्धारित है नियम में ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, आज का दिन महत्वपूर्ण है गाँधी जी की...

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

‘‘इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटायी जाय । ’’

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ....

अध्यक्ष : समय यह तय है, नेता प्रतिपक्ष, आप जानते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया ।

अध्यक्ष : यह समय किसी को नहीं मिल सकता है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 380,35,92,80,000/- (तीन सौ अस्सी अरब पैंतीस करोड़ बानवे लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । आज दिनांक 03 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-32 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 04 मार्च, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

परिशिष्ट

**मान्यवर अध्यक्ष महोदय,**

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज 03 मार्च, 2021 को मैं सदन में शिक्षा से संबंधित विषयों पर एवं शिक्षा पर प्रस्तावित व्यय माँग संख्या–21 पर अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। 03 मार्च का दिन विशेष महत्व का दिन है। 3 मार्च, 1939 को गुजरात में महात्मा गांधी ने तानाशाही के विरोध में भूख हड़ताल की थी। गांधीजी का सपना ऐसे आजाद भारत का था जहाँ सभी सुशिक्षित हों, स्वावलंबी हों और अधिकार के साथ–साथ कर्त्तव्य को महत्त्व देते हों। महात्मा गांधी की याद में हमलोगों ने चम्पारण सत्याग्रह का 100वां वर्ष मनाया, गांधी के विचारों को गाँव–गाँव, घर–घर पहुँचाने की योजना बनाई। हमारे विद्यालयों में प्रतिदिन बच्चों के द्वारा गांधी कथा का वाचन किया जाता है। गांधीजी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ।

1. प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता? जिस समय पृथ्वी के विभिन्न भू–भाग में मानवजाति शिक्षा और सभ्यता की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में थी, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्ज्वलित था और दूर–दूर के देशों से छात्र और शिक्षक यहाँ ज्ञानार्जन हेतु आते थे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना गौरव की बात थी। ह्वेनसांग के एकाउन्ट के अनुसार जब वह नालंदा आये तो वहाँ 10 हजार छात्र, 15 सौ शिक्षक विश्वविद्यालय में थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, मंगोलिया से लोग अध्ययन के लिए यहाँ आते थे और दर्शन एवं बौद्ध साहित्य साथ में ले जाते थे। उस समय एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय नालंदा में ही था। बारहवीं शताब्दी तक इसका यह गौरव बरकरार रहा। विक्रमशिला भी उसी कालखंड में भागलपुर के पास उच्च शिक्षा के अध्ययन केन्द्र के रूप में विख्यात था। कालक्रम में हम शिक्षा एवं साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ गए।

2. 2005 में जब हमारी सरकार आयी तो हमने एक स्पष्ट सोच के साथ शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। बिहार के प्राचीन शैक्षणिक गौरव को वापस लाने के लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कार्य लगातार किए गए। आजादी के बाद विकास के अवसरों से वंचित, आधुनिक बिहार ने अपने मानव संसाधन को कौशल सम्पन्न, योग्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा को आधार बनाया। हर 1 कि0मी0 में प्राथमिक विद्यालय, 3 कि0मी0 के अन्दर मध्य विद्यालय एवं हर पंचायत में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कर ली गई है। पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं शत प्रतिशत बच्चों का स्कूल में नामांकन हो चुका है और हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हो चुकी है। उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति से विकास के नए आयाम खुले हैं।

3. राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे–बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। बजट के लगभग 20 % या उससे अधिक शिक्षा पर व्यय से बिहार को नई पहचान मिली है। लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हमें लगातार काम करने की जरूरत है।

4. बिहार के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक हमारा पुराना गौरव लौटे, हमारा यही लक्ष्य है। इसके लिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था एवं पढ़ाई को बेहतर करना है। शिक्षक अपने ज्ञान का शत–प्रतिशत बच्चों को दें, सीखने सिखाने का माहौल बने इस पर हम काम कर रहे हैं। हमें कोरोना काल में बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई भी करनी है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में आवश्यक रणनीति अपनाकर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना है।

5. 6–14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को उम्र–सापेक्ष दक्षता देकर शिक्षा की मुख्यधारा में लाने में राज्य ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या 1 % से भी कम अर्थात 1.44 लाख ही रह गई थी, जिसमें से 71,862 बच्चों को सीधा नामांकन कराकर एवं 62,991 बच्चों को गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से आच्छादित किया गया है। शैक्षिक सत्र 2020–21 में पाठ्यपुस्तक क्रय हेतु Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से कक्षा 1 से 8 में नामांकित छात्र–छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। समाज के कमजोर वर्ग की छीजित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कक्षा– 6 से 8 तक के लिए राज्य में 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के०जी०बी०भी०) संचालित हैं तथा इनमें कुल 50,385 बालिकाएँ नामांकित होकर पढ़ रही हैं।

6. मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत वर्ग 1 से 8 तक के 1,19,22,938 (एक करोड़, उन्नीस लाख, बाईस हजार, नौ सौ अड़तीस) छात्र/छात्राओं को कोरोना काल में सूखा राशन (चावल) वितरित किया गया एवं परिवर्तन मूल्य की राशि DBT के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी। राज्य के 15,977 विद्यालयों में पोषण वाटिका का भी निर्माण कराया गया है।

7. राज्य में अवस्थित 8,386 पंचायतों में 5082 में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। शेष 3304 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना उक्त पंचायतों में चिह्नित मध्य विद्यालय में करते हुए वर्ग–9 की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है। उक्त पंचायत में भूमि की उपलब्धता के मद्देनजर नए विद्यालय भवन का निर्माण क्रमिक रूप से किया जाएगा। इस प्रकार अब बिहार के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

8. सभी 38 जिले के एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को चिह्नित कर उसे अनुकरणीय मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही माध्यमिक–उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र, छात्राओं

के कैरियर कांउसलिंग के लिए " **बिहार कैरियर पोर्टल** " भी विकसित किया गया है।

9. "**उन्नयन बिहार**" कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यमिक कक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) का उपयोग कर स्मार्ट क्लास के द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है, ताकि शैक्षणिक वातावरण कायम हो एवं शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो सके।

10. राज्य सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के निमित्त मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमिडिएट) प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत इन्टरमिडिएट एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में क्रमशः प्रति छात्रा ₹ 10,000/–(दस हजार रूपये) एवं ₹ 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) उपलब्ध कराया जाता है।

11. वित्तीय वर्ष 2021–22 से सरकार ने उक्त दोनों योजनाओं को सात निश्चय–2 में शामिल करते हुए मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमिडिएट) प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना की प्रोत्साहन राशि को क्रमशः ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) एवं ₹ 50,000/–(पचास हजार रूपये) करने का निर्णय लिया है।

12. बालिका शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाये गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना, पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (सैनिटरी नैपकिन), साईकिल योजना एवं छात्रवृत्ति योजना पूर्व से संचालित है। फलतः बिहार में बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2020 की मैट्रिक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में बालिकाओं की भागीदारी

51 % हो गई है। आज माध्यमिक स्तर तक बालक एवं बालिका शिक्षा में अन्तर (Gap) शून्य है।

13. वर्ष 2020 की माध्यमिक परीक्षा में 7,29,212 (सात लाख, उनतीस हजार, दो सौ बारह) छात्र एवं 7,64,859 (सात लाख, चौंसठ हजार, आठ सौ उनसठ) छात्राओं ने भाग लिया। स्पष्टतः छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मैट्रिक में जहाँ 92 % छात्र एवं 88 % छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की है। वहीं इन्टरमीडिएट में 85 % छात्र तथा 88 % छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की है। इन योजनाओं का प्रतिफल है कि बिहार में बालिका शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ, बाल विवाह पर अंकुश लगे, कुल प्रजनन दर (TFR) में कमी आयी है तथा शिक्षा में लिंग भेद समाप्ति पर है।

14. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज पूरे देश में उत्कृष्टता के नये आयामों को गढ़ते हुए नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वर्ष 2020 में समिति द्वारा लगातार दूसरे वर्ष देश में सबसे पहले मैट्रिक एवं इंटर का परीक्षाफल जारी किया गया। इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल कम समय में दिनांक 24 मार्च, 2020 को जारी किया गया, जो देश के इतिहास में एक रिकार्ड है। इसके पश्चात् कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के बावजूद सभी नियमों का पालन करते हुए देश में सबसे पहले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 26 मई, 2020 को जारी किया गया।

April में result

15. उच्च शिक्षा में GER की वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। 7 निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवार के बच्चे भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना** के अन्तर्गत अभी तक कुल 2,22,500 आवेदकों के लिए ₹ 3,290.43 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें 1,10,457 छात्र–छात्राओं को ₹ 1,538.86 करोड़ का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

16. राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 2,776 व्याख्याताओं की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से की जा चुकी है। शीघ्र नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठित होकर कार्यरत है। नियुक्ति की अनुशंसा देने हेतु इसे 4,638 रिक्ति उपलब्ध करायी गयी है।

17. राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त 07 निजी विश्वविद्यालयों, यथा– अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, मधुबनी, के0 के0 विश्वविद्यालय, नालन्दा, डॉ सी0वी0 रमण विश्वविद्यालय, वैशाली, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार (सासाराम), अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार एवं माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज की स्थापना की गई है।

18. तकनीकी शिक्षा के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत नैनो सायंस एवं नैनो टेक्नॉलौजी के अध्ययन की व्यवस्था है तथा "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies", "Centre for Geographical Studies", "Centre for Stem Cell Technology", "Centre for Astronomy" and एवं "Centre of Philosophy" के रूप में 7 स्वायत्तशासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार बिहार के शैक्षणिक जगत में ठोस और परिणामकारी कार्य करने में हम अग्रसर हैं।

**19.** **Covid-19** के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किये गये ई–कन्टेन्ट के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन, बिहार (मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय) पर प्रतिदिन 5 स्लॉट (एक–एक घंटा का एक स्लॉट) में डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गयी। राज्य में ऑनलाईन पठन–पाठन की व्यवस्था 20 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ की गयी है। कक्षा 6 से 12

के लिए विकसित सभी ई–कन्टेन्ट परिषद् के यू–ट्यूब चैनल एवं "मेरा मोबाईल–मेरा विद्यालय" एप्प पर भी उपलब्ध कराया गया।

20. वर्ष 2020 कोविड–19 के कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए बड़ा ही संकट का वर्ष रहा है। 14 मार्च, 2020 से सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गये और पूरे वर्ष बंद रहे। हमने 4 जनवरी, 2021 से उच्च संस्थानों एवं माध्यमिक विद्यालयों को एवं 8 फरवरी, 2021 से मध्य विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) को खोलकर अध्ययन–अध्यापन को प्रारंभ किया है। 1 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) खोले जा रहे हैं। यद्यपि दूरदर्शन–बिहार, मोबाईल एप्प, इंन्टरनेट आदि के माध्यम से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर शिक्षा विभाग ने बच्चों के बीच पढ़ाने का काम लगातार जारी रखा। बड़ी संख्या में बच्चे लाभान्वित भी हुए, परन्तु इन माध्यमों की पहुँच सभी बच्चों के पास नहीं है। खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चों के सीखने के कार्य कम हुए। पिछले वर्ष की कमी की भरपाई के लिए नये सत्र में नामांकन अभियान चलाया जा रहा है, ब्रिज कोर्स का आयोजन हो रहा है और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ठोस व्यवस्था की जा रही है। हमें उम्मीद है कि कोरोना से उपजी स्थितियों ने हमें जितना पीछे ढ़केला उसे हम चुनौती के रूप में लेकर बच्चों में सीखने के स्तर को उँचा उठाने का कार्य करेंगे।

**माँग विवरण**

(i) शिक्षा विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 के व्यय वहन हेतु कुल ₹ 380,35,92,80,000/–(तीन सौ अस्सी अरब, पैंतीस करोड़, बानबे लाख, अस्सी हजार रूपये) का उपबंध माँग संख्या– 21 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम शामिल हैं।

(ii) इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिये ₹ 160,96,89,80,000/– (एक सौ साठ अरब, छियानवे करोड़, नवासी लाख, अस्सी हजार रुपये) प्रस्तावित है।

(iii) वार्षिक स्कीम के लिए कुल ₹ 219,39,03,00,000/–(दो सौ उन्नीस अरब, उनचालीस करोड़, तीन लाख रुपये) का प्रस्ताव है जिसमें केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹ 103,29,61,00,000/– (एक सौ तीन अरब, उनतीस करोड़, इकसठ लाख रुपये), राज्यांश की राशि ₹ 76,00,10,00,000/–(छिहत्तर अरब, दस लाख रुपये) एवं राज्य स्कीम के लिए ₹ 40,09,32,00,000/–(चालीस अरब, नौ करोड़, बत्तीस लाख रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि शिक्षा से हम सबों का सरोकार है। बिहार की शिक्षा की बेहतरी के लिए सबों का साथ मिले ऐसी मेरी आकांक्षा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि शिक्षा की विकास की यात्रा को हम आगे बढ़ायेंगे। मेरा आप सबों से अनुरोध है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आप सभी सहयोग दें। शिक्षा के मामले में हम दलगत राजनीति से उपर उठ कर सोचें। सुधार के उद्देश्य से कमियों को उजागर करना चाहिए। सिर्फ आलोचना के लिए, विरोध के लिए बोलने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। आप समस्या के समाधान के लिए हमें सुझाव दें। हम सब मिलकर समाधान का हिस्सा बनें। तभी हमारी शिक्षा आगे बढ़ेगी और बिहार आगे बढ़ेगा।

कोरोना संकट के कारण शिक्षा में आयी रूकावट और गुणवत्ता की कमी से बिहार ही नहीं पूरा देश जूझ रहा है। धीरे–धीरे हम विपत्ति से बाहर आ रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस वैश्विक विपत्ति के बाद पटरी पर लौट रही है। सभी विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, पढ़ाई आरंभ हो चुकी है। इन्टर और मैट्रिक की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। समय पर परीक्षा परिणाम देने के लिए हम कटिवद्ध हैं। समस्याओं को हम चुनौती के रूप में लेंगे और हमारी सरकार के लगातार प्रयास से बिहार में शिक्षा की राह प्रशस्त होगी। अन्त में आप सबों से आग्रह है कि शिक्षा विभाग की मांग स्वीकृत करने का कष्ट करें।